PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अक्टूबर-2019 | अंक-4

वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 और भारत

एक विश्लेषण

- भारत में एचआईवी का संकट और इसका समाधान
- भारत में खाद्य अपमिश्रण एवं संदूषण
- तुर्की-सीरिया संकट: एक अवलोकन
- भारतीय डाक सेवा: अब तक की यात्रा
- कच्चे तेल में उछाल और भारत पर उसका प्रभाव
- 'मेक इन इंडिया' : एक मूल्यांकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

May the Warmth and Splendor, that are a Part of this Auspicious Occasion, fill Your Life with Happiness and Bright Cheer.

May Light Triumph over Darkness.

May Knowledge Triumph over Ignorance.

May Spirit of Light Illuminate the World.

May You Reach Your DHYEYA with Grand Celebration.

Wishing You Success, Knowledge and Prosperity.

Content Team
DHYEYA IAS

This Diwali we are waiting to hear from you!
Send us your constructive & valuable suggestions, comments, views and feedback for guiding us towards continuous improvement & enhancement of 'Perfect 7' on

9990772422

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अक्टूबर-2019 | अंक-4

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 और भारत: एक विश्लेषण
- भारत में एचआईवी का संकट और इसका समाधान
- भारत में खाद्य अपमिश्रण एवं संदूषण
- तुर्की-सीरिया संकट: एक अवलोकन
- भारतीय डाक सेवा: अब तक की यात्रा
- कच्चे तेल में उछाल और भारत पर उसका प्रभाव
- 'मेक इन इंडिया' : एक मूल्यांकन

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 और भारतः एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति अनुसंधान संस्था (IFPRI) ने 14वां 'वैश्विक भूख सूचकांक' जारी किया है। भारत 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर है।

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान एवं दो अन्य गैर लाभकारी संस्थान जैसे जर्मनी का वेल्टहंगर हाइफ (Welthunger Hilfe) और आइरिश संगठन कनसर्न वर्डवाइड इस 'वैश्विक भूख सूचकांक' के प्रकाशन में सहयोग देते हैं। इस संस्था के द्वारा भुखमरी की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को पर्याप्त कैलोरी न मिलना ही भुखमरी कहलाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कृषि संगठन भोजन की कमी या अल्पपोषण को भुखमरी के रूप में परिभाषित करता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिंग व आयु या अन्य बीमारियों के कारण आहार में भिन्न-भिन्न ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए विश्व के कई संस्थान भुखमरी व कुपोषण दोनों को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा वैश्विक भुखमरी की स्थिति को मापने के लिये चार आधार संकेतों का उपयोग किया जाता है-

- **कुपोषणः** जनसंख्या का वह भाग जिसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्त्व नहीं मिल पा रहा है।
- **बाल निर्बलताः** 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन उसके कद के अनुपात में कम होना।
- **बच्चों में बाधित विकासः** 0 से 5 वर्ष के बच्चों का उनकी आयु के अनुपात में कद में सही वृद्धि न होना।
- **बाल मृत्युः** पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अल्पपोषण या अस्वास्थ्यकारी पर्यावरण के कारण मृत्यु का अनुपात।

वैश्विक भूख सूचकांक में इन संकेतों के आधार पर प्रत्येक देश को 0 से 100 तक के बीच के अंक प्रदान किये जाते हैं। 0 अंक से सबसे अच्छा एवं 100 तक के प्राप्त अंक को सबसे खराब स्थिति माना जाता है। 1 से 10 तक का अंक निम्न श्रेणी में, 10-20 तक का अंक मध्यम श्रेणी, 20-35 तक के बीच का अंक गंभीर, 35-50 तक के बीच का अंक भयावह, व 50 से अधिक अंक को अति भयावह श्रेणी में रखा जाता है।

'वैश्विक भूख सूचकांक' रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- वैश्विक स्तर पर भुखमरी सूचकांक में प्रथम तीन स्थान प्राप्तकर्त्ता देश बेलारुस, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, हैं।
- इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति में भी सुधार हुआ है, जिनमें नेपाल-73वें, श्रीलंका-66वां, बांग्लादेश-88वां, म्यांमार-69वां, चीन-25वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं पाकिस्तान- 94वें व अफगानिस्तान- 108वें स्थान पर है। एशिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत कई छोटे देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपीन्स आदि से भी पीछे है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का बाल निर्बलता अनुपात 20.8% है जो कि किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है।
- भारत में बाल वृद्धि दर 37.9 प्रतिशत है जो कि लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी गंभीर समस्या है।
- भारत में 6 से 23 महीनों के सभी बच्चों के बीच केवल 9.6 प्रतिशत बच्चों को न्यूनतम आवश्यक आहार दिया जाता है।
- इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के 39 प्रतिशत घरों में स्वच्छता नहीं है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर बच्चों की वृद्धि और विकास पर पड़ता है। भारत में 2014 में 'स्वच्छ भारत' अभियान के आरंभ होने के बावजूद अभी भी लोग खुले में शौच को जा रहे हैं।
- इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत ने स्वच्छ जल स्रोत की पहुँच को 90 प्रतिशत तक सुधारा है। बावजूद इसके अभी भी वह गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी गणतंत्र देश अति भयावह स्थिति में हैं तथा चार अन्य देश चाड, मेडागास्कर, यमन और जाम्बिया भयावह स्थिति में हैं, जबकि 43 देश भुखमरी की गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं।
- इस रिपोर्ट में सर्वाधिक खराब स्थिति में क्रमशः मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, यमन एवं चाड है।
- विश्व के कुछ देश जैसे हैती, जिम्बाब्वे और मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र देश में अल्पपोषण की दर सर्वाधिक ऊँची है, जो कि 49.3% से 59.6% के बीच है।
- बच्चों की निम्न वृद्धि दर के मामले में मेडागास्कर बुरुन्डी और यमन सर्वोच्च स्थान प्राप्तकर्त्ता हैं। यहाँ पर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आधे से अधिक बच्चों की बाधित वृद्धि दर सर्वाधिक है।
- बाल निर्बलता के मामले में क्रमशः यमन, जिबूती और भारत सर्वाधिक हैं जिन्हें इस मामले में 17.9 से 20.8 प्रतिशत के बीच का अंक प्राप्त है।
- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सर्वाधिक मृत्यु मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र देश में होती है।

वैश्विक स्थिति

- वैश्विक स्तर पर भुखमरी ग्रस्त लोगों की संख्या में पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो

कि 2015 में 785 मिलियन थी, 2018 में यह बढ़कर 822 मिलियन हो गई है।

सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य सूची में विश्व को 2030 तक शून्य भुखमरी तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 2025 तक कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने का भी लक्ष्य निर्धारित है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कृषि उत्पादन को दोगुना तक बढ़ाना; सीमान्त किसान की आय बढ़ाना; पर महिला, वंचित वर्ग, देशों के मूल निवासियों, किसान, पशुपालक और मछली पालन कर्त्ता को जरूरत के लिये भूमि, उपकरण, जानकारी, वित्तीय मदद, बाजार तक पहुँच आदि की सुविधा देना ताकि रोजगार बढ़ाया जा सके।

- 19 में से 1 व्यक्ति को प्रत्येक दिन भोजन उपलब्ध नहीं है। यू.एन. रिपोर्ट ने भुखमरी को मिटाने के लिये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के निर्धारित लक्ष्य, शून्य भुखमरी की ओर संकेत किया। यू.एन ने यह भी कहा कि मध्यम आय श्रेणी वाले देश में यह समस्या अधिक है।
- अफ्रीका महाद्वीप में भुखमरी 20% तक बढ़ी है, एशियन देशों में 11% जनसंख्या अल्पपोषित है तथा पश्चिमी एशिया 12% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। दक्षिणी एशियाई देश में कुपोषण बढ़ा है। यह वृद्धि दक्षिणी अमेरिका एवं कैरेबिया देशों में भी देखी गई है। भुखमरी के बढ़ने के पीछे आर्थिक कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
- 338 मिलियन स्कूली बच्चे अधिक वजन वाले हैं, 672 मिलियन युवा मोटापा का शिकार है। एशिया और अफ्रीकी देशों में 10में से 9 बच्चे अल्प विकास से प्रभावित हैं। विश्व स्तर पर वर्ष 2015 तक 7 में से एक बच्चा आवश्यकता से कम वजन के साथ जन्म ले रहा है।
- विश्व की 17.2 प्रतिशत जनसंख्या के पास न्यूनतम आहार एवं पर्याप्त पोषण युक्त भोजन नहीं पहुँच पा रहा है।
- बालमृत्यु दर की सबसे उच्च दर सोमालिया (13.3%), चाड (12.7%) मध्य अफ्रीकी गणराज्य (12.4%) है।

भारत की स्थिति

यदि भारत का तुलनात्मक अध्ययन करें तो वर्ष 2000 में 113 देशों की सूची में भारत 83वें स्थान पर था। 2019 में यह 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर है। यह भारत की निम्न सुधार दर को दर्शाता है। इस सूची में भारत ने जहाँ 2000 में 38.8 अंक प्राप्त किये। वहीं वर्ष 2005 में पुन: 38.8 अंक ही प्राप्त किए, फलत: यह देखा जा सकता है कि इन पाँच वर्षों में देश ने कोई सुधार नहीं किया है। वर्ष 2010 में भारत को इस सूची में 32.2 अंक प्राप्त हुए जो कि भारत की स्थिति में सुधार को दर्शाता है। लेकिन 2018 पर गौर करें तो भारत को 31.1 प्रतिशत अंक ही प्राप्त हुए। पिछले पाँच दशकों पर ध्यान दें तो वर्ष 2014 में भारत को 55वां स्थान प्राप्त था। यह भी अभी तक का सर्वाधिक उच्च स्थान है जिसे भारत ने प्राप्त किया है। इसके बाद 2015 में 80वां स्थान, 2016 में 97वां स्थान, 2017 में 100वां स्थान व 2018 में 103वां स्थान, भारत का इस सूची में था।

- 10 में से 4 बच्चे भारत में चिरकालिक (Chronic) भुखमरी से ग्रसित हैं। 195.9 मिलियन लोग प्रतिदिन भूखे रहते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल 75% ग्रामीण क्षेत्र को तथा 50% शहरी क्षेत्र को कवर कर रहा है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत में गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में, बाल निर्बलता अत्यधिक संख्या में देखने को मिलती है।
- यह विश्लेषण यह सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि जहाँ भारत एक तरफ वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति की दावेदारी करता है या फिर एशियाई देशों के नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है, तो क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति भारत अपनी घरेलू स्थिति को सुधारे बिना कर सकता है। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि भारत अपनी रैंकिंग में सुधार क्यों नहीं कर पा रहा है।

भारत रैंक में क्यों सुधार नहीं कर पा रहा है?

- वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार न होने का एक कारण जलवायु में लगातार परिवर्तन भी है। इसका जिक्र इस सूचकांक में भी किया गया है। चरम मौसम की स्थिति आने से बीमारी में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा पर संकट, हिंसक संघर्ष में वृद्धि देखी जा रही है। इन परिस्थितियों के लिये सर्वाधिक सुभेद्य वर्ग बच्चे ही हैं जिन पर तीव्रता से, अधिक घातक प्रभाव पड़ता है।
- यहां पर भुखमरी का कारण गरीबी भी है। देश की 21.9% जनसंख्या वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है जिनमें अधिकांशत: लोगों को एक वक्त का भोजन तक नहीं मिल पाता है।
- विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 की बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एम.एम.आर.पी) के आधार पर जिन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया वह बतलाता है कि खाद्य पदार्थ की कीमत में उतार चढ़ाव का कारण भौगोलिक असमानता एवं उनका पिछड़ापन है। अत: ऐसे क्षेत्र अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इन क्षेत्रों में गरीब आदिवासी लोगों का निवास है। इनकी अधिकांश जनसंख्या अल्पपोषण व भुखमरी का शिकार है। इन्हीं क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर भी अधिक देखी जाती है।
- भुखमरी और अल्पपोषण को बढ़ावा देने में कुछ कारण जैसे-अस्वच्छ जल की पहुँच, साफ-सफाई न होना, खाद्य तक लोगों की पहुँच न होना भी जिम्मेदार हैं, यद्यपि कुपोषण के लिये कुछ जनसांख्यिकी कारक जैसे लिंग, जाति आदि भी जिम्मेदार कारक हैं।
- भारत अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहा इसके लिये नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन एक बड़ी समस्या है, जिसका जिक्र एकीकृत बाल विकास सेवा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में किया गया है।
- कुपोषण को बढ़ाने के लिये कुछ बीमारियां भी जिम्मेदार हैं जिनमें तपेदिक, खसरा, दस्त आदि हैं क्योंकि यह कमजोरी के साथ-साथ चयापचय को भी प्रभावित करती हैं, जिससे बच्चे अन्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। विकासशील देशों में एच.आई.वी. संक्रमित बच्चे कुपोषण से ग्रसित होते हैं। यद्यपि इन बच्चों को पर्याप्त एंटी-रेट्रोवायरल दवाएँ भी दी जाती हैं तो भी पर्याप्त पोषणयुक्त भोजन न मिलने के कारण दवाओं का कुप्रभाव इन बच्चों पर पड़ता है, अंतत: बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
- भुखमरी या अल्पपोषण का एक कारण संघर्ष भी है। किसी भी कारण से आपसी संघर्ष से प्राय: लोगों को अपनी जमीन, व्यवसाय या नौकरी छोड़नी पड़ती है। यदि क्षेत्रीय विवाद उठता है तो आपूर्ति शृंखला बाधित होती है

जिस कारण लोगों तक राशन की पहुँच नहीं हो पाती। यह समस्या कई बार विकट रूप धारण कर लेती है।

- शरणार्थी संकट भी भुखमरी का कारण है। 68.5 मिलियन जनसंख्या प्रत्येक वर्ष अपने देश से निर्वासित हो रही है। वहीं 40.0% मिलियन आंतरिक स्थानांतरण का शिकार हो रही है और 25.4 मिलियन लोग शरणार्थी शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं, तो 3.1 मिलियन लोग अन्य जगह पर शरण लेना चाहते हैं।
- भुखमरी एवं कुपोषण बढ़ने का एक कारण महिलाओं का पर्याप्त शिक्षित न होना है। जानकारी के अभाव में वे अपने परिवार की देखरेख ठीक प्रकार से नहीं कर पाती हैं।
- भारत में भुखमरी का एक कारण क्रय शक्ति क्षमता में कमी है। भारत विश्व के उन कुछ देशों में से आता है जिसका उसके जनसंख्या के अनुपात में क्रय शक्ति क्षमता में काफी कमी है।
- भारत की खाद्य भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं है। देश में उत्पादित अनाज का लगभग 1/3 हिस्सा अच्छी भण्डारण सुविधा न होने के कारण नष्ट हो जाता है। वहीं फसल की कटाई के दौरान लगभग 14% हिस्से का नुकसान हो जाता है। जो कि खाद्य सुरक्षा के लिये एक प्रमुख समस्या हैं।
- मध्यम एवं निम्न श्रेणी के परिवारों की रोजमर्रा के जीवन में खराब आदत भी इस समस्या का एक कारण है क्योंकि इन घरों की महिलाएँ, बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुरूप भोजन नहीं लेते हैं।

चुनौतियाँ

- भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, पर्याप्त अन्न का उत्पादन करना, इसके साथ ही फल, मांस, मछली तथा अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाना है जो अपेक्षाकृत नहीं हो पा रहा है। भारत का वैश्विक स्तर पर फलों एवं बागवानी फसलों के निर्यात में आनुपातिक भागीदारी काफी कम है। यहाँ तक कि इन पोषण युक्त फसलों की पहुँच देश के आम लोगों तक भी नहीं हैं। इस प्रकार भारतीय कृषि को नया रूप देना एक बड़ी चुनौती है।
- लोगों में जागरूकता का अभाव है विशेष तौर पर महिलाओं में, जिसके कारण वे परिवार के लोगों में भोजन की आदतों व उनके भोजन करने के तरीके में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं।
- गोदामों में पड़े अनाजों की पर्याप्त मात्रा में भण्डारण क्षमता का अभाव है जिसके कारण, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने में कठिनाई आती है।
- भारत में फसलों के उत्पादन में धड़ल्ले से रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है जो एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- आज भी पर्याप्त संख्या में आम लोगों की पहुँच बाजार तक नहीं हो पायी है जिससे वे उन सभी पोषणयुक्त ब्रांडेड उत्पादों को प्राप्त कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- देश की परिवहन प्रणाली एवं आधारभूत संरचना का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया है जिससे खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ जाती है।
- क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्र की मिट्टी के अनुरूप फसल उत्पादन की ओर नहीं बढ़ा जा सका है।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

- सरकार द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक में भारतीय रैंक को सुधारने के लिये कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे मिड-डे मिल योजना, जिसके तहत प्रत्येक बच्चे को उसके विद्यालय में पर्याप्त पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को 1975 से चलाया जा रहा है। जिसमें बच्चों में पोषण, उसकी देखभाल, मृत्युदर को कम करना, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना तथा अन्य बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है। यह भारत का बच्चों के विकास को बनाये रखने के लिये सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- जननी सुरक्षा योजना जो न केवल गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव देने की सुविधा प्रदान करती है बल्कि इसके तहत निःशुल्क अस्पताल की सुविधा, न्यूनतम धन राशि एवं बच्चे के जन्म के बाद उसकी चिकित्सीय जाँच की सुविधा भी देती है ताकि महिला एवं बच्चे दोनों को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखा जा सके।
- देश में प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा देने के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पास किया गया जो कि प्रत्येक व्यक्ति के भोजन के अधिकार को सुरक्षित करता है।
- हाल ही में सरकार द्वारा आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये एफ.एस.एस.ए.आई के माध्यम से 'राइट ईट' (सही भोजन) अभियान चलाया गया। इतना ही नहीं बिगड़ते जलवायु एवं लोगों की आदतों में सुधार करने के लिये 'फिट इंडिया' अभियान भी चलाया जा रहा है। यह कुपोषण को दूर करने में काफी सहायक होगा।
- भारत को 2022 तक 'कुपोषण मुक्त' बनाने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन को वर्ष 2017 में नीति आयोग ने पोषण स्तर को बढ़ाने एवं भुखमरी को व्यापक स्तर पर समाप्त करने के लिये शुरू किया। इस मिशन के लिये सरकार ने 9046.17 करोड़ रुपये 2017-18 के लिये आवंटित किये थे। इस मिशन का केन्द्रीय विषय यह है कि अल्पविकास, अल्पपोषण, बच्चों में एनीमिया, महिलाओं एवं लड़कियों में कम वजन की समस्या को दूर किया जा सके। इस योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को आच्छादित किया जाएगा।

सुझाव

- सरकार को कुपोषण एवं भुखमरी समाप्त करने के लिये आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए।
- महिलाओं के लिये उन रणनीतियों को बनाया जाना चाहिए जो कि घरेलू एवं परम्परागत जानकारी के अनुरूप हो।
- वैश्विक स्तर पर एवं क्षेत्रीय स्तर पर किन्हीं भी कारणों से फैली असमानता को कम से कम करना चाहिए।
- लोगों के खाद्य सुरक्षा और उनके पोषण से बिना किसी समझौते के विकसित देशों को यूएन का एजेंडा 2030 एवं पेरिस समझौते का पालन करना चाहिए।

आगे की राह

सरकार द्वारा सुभेद्य लोगों के लिये लगातार कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद भारत पिछले पाँच दशकों में लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर भारत जो कि वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। यू.एन की रिपोर्ट के मुताबिक 0-14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की कुल संख्या 26.16% है। भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 0-5 वर्ष तक की संख्या, कुल जनसंख्या का 10.7% है। अतएव भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार के साथ ही साथ आपूर्ति शृंखला को सरलीकृत एवं भ्रष्टाचार मुक्त किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अभिभावकों को तथा अन्य सीमान्त लोगों को कुपोषण, भुखमरी के प्रति जागरूक करने की जरूरत है क्योंकि किसी भी देश के उज्ज्वल भविष्य के लिये उस देश के मानव संसाधन का स्वस्थ एवं खुशहाल होना उसकी प्रगति के लिये पहली प्राथमिकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

■

2. भारत में एचआईवी का संकट और इसका समाधान

चर्चा का कारण

हाल ही में मिजोरम स्टेट 'एड्स नियंत्रण सोसायटी' (एमएसएसीएस) के अनुसार भारत में मिजोरम में सबसे ज्यादा एचआईवी एड्स (HIV AIDS) से पीड़ित मरीज पाए गए हैं। वर्ष 2017 के नवंबर तक मिजोरम में एचआईवी से 14,632 लोग पीड़ित थे, जो अगस्त 2018 तक बढ़कर 18,081 तक हो गये।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण' संगठन की ओर से जारी की गई, एचआईवी अनुमान रिपोर्ट 2017 के अनुसार मिजोरम उन पांच राज्यों में शामिल है, जहाँ संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कमी दर्ज की गई है।

मिजोरम स्टेट 'एडस नियंत्रण सोसाइटी' ने इंडियन एचआईवी एस्टिमेशन्स 2017 टेक्निकल रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मिजोरम एचआईवी संक्रमण के मामले में देश में पहले स्थान पर है। यहां जिन लोगों के खून के नमूनों की जांच की गई उनमें से 2.04 प्रतिशत लोग इससे पीड़ित थे। रिपोर्ट के मुताबिक, मिजोरम के बाद मणिपुर में 1.43 प्रतिशत और नागालैंड में 1.15 फीसदी मामले मिले हैं। एम.एस.ए.सी.एस के अधिकारी ने बताया कि संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध जिससे समलैंगिकता भी शामिल है। इसका दूसरा कारण सीरिंज के दोबारा इस्तेमाल की वजह से संक्रमण फैलना है। अधिकारी ने बताया कि 25-34 साल आयु वर्ग में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या 42 प्रतिशत से अधिक है जबकि 35-49 आयु वर्ग के 26 फीसदी लोग एचआईवी से संक्रमित हैं।

मिजोरम की राजधानी आईजोल में महिलाओं में 24.68 फीसदी एचआईवी का संक्रमण बढ़ा है, जबकि भारत से इसकी तुलना करें तो देश में महिलाओं में संक्रमण सिर्फ 1.6 फीसदी बढ़ा है। वहीं अगर गर्भवती महिलाओं में एचआईवी संक्रमण की बात करें तो मिजोरम में छह जगहों पर संक्रमण सबसे अधिक बढ़ा है, जबकि मेघालय और त्रिपुरा में एक जगह पर सबसे अधिक संक्रमण बढ़ा है।

परिचय

एड्स 'एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएन्सी सिंड्रोम' का संक्षिप्त नाम है। यह एक असाध्य बीमारी है, जिसे पिछली सदी के अस्सी के दशक के पूर्व कोई भी नहीं जानता था। इस बीमारी का पता सर्वप्रथम 1981 ई. में अमेरिका में हुआ, जब पाँच समलिंगी पुरुषों में इस अनोखी बीमारी के लक्षण पाए गए। एचआईवी का उद्भव अफ्रीका से माना जाता है तथा अमेरिका पहला देश था जिसने इस वायरस के बारे में लोगों को बताया।

इसकी जानकारी के लगभग आठ वर्ष पश्चात, 1989 ई. में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की एक गणना के अनुसार 1,40,000 से भी अधिक लोग इस बीमारी के शिकार पाए गए। 1997 ई. में यह संख्या बढ़कर 15,44,067 हो गई। वर्तमान में भारत में ही लगभग पचास लाख एचआईवी संक्रमित व्यक्ति निवास कर रहे हैं।

एड्स वास्तविक रूप में किसी एक बीमारी का नाम नहीं है अपितु यह अनेक प्रकार के रोगों का समूह है जो विशिष्ट विषाणुओं के द्वारा मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने से उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि 'एच. आई. वी.' से ग्रसित सभी मनुष्य एड्स के रोगी हैं। इस विषाणु से ग्रसित लोगों में 'एड्स' को पूर्णत: विकसित होने में 7 से 10 वर्ष तक लग सकते हैं।

विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में एचआईवी संक्रमण 'एड्स' के रोग के रूप में जल्दी विकसित होता है क्योंकि इन देशों के नागरिकों का खान-पान व स्वास्थ्य का स्तर अत्यंत निम्न है। केवल आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत में विश्व के 80% से भी अधिक 'एच. आई. वी.' ग्रसित लोग पाए जाते हैं।

मिजोरम में एड्स के मरीजों में वृद्धि का कारण

कभी उच्च साक्षरता के लिए सुर्खियों में रहने वाला मिजोरम राज्य अब एचआईवी के बढ़ते मामलों के कारण सुर्खियों में है। इस राज्य में बढ़ते एड्स के निम्नलिखित कारण हैं-

- राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आँकड़ों के मुताबिक मिजोरम में असुरक्षित यौन संबंध इसकी सबसे बड़ी वजह है। चूँकि मिजोरम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसकी सीमाएँ पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। परिणामस्वरूप इन देशों से कई तरह के अवैध व्यापार होते हैं जिससे कि मिजोरम में एड्स की समस्या बढ़ती जा रही है।
- न सिर्फ देह व्यापार बल्कि नशीले पदार्थों का एक बड़ा कारोबार मिजोरम में इन देशों से होता है। इनमें से कुछ मादक पदार्थ का सेवन सीरिंज के माध्यम से किया जाता है। इसी का परिणाम है कि यहां एचआईवी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।

एचआईवी के संबंध में भारत की स्थिति

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2017 तक करीब 1.20 लाख बच्चे और किशोर एचआईवी संक्रमण से पीड़ित थे। यूनिसेफ की रिपोर्ट 'चिल्ड्रन, एचआईवी और एड्स: द वर्ल्ड इन 2030' के मुताबिक पाकिस्तान में 5800, उसके बाद नेपाल में 1600 और बांग्लादेश में लगभग 1000 लोग एचआईवी के शिकार थे।

रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 26 शहरों में सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि ऐसे 41 प्रतिशत लोगों को अपने एचआईवी से ग्रस्त होने का पता था जो इंजेक्शन के माध्यम से मादक द्रव्य लेते थे। एचआईवी की स्थिति जानने वालों में सिर्फ 52 फीसद लोगों की इलाज तक पहुंच थी और इलाज पाने वालों में से 83 प्रतिशत लोगों में वाइरस नियंत्रण में था।

यूनिसेफ ने चेताया है कि अगर इसे रोकने की कोशिशें तेज नहीं की गई तो 2030 तक हर दिन दुनियाभर में एड्स की वजह से 80 किशोरों की मौत हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया ने बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और माताओं में एचआईवी की रोकथाम के लिए जरूरी प्रयास किए हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और पाकिस्तान उन 10 देशों में शामिल हैं, जहाँ 2016 में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में नए एचआईवी संक्रमण के 95 प्रतिशत से ज्यादा मामले हुए हैं।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में नए संक्रमण के ज्यादातर मामले भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया में हैं। पिछले साल, इन देशों में कुल मामलों के लगभग 95 प्रतिशत एच.आई.वी. के संक्रमण देखे गए। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में एचआईवी की महामारी ज्यादातर यौनकर्मियों, समलैंगिकों, ट्रांसजेंडर और मादक द्रव्य का इंजेक्शन लेने वालों के बीच पाई गई है। हालाँकि इन सब में एक अच्छी बात यह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एचआईवी के नए संक्रमण की वार्षिक संख्या 2017-18 दौरान 13 प्रतिशत गिरी है। 2010 में यह संख्या 3,10,000 थी जबकि 2016 में यह संख्या 2,70,000 थी।

सरकारी प्रयास

मिजोरम में तेजी से पांव पसार रहे एचआईवी रोग से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरूआत की है। अभियान की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा था कि राज्य की वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। मालूम हो कि वर्ष 2011-12 में राज्य में एचआईवी फैलने की दर 4.8 फीसद थी, जो 2012-13 में घटकर 3.8 पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद इस बीमारी के फैलने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्ष 2017-18 में एचआईवी के फैलने की दर 7.5 फीसद तक पहुंच गई थी। मार्च 2019 में एचआईवी फैलने की ये दर 9.2 फीसद तक पहुंच गई है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है।

बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से सटे इस राज्य में एचआईवी का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं जो महीने में 25 दिन खुले रहते हैं। इन केंद्रों पर रोजाना एचआईवी/एड्स के नौ नए मामले पहुंच रहे हैं। मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा. लालथेंगलियानी बताती हैं, "पूरे राज्य में 44 ऐसे केंद्र हैं जहाँ इस बीमारी की जांच और पुष्टि की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्य में एचआईवी का पहला मामला 1990 में सामने आया था।"

संयुक्त राष्ट्र का एड्स पर कार्यक्रम (UNAIDS) वर्ष 1994 में अपनी स्थापना के बाद से एड्स के विरुद्ध विश्व जनमत को सफलतापूर्वक जुटाने में सक्षम रहा है। एड्स का प्रभावी उपचार न होने से अभी तक 20 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। एड्स उन्मूलन के प्रयासों में वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र का राजनीतिक प्रस्ताव बेहद महत्त्वपूर्ण था।

एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिये वैश्विक कोष (Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and Malaria- GFATM) की स्थापना और सस्ती भारतीय औषधियों ने कई देशों में उपचार को आसान बना दिया।

एड्स पर अपनी रिपोर्ट में यूएन एड्स ने कहा है कि इस खतरनाक रोग के खिलाफ संघर्ष में पहली बार पलड़ा भारी हुआ है क्योंकि एचआईवी वाइरस से संक्रमित 50 फीसद लोगों को अब इलाज उपलब्ध है जबकि 2005 के बाद पहली बार एड्स से संबंधित मौतों की संख्या तकरीबन आधी हो गई है।

रोकथाम के तरीके

एचआईवी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसकी चपेट में आने वाले मरीजों को लंबे समय तक इस बीमारी का आभास ही नहीं होता है। ऐसे लोग अगर प्री-एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस (PrEP) गोलियां लें तो वह संक्रमण से बच सकते हैं। इन दवाओं को रोज खाना होता है। इनका असर इस बात पर निर्भर होता है कि इन्हें कितना नियमित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।

चिकित्सकों के अनुसार प्री-एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस (PrEP) गोलियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम हैं, लगभग उतना ही जितना किसी पेनकिलर गोली का होता है। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2017 में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि यौन रूप से सक्रिय किशोर-किशोरियों में भी ये दवा काफी सुरक्षित रही हैं। जानकार मानते हैं कि जागरूकता के अभाव की वजह से इतनी असरदार दवा के बारे में अब तक ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ देशों में ये दवाएं महंगी होने के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। वहीं कुछ जगह पर स्वास्थ्यकर्मी जानबूझकर इस दवा के बारे में नहीं बताते हैं।

विश्व एड्स दिवस के उद्देश्य

विश्व एड्स दिवस की शुरूआत मात्र स्वास्थ्य के क्षेत्र को और मजबूत बनाना और लोगों को एचआईवी एड्स के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करना है क्योंकि एचआईवी एड्स से बचने का एकमात्र उपाय है एचआईवी एड्स के विषय में जागरुकता। साल 2018 का थीम: 'अपनी स्थिति जानें'। इसका मतलब यह है कि हर इंसान को अपने एचआईवी स्टेटस की जानकारी होनी चाहिए. एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है।

- विश्व स्तर पर एचआईवी, एड्स के लिए रोकथाम और नियंत्रण उपायों में वृद्धि के लिए सदस्य राज्यों को निर्देशित करना।
- सदस्य को रोकथाम, देखभाल और एचआईवी/एड्स के उपचार और योजना को लागू करने के लिए एक तकनीकी सहायता की पेशकश, बच्चे को माँ से संक्रमण को रोकना, एसटीआई नियंत्रण (STI)और एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी।
- लोगों को एंटीरेट्रोवायरल दवाइयों के विषय में जागरूकता प्रदान करना जिनसे उन्हें एचआईवी एड्स से लड़ने में मदद मिल सके।
- सबसे प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए अभियान में सहकर्मी समूहों को शामिल करना।
- स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संरचनाओं से अधिक छात्रों को एड्स के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना।
- एचआईवी/एड्स से संक्रमित रोगियों की संख्या को कम करने और नियंत्रित करने के साथ-साथ यौन संबंध के दौरान कंडोम के उपयोग के लिए सहकर्मी समूहों को प्रोत्साहित करना।

अन्य उपाय

- **साथी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानना चाहिए:** एक साथ रहने वाले लोगों

को चाहिए की वे एक-दूसरे के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जाने। विभिन्न राज्यों में कई स्वास्थ्य केंद्र परीक्षण किट प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस रोग के होने की आशंका हो तो इन किटों का इस्तेमाल करना चाहिए।

- **सुरक्षित यौन संबंधः** चूंकि वायरस के बड़े पैमाने पर फैलने के प्रमुख कारणों में से एक असुरक्षित यौन संबंध है, इसलिए इससे सुरक्षा के लिए प्रर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध रखने की वजह से एचआईवी या अन्य एसटीडी के संबंध में आने की अधिक सम्भावना रहती है। अतः इससे बचना चाहिए।
- **दवाओं का दुरुपयोग न करें:** दवाओं का दुप्रयोग न करें। हालांकि, यदि आप दवा लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सुइयों को कीटाणुरहित कर दिया गया है और उन्हें किसी और के साथ साझा नहीं किया गया है।
- **प्री-एक्सपोजर प्रोफेलेक्सिसः** पीड़ित व्यक्ति को प्री-एक्सपोजर प्रोफेलेक्सिस के बारे में किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करनी चाहिए। इससे शुरूआती चरणों में एचआईवी संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। इसे एचआईवी के संपर्क में आने के तीन दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।

आगे की राह

एड्स भारत के लिए सिर्फ मिजोरम या उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे भारत की समस्या है। यह बीमारी उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूरब से लेकर पश्चिम सभी जगह बढ़ रही है, इस बीमारी की वजह जो कुछ भी हो, ऐसे लाइलाज बीमारियों के खात्मे के लिए देश के स्तर पर प्रयास तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो प्रयास चल रहे हैं उसका भी सहभागी बनना चाहिए।

यदि मिजोरम की बात करें तो सरकार अपने स्तर पर कई कार्य कर रही है लेकिन आम नागरिकों को भी इसके उन्मूलन के लिए भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ाकर, नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर, बच्चों में खासकर युवाओं पर कड़ी नजर रखकर, विदेशी नागरिकों तथा विदेशी सामानों की गहन जाँच पड़ताल कर आदि के माध्यम से रोका जा सकता है।

सरकार चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार उसे चाहिए कि पड़ोसी देशों की सीमाओं की चौकसी बढ़ा दी जाय। आयात की गई वस्तुओं की भी गहन जाँच पड़ताल हो और इसके पीड़ित व्यक्तियों की नियमित रूप से चिकित्सीय जाँच हो, जिससे कि इस रोग के प्रसार को रोका जा सके।

इसके अलावा जाँच पड़ताल कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी अपने कर्त्तव्यों को समझना होगा क्योंकि यह व्यक्तिगत बुराई कुछ समय बाद सामाजिक बुराई के रूप में तब्दील हो जाती है और उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। अतः इस तरह की गंभीर बीमारी से निपटने के लिए सरकार व समाज दोनों को आगे आना होगा जिससे कि वर्तमान और भविष्य दोनों को सुधारा जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. भारत में खाद्य अपमिश्रण एवं संदूषण

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के लिए एक एडवायजरी जारी की जिसमे कहा गया कि अगर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो साल 2025 तक देश की करीब 87 फीसदी आबादी कैंसर की चपेट में होगी।

परिचय

सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें से कोई मूल्यवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए या भोज्य पदार्थ को अनुचित ढंग से संग्रहीत किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ को मिलावटयुक्त कहा जाता है। आज हालात यह हैं कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय बना रहता है। दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं रहा है।

मिलावट का प्रभाव

वर्तमान समय में मिलावट का सबसे अधिक कुप्रभाव हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। अनेक स्वार्थी उत्पादक एवं व्यापारी कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते अवयवों की मिलावट कर रहे हैं, स्मरणीय हो कि शरीर के पोषण के लिए हमें खाद्य पदार्थों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण आदि की पर्याप्त मात्रा को आहार में शामिल करना आवश्यक होता है तथा ये सभी पोषक तत्व संतुलित आहार से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह तभी संभव है, जब बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री, दालें, अनाज, दुग्ध उत्पाद, मसाले, तेल इत्यादि मिलावटरहित हों।

ज्ञातव्य है कि खाद्य अमिश्रण से उत्पाद की गुणवत्ता काफी कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों में सस्ते रंजक इत्यादि की। मिलावट करने से उत्पाद तो आकर्षक दिखने लगता है, परंतु पोषकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वही खाद्य अपमिश्रण से मूल खाद्य पदार्थ तथा मिलावटी खाद्य पदार्थ में भेद करना काफी मुश्किल हो जाता है। अपमिश्रित आहार का उपयोग करने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकार उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। खाद्य अपमिश्रण से आखों की रोशनी जाना, हृदय संबन्धित रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के रोग, पक्षाघात व कैंसर जैसी समस्या हो सकती हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समग्र रोग पर्यवेक्षण कार्यक्रम (डीएसपी) के ताजा आंकडों के मुताबिक 2017 में देश में फूड प्वाइजनिंग के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के मुताबिक लोगों और डॉक्टरों की उदासीनता और उपेक्षा भाव के कारण फूड प्वाइजनिंग के मामले दर्ज नहीं हो पाते और दर्ज न हो पाने की दर 100 से 300 गुना तक हो सकती है।

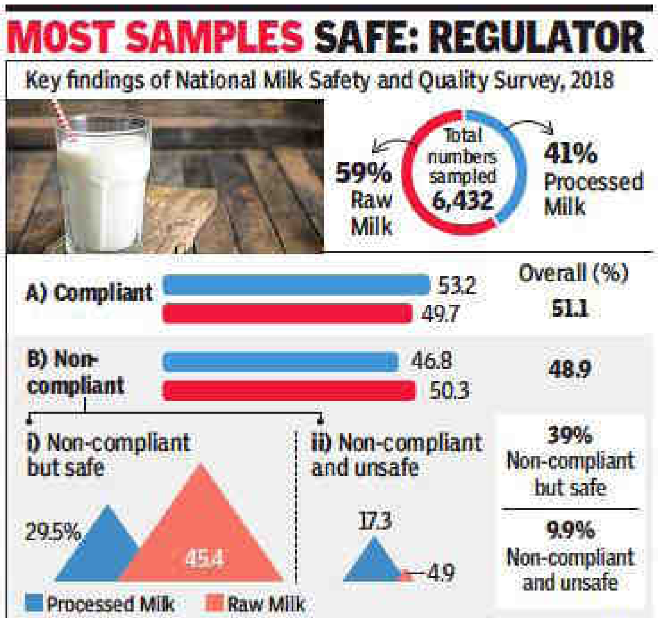

(Source: Food Safety and Standards Authority of India)

खतरे की भयावहता का अंदाजा हम इस आंकड़े से भी लगा सकते हैं कि देश के 127 करोड़ लोगों की जिंदगी इसी पर आश्रित है कि वे क्या खाते हैं।

आज खाद्य पदार्थों के इतर डीजल-पेट्रोल और मोबिल ऑयल में भी केरोसीन आदि की मिलावट की जा रही है। मिलावटी तेल और मोबिल ऑयल से इंजन जल्दी खराब होता है। इंजन के स्पेयर पार्ट्स समय से पहले खराब होने लगते है। साथ ही माइलेज भी कम आता है। वाहन के इंजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए शुद्ध तेल का इस्तेमाल करना चाहिए।

सरकारी प्रयास

भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन् 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (पीएफए एक्ट 1954) लागू किया गया। उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुए उपरोक्त खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम बनाया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं-

- जहरीले एवं हानिकारक खाद्य पदार्थों से जनता की रक्षा करना।
- घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री की रोकथाम
- धोखाधड़ी प्रथा को नष्ट करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
- इसके अलवा सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 में सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया। इस कानून में दूषित एवं मिलावटी भोजन के उत्पादकों, वितरकों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना और 6 महीने से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान किया गया है। साथ ही एफएसएसएआई ने 'खाद्य सुरक्षा और पोषण निधि' निर्मित किये जाने का भी सुझाव दिया है जिसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के बीच इसका प्रचार और आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करना है।
- विदित हो कि आजकल दूध में हो रही मिलावट को देखते हुए इसे रोकने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India) ने 1 जनवरी 2020 से एक नया नियम बनाने जा रही है जिसके अनुसार अब संगठित क्षेत्र के दूध कंपनियां जैसे मदर डेरी (Mother Dairy), अमूल (AMUL), पारस (Paras) को भी अपने दूध के सैंपल (Milk Sample) की जाँच FSSAI की लैब में कराना होगा।
- सरकार द्वारा मिलावट को रोकने के लिए आईपीसी की धारा 272 एवं 273 के अंतर्गत पुलिस प्रशासन को सीधे कार्रवाई की भी छूट दी गई है।
- गौरतलब है कि सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मिलावटी और गैर-गुणवत्तापूर्ण खाने-पीने की चीजों पर रोकथाम के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की स्थापना भी की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कदम उठाते हुए 2016 में केंद्र और राज्य सरकारों को फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की फूड सेफ्टी अथॉरिटी अपने इलाके में मिलावट के लिए हाई रिस्क क्षेत्र और त्योहार के दौरान ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले। साथ ही, राज्य की फूड सेफ्टी अथॉरिटी यह तय करे कि इलाके में पर्याप्त मान्यता प्राप्त लैब हों। राज्य और जिला स्तर पर लैब पूरी तरह संसाधनों, टेक्निकल प्रोफेशनल और टेस्ट की सुविधा से भी लैस हो।
- अन्य प्रयासों के तहत सरकार ने मिलावट को रोकने के लिए गाँव और शहरी स्तर पर फूड एण्ड ड्रग नामक आयोग की भी नियुक्ति की है। जहाँ शहरों में मुनिसिपल अधिकारी यह कानून लागू करते हैं। वहीं गाँव में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त फूड इन्सपेक्टर यह काम करते हैं। फूड इन्सपेक्टर का काम होता है कि वह सभी दुकानों और खाने के सामान आदि की दुकानों में जाए और वहाँ बिकने वाली खाने की चीजों की गुणवत्ता की जाँच करे।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया।जिसे 1 अगस्त , 2011 को केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया। विदित हो कि इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।

- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा, यह देश के सभी राज्यों , जिला एवं ग्राम पंचायत स्तकर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

चुनौतियाँ

- मिलावट रोकने के लिए कानून केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन पालन राज्य की एजेंसियों को करवाना होता है। राज्य का खाद्य विभाग, नगर निगम, पुलिस, एफएसएसएआई का जो राज्य कार्यालय है, उनके जिम्मे कानून का अनुपालन करवाना होता है। लेकिन, इन महकमों में इतना भ्रष्टाचार है कि अधिकारी कानून का डर दिखाकर वसूली करते हैं। वे सैंपल इकट्ठा कर उनकी जांच नहीं करवाते।
- लोगों में जागरूकता कि कमी के कारण भी मिलावट का यह धंधा खुब फलफूल रहा है।
- आइडीएसपी के मुताबिक, फूड प्वाइजनिंग के मामले वहीं सबसे ज्यादा होते हैं जहां बड़े पैमाने पर भोजन पकाया जाता है। मसलन, कैंटीन, रेस्तरां, होटल, होस्टल और शादी-विवाह के कार्यक्रम। ये सभी एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट हासिल

करते हैं, लेकिन मिलावटी और असुरक्षित खाद्य सामग्री की आपूर्ति की रोकथाम का कोई इंतजाम शायद ही उनके पास होता है। ऐसे कोई आंकड़ें नहीं हैं, जिनसे पता चले कि इनमें से कितने के लाइसेंस कभी रोके गए या रद्द किए गए है।

- दुनिया भर में इस संदर्भ में व्यवस्था यह है कि खाद्य सुरक्षा के अधिकारी समय-समय पर अपने कामकाज के बारे में आम लोगों का फीडबैक लेते हैं और इसके नतीजों को सार्वजनिक करते हैं। फिर इस पर विचार होता है कि कहाँ सुधार करना है और किन वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर करनी है। हमारे कानून में भी आम लोगों से फीडबैक लेने की व्यवस्था है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ हैं।
- अस्पतालों में बेतहाशा भीड़ और स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य बजट में इजाफे की बढ़ती मांग का यही साफ संदेश है कि देश में खाने-पीने की निगरानी व्यवस्था बेहद खराब और नाकाफी है। यह आज के दौर की जरूरतों के हिसाब से बिलकुल नहीं हैं, न ही ये दुनिया में मान्य मानकों पर खरी उतरती है।

सुझाव

- आम लोगों से हर साल खाद्य सुरक्षा मानकों और उपलब्ध सामग्रियों पर रायशुमारी की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए।
- एफएसएसएआई के कामकाज पर भी ऐसा ही सर्वे हर साल किया जाना चाहिए। इसमें सरकार को कोई विशेष खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे यह तय हो जाएगा कि एफएसएसएआई आखिर क्यों ठीक काम नहीं कर पा रही है? एफएसएसएआई के इंस्पेक्टरों और लेबोरेटरियों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय की जाए।
- आम आदमी को मिलावटी सामान बेचना भी पूरे राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए उसकी सजा कठोर से कठोर होनी चाहिए। इसके लिए कानून की सख्ती के साथ ही सरकार की तीव्र राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है।
- मिलावटी राष्ट्रव्यापी समस्या है लेकिन इसे लेकर पूरे देश में एक जैसा कानून आज भी नहीं है। अभी हालात यह हैं कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में दूध में मिलावट के अपराध पर उम्र कैद की सजा दिए जाने का प्रावधान हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कानून नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है।
- सख्त कानून बनाए जाने का जहाँ तक सवाल है, इन दिनों यह रिवाज- सा चल पड़ा है। कि अगर कोई अपराध बढ़ रहा है तो उसकी सजा बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है पहले से मौजूद कानूनों का सही तरह से क्रियान्वयन किया जाए।
- मिलावटखोरी के लिए कानून में सजा बढ़ाने से कानून के दुरुपयोग की आशंका बढ़ने का खतरा होता है। ऐसे में कोई भी कदम पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही उठाया जाना चाहिए।
- दोषियों को सजा मिले और खाने की चीजों में मिलावट की समस्या से निपटा जा सके इसके लिए बड़े स्तर पर लोगों में जानकारी फैलाने की जरूरत है।
- यदि बाजार में कोई नकली सामान बिक रहा है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी केवल पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं के निर्माता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में उसका नकली माल नहीं बिके। इसके लिए निर्माणकर्त्ता को प्रशिक्षित समूहों द्वारा इस बात के लिए तैयार किया जाएगा।
- दवा, खाद, कीटनाशक, बीज में मिलावट का जिक्र होना चाहिए दरअसल जब मिलावट की बात आती है तो केवल खाद्य पदार्थों की बात की जाती है, जबकि जरूरत इन चीजों की गुणवत्ता के मानक भी तय करने की है।
- संसद में मिलावट को लेकर सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी खाद्य पदार्थों की लगातार निगरानी और नमूनों की जाँच करते हैं लेकिन, जिन प्रयोगशालाओं में नमूनों की जाँच की जाती है वहां संसाधनों का अभाव है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि बिना जांच के ही सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए जाते हैं। इसको लेकर सरकार को अलग से एक निगरानी विभाग कि व्यवस्था करनी चाहिए।
- डब्ल्यूटीओ के समझौते के हिसाब से भारतीय खाद्य कानून को भी बदलने की जरूरत है। पुराने पीएफए कानून के तहत कई गंभीर शिकायतें आ रही थीं। कई नियम वैज्ञानिक तर्कों पर खरे नहीं उतर रहे है। फूड इंस्पेक्टर और लेबोरेट्री के विशेषज्ञों के भ्रष्टाचार के मामले बड़े पैमाने पर दिखने लगे हों। कानून में कड़े प्रावधानों का डर दिखाकर फूड इंस्पेक्टर कारोबारियों से घूस लेकर मामला रफा-दफा कर रहे हैं।
- मिलावटी पदार्थों से बचने और अपमिश्रण की पहचान के लिए गृहिणियों का जागरूक होना अति आवश्यक है। अतः इस दिशा में एक जागरूक मंच द्वारा घर-घर जाकर महिलाओं को इस संदर्भ में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कुछ आवश्यक बिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए जैसे खुली खाद्य सामग्री न खरीदें। अधिकतर मानक प्रमाण चिन्ह (एगमार्क, एफपीओ, आईएसआई, हॉलमार्क) अंकित सामग्री खरीदें तथा खरीदे जाने वाली सामग्री के गुणों, रंग, शुद्धता आदि की समुचित जानकारी रखा जाए। सदैव जानकार दुकानदारों व सत्यापित कम्पनियों का सामान लें तथा जहाँ तक हो सके पैकेज्ड सामान का उपयोग करते समय कम्पनी का नाम व पता, खाद्य पैकिंग व समाप्ति की तिथि, सामान का वजन, गुणवत्ता लेबल का अवश्य ध्यान रखा जाए क्योंकि स्वस्थ और निरोगी जीवन ही सफलता है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि खाद्य पदार्थों मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और इसका रोकथाम के लिए न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हमारी भावी पीढ़ी स्वच्छ और मिलावट रहित खाद्य पदार्थों का सेवन कर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। स्वस्थ्य और खुशहाल जीवन न सिर्फ उनके हित में होगा बल्कि राष्ट्र के लिए भी अनुकूल होगा चूँकि स्वस्थ्य और खुशहाल राष्ट्र ही विकसित होता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. तुर्की–सीरिया संकटः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में सीरिया के उत्तर-पूर्व क्षेत्र और तुर्की के सीमाई क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात तुर्की ने इन क्षेत्रों में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की है, जिसे उसने 'ऑपरेशन पीस स्प्रिंग' (Operation Peace Spring) नाम दिया है।

परिचय

सन् 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू होकर अरब स्प्रिंग (Arab Spring) जब सीरिया पहुँची तो वहाँ भी गैर-लोकतांत्रिक सरकार (राष्ट्रपति बशर अल-असद के नेतृत्व की सरकार) के विरुद्ध महँगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गये। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए रूस व ईरान समर्थित बशर अल-असद सरकार ने सैन्य शक्ति का सहारा लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सीरिया गृह युद्ध की चपेट में आ गया और सन् 2014 में इस्लामिक स्टेट (आइएस) जैसे आतंकी संगठन ने सीरिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया।

सीरिया से आतंकवाद को खत्म करने व आइएस को हराने के लिए यूएसए के प्रयासों से सन् 2015 में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (SDF) का गठन हुआ। एसडीएफ कई समूहों का एक गठबंधन है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी 'पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट' (इसे YPG के नाम से भी जाना जाता है) की है। पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट, सीरिया के कुर्द लड़ाकों की है। अमेरिका ने एसडीएफ को कई प्रकार की सहायता (यथा-तकनीकी, हथियार, प्रशिक्षण, रसद आपूर्ति आदि) देकर सीरिया से इस्लामिक स्टेट का खात्मा कर दिया। इसके बाद सीरिया के उन इलाकों (मुख्यतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) में जहाँ कुर्द जनसंख्या ज्यादा रहती है वहाँ कुर्द लोगों ने अपनी सरकार स्थापित की और इस सरकार को पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट (YPG) का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ।

अब सीरिया के किसी भी शहर पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा नहीं है और उसके आतंकी मरुस्थली क्षेत्रों की ओर भाग गये हैं साथ ही साथ सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कुर्द लोगों की स्वयं की सरकार स्थापित हो गयी इस स्थिति में अमेरिकी सेना सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों (तुर्की सीमा के पास) से वापस अपने देश लौट गयी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुर्की सेना ने सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में हमला बोल दिया ताकि कुर्द लड़ाकों को यहाँ से खदेड़ा जा सके।

मजबूत तुर्की सेना के सामने कुर्द लड़ाकों के पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट को भारी मात्रा में क्षति हुई है और उसके कई लड़ाके भी मारे गये। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, उत्तरी सीरिया में संघर्ष की स्थिति के परिणामस्वरूप लगभग एक लाख 60 हजार लोगों ने सुरक्षित स्थान की ओर पलायन किया है। हालाँकि बीबीसी जैसे मीडिया संगठनों का कहना है कि कुर्द-तुर्की संघर्ष से सीरिया के उत्तर-पूर्व में लगभग तीन लाख लोग बेघर हुए हैं।

कुर्द एवं कुर्दिस्तान

कुर्द पश्चिम एशिया या मध्य-पूर्व का एक नृजातीय समूह (Ethnic Group) है जो वर्तमान में कई देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं, ये देश हैं- तुर्की (दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र), सीरिया (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र), ईरान (उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र), इराक (उत्तरी क्षेत्र) और आर्मेनिया (दक्षिणी क्षेत्र)। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे विश्व में कुर्दों की आबादी 35 से 40 मिलियन तक है और यह दुनिया का सबसे बड़ा राज्यविहीन नृजातीय समूह है। विशाल जनसंख्या और एक विशिष्ट सांस्कृतिक व नृजातीय पहचान के बावजूद भी कुर्द लोगों के पास ऐसा कोई अपना स्वतंत्र राज्य या राष्ट्र नहीं है जहाँ वे स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें और अपनी संस्कृति के अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा व उनका संवर्द्धन कर सकें। कुर्द लोगों द्वारा ऐतिहासिक रूप से समय-समय पर कुर्दिस्तान रूपी राष्ट्र के गठन की माँग उठायी जाती रही है जिसमें वह तुर्की का दक्षिण पूर्वी-क्षेत्र, सीरिया का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, ईरान का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, इराक का उत्तरी क्षेत्र और आर्मेनिया का दक्षिणी क्षेत्र शामिल करने की बात करते हैं अर्थात् जहाँ-जहाँ कुर्द जनसंख्या बाहुल्य रूप से निवास करती है उसे वह कुर्दिस्तान में शामिल करते हैं।

कुर्द एवं तुर्की संघर्ष

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि के दौरान कुर्द लोगों ने एक नये कुर्दिस्तान के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा था। इसमें कहा गया था कि आधुनिक तुर्की, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों को शामिल करके कुर्दों के लिए एक कुर्दिस्तान नामक देश का गठन किया जाये। इसके पश्चात् 1920 की सेव्रेस की संधि (Treaty of Serveres) में पश्चिमी देशों ने कुछ हद तक कुर्दों की माँग पर विचार किया और पश्चिम एशिया में कुछ क्षेत्र को कुर्दिस्तान हेतु निर्धारित किया, लेकिन बाद में कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिक तुर्की का गठन हुआ और तुर्की ने किसी भी तरह के कुर्दिस्तान की माँग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके पश्चात् मार्क्सवाद से प्रभावित अब्दुल्ला अकालान ने सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में एक स्वतंत्र देश 'कुर्दिस्तान' की स्थापना के उद्देश्य से तुर्की के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में 'कुर्दिस वर्कर्स पार्टी' (जिसे PKK के नाम से भी जाना जाता है) का गठन किया। अस्सी के दशक के मध्य में कुर्दिस वर्कर्स पार्टी ने तुर्की के विरुद्ध जंग छेड़ दी। तुर्की की सेना और कुर्दिस वर्कर्स पार्टी के बीच संघर्ष की वजह से तुर्की में गृहयुद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं और यहाँ हजारों की संख्या में लोग मारे गये, हालाँकि इसमें कुर्द लोगों की संख्या अधिक थी।

कुर्दिस वर्कर्स पार्टी और तुर्की सेना के बीच अस्सी के दशक में शुरू हुई जंग आज तक जारी है, हालाँकि समय-समय पर इस संघर्ष पर विराम जरूर लगे किन्तु कुर्द लोगों की कुर्दिस्तान की माँग खत्म नहीं हुई है। सन् 2015 में गठित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के मुख्य अंग 'पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट' को तुर्की की सरकार कुर्दिस वर्कर्स पार्टी का ही सीरिया के उत्तर-पूर्व में विस्तार मानती है।

ऑपरेशन पीस स्प्रिंग

तुर्की ने सीरिया के उत्तर-पूर्व में पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट और इस यूनिट के समर्थन वाली कुर्द सरकार के विरुद्ध अपनी सैन्य कार्रवाई को 'ऑपरेशन पीस स्प्रिंग' नाम दिया है। तुर्की का कहना है कि कुर्दिस वर्कर्स पाटी और पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट, दोनों ही चरमपंथी संगठन हैं जो तुर्की व मध्य-पूर्व के स्थायित्व और शांति के लिए खतरा हैं। तुर्की, सीरिया के उत्तर-पूर्व में ऑपरेशन पीस स्प्रिंग द्वारा सीरिया के उन समूहों (समुदायों) एवं शरणार्थियों को बसाना चाहता है जो तुर्की से मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं। इस जनांकिकीय परिवर्तन (Demographic Change) को तुर्की ने सुरक्षित क्षेत्र (Safe Zone) की संज्ञा दी है। उल्लेखनीय है कि सीरिया में कई ऐसे समुदाय या समूह हैं जो तुर्की के प्रति सहानुभूति रखते

हैं। यदि ये सहानुभूति रखने वाले लोग सीरिया के उत्तर-पूर्व में तुर्की की सीमा के पास बस जायेंगे, तो सीरिया के कुर्दों और तुर्की के कुर्दों के बीच संपर्क टूट जायेगा तथा इसका परिणाम यह होगा कि तुर्की में कुर्दिस्तान की माँग शिथिल पड़ जाएगी।

सुरक्षित क्षेत्र

सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तुर्की अपनी सीमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ एक 'सुरक्षित क्षेत्र' का निर्माण करना चाहता है, इसीलिए वह इस क्षेत्र से अपने विरोधी 'कुर्दों' को खदेड़ रहा है। संरक्षित क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी सीरिया क्षेत्र में तुर्की सीमा के साथ-साथ लगभग 480 किमी लम्बा और 30 किमी चौड़ा एक पट्‌टीनुमा क्षेत्र होगा। इसमें तुर्की के हितों के रक्षक लोग (सीरियाई शरणार्थी आदि) रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सीरियाई शरणार्थी ऐसे लोग हैं जो सीरिया में गृह युद्ध के दौरान तुर्की में पलायन कर गये थे। तुर्की से ये लोग यूरोपीय एवं अन्य देशों की ओर भी गये हैं, लेकिन ज्यादातर अभी तुर्की में ही रह रहे हैं।

तेल का खेल

इस समूचे घटनाक्रम में अमेरिका की पश्चिम एशिया को लेकर पूर्व से चली आ रही अस्थायी और अस्पष्ट नीति एक बार फिर सामने आई है। बीते कई सालों से अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ मध्य पूर्व को असंतुलित करने में लगी रही हैं। इसमें 'तेल की राजनीति' (Petroleum Politics) के साथ-साथ मजहब या धर्म की जोर आजमाइश को बढ़ावा दिया गया है। विश्व के संपूर्ण उपलब्ध तेल का लगभग 68 प्रतिशत ईरान की खाड़ी के आसपास के इलाकों, मुख्य रूप से कुवैत, ईरान और सऊदी अरब में पाया जाता है। सोवियत संघ और अमेरिका तो तेल के मामले में आत्मनिर्भर हैं लेकिन यदि यूरोप को इस इलाके से तेल मिलना बंद हो जाए तो उसके अधिकांश उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और इस प्रकार यूरोपीय महाद्वीप की औद्योगिक और सामरिक क्षमता बर्बाद हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी देश मध्य पूर्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। गौरतलब है कि आइएस ने इस इलाके (सीरिया, इराक इत्यादि) के तेल कुओं पर अपना कब्जा जमा कर महाशक्तियों के सामने चुनौती पेश कर दी थी, जिसके बाद पश्चिमी देशों, अमेरिका, रूस, तुर्की जैसे देशों ने मिलकर आइएस को खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किंतु लम्बे समय बाद इस युद्धग्रस्त इलाके से आइएस समाप्त होने की कगार पर आया तो अब एक बार फिर तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल कर नये संकट को जन्म दे दिया है।

वैश्विक प्रतिक्रिया

कुर्द और तुर्की के बीच वर्तमान में व्याप्त संघर्ष पर वैश्विक प्रतिक्रिया काफी हुई है, जिसे निम्नांकित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- अमेरिका सहित विश्व के अन्य लोग इस संघर्ष के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि अमेरिकी सरकार ने सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से अचानक सेना वापस बुला ली, जिससे तुर्की को सैन्य कार्रवाई का मौका मिल गया। अमेरिका को चाहिए था कि इस क्षेत्र से धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से सेना की वापसी सुनिश्चित की जाती ताकि वहाँ शांति और स्थायित्व के लिए समय मिल पाता।
- सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के प्रमुख अंग 'पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट' ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट को खत्म करने हेतु अग्रणी भूमिका निभायी थी। इस यूनिट ने मध्य-पूर्व से आतंकवाद को खत्म करने हेतु अमेरिका का भरपूर साथ दिया था और आतंकियों के विरुद्ध जमीनी लड़ाई में सबसे आगे रहा था, तो इस स्थिति में जानकारों द्वारा यह सवाल उठाना लाजिमी है कि कभी अमेरिका का सहयोगी रहा पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट को अमेरिका एकदम से अकेला कैसे छोड़ सकता है? यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब साधन विहीन कुर्द लड़ाकों के विरुद्ध साधन सम्पन्न तुर्की सेना हो।
- विद्वानों का मानना है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे को लेकर कार्य करता है। उसके इस विचार को अफगानिस्तान में भी देखा जा सकता है। सोवियत संघ को संतुलित करने हेतु अमेरिका ने अफगानिस्तान को गृहयुद्ध की स्थिति में ढकेल दिया और अब वह तालिबान जैसे चरमपंथी व आतंकी समूहों से समझौता करने में लगा है। इसी प्रकार की रणनीति को अमेरिका ने सीरिया में भी अपनाया है।
- हालाँकि अमेरिका ने चौतरफा दबाव को देखते हुए तुर्की के साथ एक अस्थाई संघर्ष विराम का समझौता किया है ताकि मतभेदों को दूर करके स्थिति को सामान्य किया जा सके। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि अमेरिका और तुर्की के बीच हुए अस्थाई संघर्ष विराम समझौते का असर नहीं हो रहा है क्योंकि तुर्की की सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच रूक-रूककर गोलाबारी जारी है। इसके अतिरिक्त, तुर्की लगातार कड़े बयान दे रहा है कि वह किसी के भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और कुर्दों के विरुद्ध तब तक कार्रवाई जारी रहेगी जब तक वो सुरक्षित क्षेत्र (Safe Zone) से पीछे नहीं हट जाते हैं। इसके अतिरिक्त तुर्की का कहना है कि अमेरिका के साथ हुआ संघर्ष विराम समझौता हमारी शर्तों पर हुआ है। अमेरिका को इस समझौते के द्वारा सिर्फ कुछ समय दिया गया है जिससे कि वो चरमपंथी ताकतों को सुरक्षित क्षेत्र छोड़ने हेतु समझा सके।
- यूरोपीय संघ ने अमेरिका की ही तरह तुर्की पर आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंध लगाने की कड़ी चेतावनी दी है। इसके जवाब में तुर्की का कहना है कि वह सीरिया से आये शरणार्थियों को संरक्षित क्षेत्र में बसा रहा है यदि इस योजना में बाधा आयी तो मध्यपूर्व से पश्चिमी देशों की ओर जाने वाले शरणार्थियों की संख्या में इजाफा होगा जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा।
- सीरिया में रूस और ईरान जैसे देशों के अपने हित हैं। यही कारण है कि इन देशों ने अभी तक तुर्की पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाया है।
- भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो आंतकवाद के पोषक हैं और उसे अपनी विदेश नीति का एक उपकरण मानते हैं, उन्होंने परोक्ष-अपरोक्ष रूप से तुर्की का समर्थन किया है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने तुर्की की तरफ से सीरिया के पूर्वोत्तर हिस्से में की जा रही अकारण सैन्य कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत का कहना है कि तुर्की की इस कार्रवाई से न सिर्फ सीरिया के उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शांति व स्थिरता में बाधा आयेगी बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई भी कमजोर पड़ेगी। तुर्की की सैन्य कार्रवाई सीरिया की संप्रभुता पर चोट है, अतः किसी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर कार्रवाई से बचना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई से बड़ा मानवीय संकट पैदा होने का खतरा है।इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम तुर्की से आग्रह करते हैं कि वह संयम बरते और सीरिया की भौगोलिक संप्रभुत्ता और अखंडता का आदर करें। हम सभी मामलों को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाने का भी आग्रह करते हैं। सनद

रहे कि कश्मीर मुद्दे (अनुच्छेद 370 हटाने) पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का समर्थन चीन, मलेशिया और तुर्की, तीन देशों ने किया था। अतः विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भी अपनी विदेश रणनीति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि भारत हमेशा से मानवता का पक्षधर रहा है और उसने हर देश की संप्रभुत्ता का सम्मान किया है।

आगे की राह

अमेरिका सहित पूरी विश्व बिरादरी को तुर्की पर दबाव बनाने की आवश्यकता है ताकि कुर्दों के मानव अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। अमेरिका को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक स्थायी संघर्ष विराम समझौता कराना होगा और सीरिया के उत्तर-पूर्व में वहाँ के मूल निवासियों की पुनर्वापसी सुनिश्चित करानी होगी। सभी पक्षों को यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी मुद्दे का हल युद्ध या संघर्ष नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए शांतिपूर्ण वार्ता ही सबसे उपयुक्त रास्ता है। आज विश्व को गाँधीवाद की ओर देखने की आवश्यकता है, गाँधीजी का मानना था कि मानवता ही सर्वोपरि धर्म है और शांति व अहिंसा मानव के सबसे बड़े हथियार हैं, जिन्हें विश्व को अपनाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. भारतीय डाक सेवाः अब तक की यात्रा

चर्चा का कारण

प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस (World Post Day) 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को डाक विभाग के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इस दिवस को स्विट्जरलैंड के बर्न में वर्ष 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की स्थापना की याद में मनाया जाता है।

परिचय

एक समय था जब लोग खत या चिट्ठी के माध्यम से अपने शब्दों को ही नहीं बल्कि भावनाओं को भी पिरोया करते थे। इन खतों के माध्यम से वे दुःख-सुख की कहानियों के साथ, ढेर सारा प्यार भी आपस में बांटते थे।

भारत में डाकिया (Postman) की छवि आज भी काफी अच्छी है। एक डाकिया वो व्यक्ति होता है जो विशेषकर गाँवों में हर परिवार से सीधे जुड़ा हुआ होता है। समाज में अपनी ईमानदार छवि रखने वाले डाकिये की भूमिका कई फिल्मों में भी हमें देखने को मिलती है। वर्तमान में हम भले ही कुरियर पर शक कर सकते हैं, पर सरकारी पोस्टमैन का भरोसा और सम्मान आज भी वैसा ही है।

गौरतलब है कि बदलते वक्त के साथ बदलती तकनीक की वजह से लोग चिट्ठी से होते हुए कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन से ईमेल और वीडियो कॉलिंग तक आ पहुँचे। हालाँकि आज भी डाकघरों की अहमियत कम नहीं हुई है। वर्तमान में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। संचार क्रांति ने चिट्ठियों पर बेशक असर डाला पर भारत सरकार ने बहुत तेजी से डाक व्यवस्था का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया। इसके जरिए सरकारी योजनाओं को भी घर-घर पहुँचाया गया। वर्तमान में सड़कों पर जीपीएस (GPS) से लैस डाक गाड़ियाँ हैं, साथ ही मोबाइल ऐप भी शुरू किये गए हैं। दुनियाभर में जहाँ डाक सेवाएँ सिमट रही हैं वहीं भारतीय डाक न केवल तकनीक के साथ कदमताल कर रहा है बल्कि अपना विस्तार भी कर रहा है।

क्यों मनाया जाता है विश्व डाक दिवस

विश्व डाक दिवस उन संदेश वाहकों को याद करने का दिन है जो मोबाइल और वीडियो कॉल से पहले के जमाने से हमारे संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाते थे। इस दिवस का मकसद रोजमर्रा की जिंदगी और समाज के बीच रिश्ते मजबूत करने में डाक विभाग की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिन उन लोगों का महत्त्व समझाने का है जो सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बगैर हमारे संदेश पहुँचाते हैं। इस दिवस के जरिए डाकघरों के बीच तालमेल बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है।

पृष्ठभूमि

9 अक्टूबर, 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन (General Postal Union) का गठन किया गया। इसके गठन के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1 जुलाई, 1875 को लागू हुई, हालांकि 1 अप्रैल 1879 को जनरल पोस्टल यूनियन का नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union) कर दिया गया। गौरतलब है कि यूपीयू की स्थापना से पहले सभी देशों को एक दूसरे के यहाँ चिट्ठी भेजने के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि करनी पड़ती थी। डाक भेजने वाले को हर चरण और रास्ते में पड़ने वाले हर देश के लिए अलग से शुल्क चुकाना होता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए 1863 में अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल काँग्रेस की बैठक बुलाई गई। इसके बाद यूपीयू के गठन का फैसला किया गया। इस यूनियन की स्थापना से वैश्विक संचार क्रांति की शुरूआत हुई। 1969 में जापान के टोक्यो (Tokyo) में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन काँग्रेस (Universal Postal Union Congress) में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मानने की घोषणा की गई। गौरतलब है कि उस दौर में कहा गया कि 9 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय पत्रों के लिए पूरी दुनिया में मुक्त प्रवाह का रास्ता खोलने की एक कोशिश है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) 1948 में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी बन गई। यूपीयू का संविधान 1964 की वियना पोस्टल काँग्रेस में स्वीकार किया गया जो 1966 से लागू हुआ। वर्तमान में यूपीयू के 192 सदस्य देश हैं। यह एजेंसी विश्व डाक दिवस पर हर साल पोस्टल जारी करने के अलावा कई और कार्यक्रम आयोजित करती है। साथ ही एजेंसी डाक व्यवस्था से जुड़ी वैश्विक दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें भी करती रहती है।

एक दिलचस्प पहलू यह है कि भारत में हर वर्ष 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। भारत 1 जुलाई, 1876 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। उस वक्त भारत एशिया का पहला देश था जिसे इसकी सदस्यता मिली थी।

भारतीय डाक प्रणाली का विस्तार

200 वर्षों से ज्यादा पुरानी भारतीय डाक दुनिया की डाक प्रणालियों में अव्वल है। पूरी दुनिया में या तो डाकघर बंद हो रहे हैं या संचार क्रांति के

कारण सिमट रहे हैं, लेकिन भारतीय डाक का लगातार विस्तार हो रहा है। आज भी ये पूरे देश की संचार व्यवस्था की धड़कन बनी हुई है।

विदित हो कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने विश्वसनीय संचार व्यवस्था के तहत नियमित हरकारों (संदेशवाहकों) को सेवा में रखा। आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरूआत 18वीं सदी से पहले हुई।

1766 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की थी। डाक व्यवस्था का विकास वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कलकत्ता जीपीओ की स्थापना करके किया। इसके बाद मद्रास जनरल पोस्ट ऑफिस, 1786 और बंबई जनरल पोस्ट ऑफिस 1793 में अस्तित्व में आए।

उस वक्त के डाकघरों में एकरूपता लाने के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1837 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत डाक व्यवस्था के एकाधिकार की पहल हुई। इस अधिनियम से तीनों प्रेसीडेंसी-कलकत्ता, मद्रास और बंबई में सभी डाक संगठनों को आपस में मिलाकर देश स्तर पर एक अखिल भारतीय डाक सेवा बनाने की शुरूआत की गई। डाक व्यवस्था को सुचारु बनाने की दिशा में 1854 का पोस्ट ऑफिस अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। इसने डाक प्रणाली का स्वरूप ही बदल दिया, अर्थात सामान्य शब्दों में कहें तो भारत में वर्तमान डाक प्रणाली का मुख्य आधार यही कानून बना। इस कानून ने समूची डाक प्रणाली में सुधार किया। इसके जरिए भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में डाक धुलाई का एकाधिकार भारतीय डाकघरों को दिया गया। उसी वर्ष रेल डाक सेवा की भी शुरूआत की गई और भारत से ब्रिटेन और चीन के लिए समुद्री डाक सेवा शुरू की गई।

1 जुलाई 1852 को सिंध (पाकिस्तान) में ही डाक मोहर बनी। इसके दो वर्ष बाद यानी अक्टूबर 1854 में आधा आना, एक आना और चार आने के टिकट की बिक्री भी शुरू हुई। इन टिकटों पर रानी विक्टोरिया की तस्वीरें थीं। अंग्रेजों ने जब आधुनिक डाक व्यवस्था 1854 में खड़ी की तो सालाना एक करोड़ बीस लाख चिट्ठियों की आवाजाही थी जो बढ़ते-बढ़ते 1550 करोड़ तक पहुँच गई थी। उस वक्त देश कई हिस्सों में बंटा था और ये राजवाड़े की मर्जी पर निर्भर करता था कि वो डाक सेवा लागू करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन धीरे-धीरे डाक की अहमियत को सभी ने समझा और इसका विस्तार या नेटवर्क बढ़ने लगा। 1926 में नासिक में डाक टिकटों की छपाई का काम जब शुरू हुआ तो भारतीय डाक को नई ऊर्जा मिली। 21 नवंबर, 1947 को आजाद भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद कई वर्षों तक भारतीय डाक और भारतीय समाज एक दूसरे के भीतर इस कदर घुल-मिल गए कि एक के बगैर दूसरे की कल्पना भी मुश्किल नजर आने लगी।

गौरतलब है कि आजादी के वक्त देश में कुल 23,344 डाकघर थे, इनमें 19,184 ग्रामीण इलाकों और 4,160 शहरी क्षेत्रों में विद्यमान थे। वर्तमान में देश में डाकघरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है। भारत में कुल 1 लाख 55 हजार 531 डाकघर हैं। गाँवों में इसका ढाँचा बहुत मजबूत है और करीब 90 फीसदी डाकघर गांवों में ही मौजूद हैं। भारत के कुल डाकघरों में ग्रामीण डाकघर 1,39,067 है, औसतन 21.56 वर्ग किमी के क्षेत्र में एक डाकघर है। एक डाकघर औसतन 7753 व्यक्तियों को सेवा दे रहा है। विदित हो कि भारतीय डाक में विभागीय कर्मचारियों की संख्या 1.84 लाख है, जबकि ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या करीब 2.5 लाख है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भले ही संचार क्रांति के बाद देश में व्यक्तिगत चिट्ठियाँ कम हुईं हों, लेकिन अभी भी सालाना करीब 635 करोड़ डाक सामग्रियाँ आ रही हैं जिनमें 568 करोड़ सामान्य चिट्ठियाँ हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जिसका इस संस्थान से कोई वास्ता न पड़ा हो, चाहे वह डाक, बैंकिंग सेवा, जीवन बीमा, मनी ऑर्डर, हो या फिर पोस्टल ऑर्डर, रिटेल सेवाएँ, स्पीड पोस्ट, मनरेगा की मजदूरी, पीपीएफ (Public Provident fund) और एनएससी (National Saving Certificate) हो। भारतीय डाक की सेवा सभी ने कभी न कभी जरूर ली है।

डाक सुधारों की दिशा में उठाये गए कदम

आजादी के कई वर्षों बाद तक डाक विभाग के कंधों पर देश के सूचना और संचार तंत्र का सबसे बड़ा जिम्मा था, इसके बावजूद शुरूआती दौर में यह विभाग सरकारी उपेक्षा का शिकार बना रहा। हालांकि जैसे-जैसे संचार क्षेत्र की अहमियत बढ़ती गई, सरकार को डाक सुधारों की दिशा में काम करने पर मजबूर होना पड़ा। सरकार द्वारा डाक सुधारों की दिशा में उठाये गए कदमों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- तेज डाक वितरण के जरिए 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर (Postal Index Number) यानी पिन कोड की शुरूआत की गई। संचार की बढ़ती अहमियत की वजह से 1985 में डाक और दूरसंचार विभाग को अलग-अलग कर दिया गया। इसके ठीक एक वर्ष बाद 1986 में स्पीड पोस्ट (Speed Post) सेवा की शुरूआत की गई।
- इसके बाद 1994 में मेट्रो, राजधानी, व्यापार चैनल, ईपीएस और वीसैट के जरिए मनी ऑर्डर भेजा जाने लगा।
- हाल ही में केन्द्र सरकार ने डाक विभाग को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इनमें आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सेवा में सुधार के लिए प्रोजेक्ट ऐरो (Project Arrow) और नेटवर्क सुधार के लिए डाक नेटवर्क का सर्वाधिक उपयोग योजना (एमएनओपी) और चिट्ठियों की तेज छटनी के लिए स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र अहम हैं।
- सभी प्रकार के पत्र, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और पार्सल के साथ-साथ मनी ऑर्डर के लिए ट्रैक (Track) और ट्रैस (Trace) सुविधा का भी विस्तार किया गया है।
- सरकार के मुताबिक 27,215 डाकघरों, डाक कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों को देश व्यापी वाइड एरिया नेटवर्क या वैन (Wide Area Network-WAN) से जोड़ा गया है।
- सरकार ने निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सेवा, इंस्टेंट मनी ऑर्डर और ई-ग्रीटिंग जैसी नई सेवाएँ भी शुरू की हैं।
- हाल ही में सरकार ने मोबाइल यूजर्स के लिए मोबाइल ऐप भी शुरू किया है।
- डाक विभाग को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank-IPPB) की शुरूआत की। 'आपका बैंक आपके द्वार' के नारे से शुरू हुआ आइपीपीबी आज देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुँच चुका है। वर्तमान में आइपीपीबी खातों की संख्या एक करोड़ से ज्यादा हो गई है और इससे डाकघर बचत के 20 करोड़ बैंक खातों को भी जोड़ा जा रहा है।
- आइपीपीबी की एक खूबी यह भी है कि इसके खातों से पीएलआई, आरपीएलआई, सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ और रिकरिंग डिपॉजिट के साथ दूसरी स्कीमों में डिजिटल भुगतान हो रहा है।

- डाक विभाग ने चुनिंदा शहरों में जीआईएस (Geographic Information Systems) मैपिंग के जरिए डाक वितरण की पहल भी शुरू की है। डाक विभाग आज म्युचुअल फंड (Mutual Fund) की रिटेलिंग, डाक जीवन बीमा और बैंकिंग क्षेत्र तक अपने पैर पसार चुका है।

चुनौतियाँ

तकनीक के दखल के बाद डाक विभाग की चुनौतियाँ काफी बढ़ी हैं, तकनीकी युग में चिट्ठी, पत्रों की दुनिया लगातार सिमटती जा रही है। वर्तमान में ई-मेल, एसएमएम (SMS) , फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में सेकेण्डों में पहुँचा जा सकता है, जिससे डाक प्रणाली में चुनौतियों का समावेश हुआ है। डाक विभाग को सरकार द्वारा काफी प्रोत्साहन देने के बादजूद इसके समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- मोबाइल फोन के विस्तार ने चिट्ठियों के सिलसिलों पर लगभग विराम सा लगा दिया है। अब लोगों की दूरी बस एक स्विच ऑन और क्लिक में सिमट गई है। इसके बाद लोग ई-जनरेशन में पहुँच गए हैं, जहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एसएमएस, फोन, वीडियो कॉलिंग और मुफ्त ऑडियो कॉलिंग की सुविधा है वहाँ डाक सेवा इसके सामने धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है।
- डाक विभाग में ज्यादातर चिट्ठियाँ या तो सरकारी दफ्तरों से आती हैं या फिर कंपनियों से। डाक विभाग नये-नये परिवर्तनों को तो अपना रहा है मगर फिर भी यह विभाग तकनीक के इस युग में अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रहा है।
- भारतीय डाक ने 1997-98 में 15 अरब 74 करोड़ चिट्ठियाँ बाँटी, 2006-07 में यह आंकड़ा घटकर 6 अरब 39 करोड़ रह गया। वर्ष 2012-13 में 6 अरब 5 करोड़ और 2013-14 में 6 अरब 8 करोड़ चिट्ठियां भारतीय डाक ने देशभर में पहुँचायीं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय डाक विभाग का राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है। साल 2016 में यह 150 फीसदी बढ़कर 6 हजार 7 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। वहीं 2019 में यह घाटा बढ़कर 15 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
- गौरतलब है कि कुछ वर्षो से पंजीकृत चिट्ठियों की संख्या में भी भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि साधारण डाक के जरिए आज भी अरबों चिट्ठियाँ भेजी जा रही हैं। इनमें दफ्तर से हुए पत्राचार की बड़ी भूमिका तो है मगर गैर सरकारी चिट्ठियों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम है।
- उदारीकरण के बाद कुरियर कंपनियों की बाढ़ आ गई, वैसे तो नियमों के तहत चिट्ठियों पर डाक विभाग का एकाधिकार है, लेकिन पैकेट के नाम पर बड़ी संख्या में चिट्ठियाँ कुरियर कंपनियाँ ले जा रही हैं। इसके अलावा तमाम सेवाओं पर डाक विभाग घाटा उठा रहा है जो पोस्टकार्ड 50 पैसे का है उस पर लिखी चिट्ठी को पहुँचाने में बारह रुपये पन्द्रह पैसे की लागत आती है। वहीं अंतर्देशीय पत्र की कीमत ढाई रुपये है लेकिन उसे पहुँचाने में बारह रुपये सात पैसे की लागत आती है।

आगे की राह

संचार और आइटी (Information Technology) क्रांति ने बेशक पत्रों या चिट्ठियों पर असर डाला है, मगर इसकी उपयोगिता समाप्त नहीं हुई है। पत्र जैसा संतोष न फोन दे सकता है और न ही कोई दूसरा साधन। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केन्द्रित है, अर्थात मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका रही है। इसलिए डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास भी हुए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल हुआ। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। व्यक्तिगत पत्राचार तो घटा है किन्तु व्यावसायिक पत्राचार के लिए डाक पर भरोसा बढ़ा है। वर्तमान डाक विभाग द्वारा पासपोर्ट व अन्य महत्वपूर्ण कागजात बनाये जाते हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से हर राज्य में पहुँचाए जाते हैं, इससे ही इसकी महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

वर्तमान में देखा जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय में हर रोज लगभग 5 हजार चिट्ठियाँ आती हैं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के पास तो रोज सैकड़ों की संख्या में पत्र आते हैं, इससे इस बात को बल मिलता है कि डाक हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए डाक विभाग को नये सिरे से मजबूत करने की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समय के साथ डाक की भूमिका बदल सकती है, किन्तु उसका महत्व समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए भारत सरकार को उन सभी क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है जिनमें डाक विभाग को समस्याएँ आ रही हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- बुनियादी ढाँचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

6. कच्चे तेल में उछाल और भारत पर उसका प्रभाव

चर्चा का कारण

वर्तमान समय में तेल के बाजार में उथल-पुथल की वजह से ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि कच्चे तेल की कीमत जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल पार कर जाएगी।हालाँकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खाड़ी देशों में हालात कैसे बनते हैं।

चूँकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था और खराब होगी। परिणामस्वरूप ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाले तेल के कारोबार को निशाना बना सकता है, जिससे कि तेल का उत्पादन और निर्यात प्रभावित होगा और इसकी कीमतों में वृद्धि होगी। विदित हो कि ऐसी स्थिति वर्ष 2008 के बाद देखी जा रही है।

परिचय

विश्वभर में कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार ईरान में ही है। इतना ही नहीं, ईरान एक ऐसा देश है जो अपने जीवाश्म ईंधन के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। यह ईरान की 440 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 15 फीसदी है। ईरान में

उत्पादित कच्चे तेल के दो सबसे बड़े आयातक चीन और भारत हैं जो ऐसी उभरती महाशक्तियाँ हैं जिन्हें अपने यहाँ त्वरित औद्योगिक विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल चाहिए।

पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि इस परिचर्चा की शुरूआत साल 2018 में उस वक्त हो गई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था।

जानकारों ने ये आशंका जतायी थी कि जल्द ही तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच सकती है। उन्होंने इसकी वजह ये बताई थी कि ईरान के कच्चे तेल और वेनेजुएला के कच्चे तेल का विकल्प तेल बाजार में मौजूद है ही नहीं। विश्लेषक यह भी कहते हैं कि सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देश ईरान और वेनेजुएला के तेल का विकल्प नहीं मुहैया करा सकते हैं। जल्द ही बाजार ने भी ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और तेल के दाम तेजी से चढ़ने लगे। कच्चे तेल के दो बड़े बाजार सूचकांकों वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट यानी WTI और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में एक दशक में पहली बार लगातार एक तिमाही तक बढ़ोतरी देखी गई। डब्ल्यूटीआई के दाम 73.46 प्रति बैरल पहुँच गए। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमतें 83.32 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छूने लगीं। कुछ ही दिनों के अंदर तेल के दाम और बढ़ गए। तब डब्ल्यूटीआई तेल 76 डॉलर प्रति बैरल का हो गया। वहीं ब्रेंट ने 86 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर लिया। ये पिछले चार साल में कच्चे तेल की कीमतों में आया सबसे बड़ा उछाल था। तेल के दाम में तेजी को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने कच्चे तेल के उत्पादक देशों से कहा कि वो तेल का उत्पादन बढ़ाएँ, ताकि कच्चे तेल के बाजार में स्थिरता आए।

लेकिन, तब तक कच्चे तेल के बाजार से ईरान और वेनेजुएला के तेल की उपलब्धता खत्म होने लगी थी। इसके बाद हालात में और गिरावट तब देखी गई, जब सऊदी अरब के अबकाइक और खुरैस तेल संयंत्रों पर ड्रोन से हमले हुए। तेल बाजार ने इन घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तेल संयंत्रों पर इन ड्रोन हमलों की वजह से सऊदी अरब के तेल के उत्पादन में रोजाना 57 लाख बैरल की कमी आ गई। आज कच्चे तेल के उत्पादन में आई इस कमी को पूरा करना सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं कच्चे तेल के दूसरे उत्पादक देश भी कच्चे तेल के बाजार में इतनी भारी कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

कच्चे तेल में उछाल के अन्य कारण एवं प्रभाव

कच्चे तेल के उत्पादन में आई भारी गिरावट तेल के बाजार में मची उथल-पुथल और कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह है, जिसके निम्न कारण रहे हैं-

- जिस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हुए ड्रोन हमले ने तेल के बाजार को और जबरदस्त झटका दिया।
- इसका नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमतों में तीस साल का सबसे बड़ा उछाल देखा गया। जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 20 प्रतिशत तक बढ़ कर 72 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। हालांकि बाजार बंद होते-होते इन में थोड़ी गिरावट देखी गई और ये 15 फीसद की बढ़त पर बंद हुईं। गिरावट के बावजूद ये उछाल पिछले चार महीनों में सबसे ज्यादा है।
- गौरतलब है कि आज अगर ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमला कर देता है, तो तेल के बाजार में पहले से बना हुआ तनाव और बढ़ सकता है। इससे तेल की कीमतें बढ़ कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती हैं क्योंकि दुनिया के बड़े तेल कारोबारी, तेल के व्यापार के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही निर्भर हैं।
- अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया में तेल के कारोबार का सबसे बड़ा रास्ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की एक तिहाई प्राकृतिक तरल गैस यानी एलएनजी गुजरती है। जबकि दुनिया के कुल तेल कारोबार का 20 फीसद इसी जल स्ट्रेट से होकर गुजरता है।
- इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते अविश्वास के माहौल ने सऊदी अरब और ईरान के बीच तनातनी के हालात और बिगाड़ दिए हैं। नतीजा ये हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की गुंजाइश और भी कम हो गई है।
- हाल के दिनों में अमेरिका, कच्चे तेल के नए निर्यातक देश के तौर पर उभरा है। लेकिन फिर भी वह तेल के बाजार में आई इस कमी की भरपाई नहीं कर सकता है।
- एक अन्य वजह माना जा रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका, दोनों ही देशों ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमलों के जोखिम को कम कर के आंका।
- खास तौर से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी अमेरिका और सऊदी अरब ने इन हमलों की आशंका को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितना लेना चाहिए था। ऐसे ड्रोन हमलों से पूरे इलाके पर जोखिम बढ़ गया है।
- विदित हो कि अब सभी तेल उत्पादक देशों को ऐसे गैर परंपरागत हमलों के लिए भी तैयार रहना होगा। इसका नतीजा ये होगा कि एशिया की बीमा कंपनियाँ, खाड़ी देशों से तेल लेकर आने वाले जहाजों का प्रीमियम बढ़ा देंगी। इसका बोझ भी तेल के आयातक देशों पर ही पड़ेगा, जो कि एक नई बात होगी।
- वहीं पूरे मध्य-पूर्व में ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ऐसा एक और हमला विश्व स्तर पर ऊर्जा संकट को जन्म दे सकता है क्योंकि दुनिया अभी भी स्वच्छ ईंधन के विकल्पों को पूरी तरह से अपना नहीं सकी है और अभी भी कच्चे तेल की खपत बड़े पैमाने पर हो रही है। ये बात ब्रिटिश पेट्रोलियम के एनर्जी आउटलुक 2019 में साफ तौर पर दिखी थी।

भारत की स्थिति

भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल आयात पर काफी हद तक निर्भर है। भारत में लगभग 80 फीसदी कच्चा तेल विदेश से आता है। ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है और वर्ष 2016-17 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 13 फीसदी का स्रोत ईरान ही था। उल्लेखनीय है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए भारत जैसे तेल के आयातक देश अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता कम कर रहे हैं और दूसरे देशों से तेल और गैस खरीद रहे हैं। इसके लिए भारत ने रूस और अमेरिका से ऊर्जा कारोबार को भी बढ़ाया है लेकिन, भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता अहम है क्योंकि फिलहाल मध्य-पूर्व के देश ही एशियाई बाजारों को तेल आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े निर्यातक हैं।

ओपेक देशों का रुख

तेल उत्पादक देशों यानी ओपेक का तेल उत्पादन दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तय करने का एक प्रमुख कारक है क्योंकि इन्हीं देशों के अतिरिक्त तेल उत्पादन से तेल की कीमतों में

स्थिरता लाई जा सकती है। अगर इन देशों की अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता सीमित ही रहती है, तो इससे तेल की कीमतों में उछाल आता है। विदित हो कि इसका असर उस वक्त से ही दिखना शुरू हो गया था, जब ओपेक देशों ने तेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया था और तेल की कीमतों में संतुलन लाने के लिए 12 लाख बैरल प्रति दिन तेल उत्पादन घटाने की घोषणा की थी। ताकि, तेल के बाजार में कच्चे तेल की अतिरिक्त उपलब्धता को कम कर के तेल के दाम बढ़ाने को प्रेरित कर सकें। फिलहाल ओपेक देश तेल के उत्पादन में इस कटौती पर कायम हैं।

गौरतलब है कि ओपेक देशों में सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब के पास ही अतिरिक्त तेल उत्पादन की क्षमता है। वो अपना रोजाना का तेल उत्पादन 15 से 20 लाख बैरल तक बढ़ाने की क्षमता रखता है जो सभी ओपेक देशों की अतिरिक्त तेल उत्पादन की कुल क्षमता से भी ज्यादा है क्योंकि, 2019 की दूसरी तिमाही तक बाकी के ओपेक देश मिलकर 21 लाख बैरल प्रति दिन ही अतिरिक्त तेल उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि सऊदी अरब को छोड़ दें तो बाकी के ओपेक देश कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और अंगोला मिलकर भी तेल के बाजार में आई इस कमी को शायद ही पूरा कर सकें। यानी आज बाजार में अतिरिक्त कच्चे तेल की उपलब्धता नहीं के बराबर है। ऐसे में तेल की सप्लाई में आई एक और कमी की चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया तैयार नहीं है।

अमेरिका की नीति

वहीं दूसरी तरफ इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने तेल के रणनीतिक भंडारों को खोला है। विदित हो कि यह अस्थाई विकल्प भी तब ही बाजार में उपलब्ध होगा जब अमेरिकी सरकार ये तय कर लेगी कि वो इन भंडारों से कितना तेल बाजार में जारी करेगी। उल्लेखनीय है कि इन दिक्कतों के चलते ही अमेरिका की शेल ऑयल कंपनियों को अपने तेल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। उन्हें वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट तेल से 15 डॉलर प्रति बैरल कम कीमत पर अपना पर्मियन तेल बेचना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार ने तेल सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में तेजी लाने का ऐलान तब जाकर किया, जब सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए।

भारत के पास विकल्प

तीन संभावित तरीकों पर ध्यान केंद्रित करके भारत विदेश से कच्चे तेल के प्रवाह से बुरी तरह प्रभावित होने से बच सकता है।

पहला तरीका यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से छूट हासिल करने के प्रयास किए जाएं। ऐसे में भारत आगे भी ईरान के साथ अपना व्यापार जारी रख सकेगा। यह छूट हासिल करने के लिए भारत को अमेरिका के समक्ष यह तथ्य सामने रखना होगा कि भारत ने पिछले दो वर्षों में ईरान से तेल आयात को काफी हद तक कम कर दिया है।

दूसरा तरीका यह है कि उन देशों से तेल आयात बढ़ाया जाए जो पहले से ही बड़ी मात्रा में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करते रहे हैं। इस मामले में उपयुक्त उदाहरण इराक, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कुवैत हैं। इन तीनों देशों ने खुद को विश्वसनीय व्यापार साझेदार साबित किया है और हाल के महीनों में भारत ने अपने तेल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वैसे तो संयुक्त अरब अमीरात से भारत में हुए आयात में पिछले वित्त वर्ष के दौरान कमी दर्ज की गई थी, लेकिन दोनों ही देशों के रणनीतिक और वित्तीय समुदायों ने निकट भविष्य में ज्यादा घनिष्ठ एवं सहयोगात्मक संबंध विकसित होने की जो आशा जताई है उससे इस संकट से बचने की संभावनाओं को काफी बल मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस बीच, इराक से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि अत्यंत उत्साहजनक नजर आती है, क्योंकि यह देश वर्ष 2017-18 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था।

भारत को इन सकारात्मक रुझानों से लाभ उठाने के लिए निश्चित तौर पर काम करना चाहिए और इसके साथ ही इन देशों से कच्चे तेल के प्रवाह में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी काम करना चाहिए।

इसी तरह भारत को पारंपरिक रूप से अपने सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब से तेल आपूर्ति में स्थिरता लाने की दिशा में भी ठोस काम करना चाहिए। वैसे तो सऊदी अरब से तेल आयात में पिछले दो वर्षों में लगभग 9 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है और यह चिंता का कारण तो है, लेकिन फिर भी इस ओर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए। खाड़ी देशों की विशाल तेल रिजर्व क्षमता को देखते हुए भारत में तेल प्रवाह में अचानक होने वाली कमी की भरपाई करने में इन देशों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

तीसरा संभावित तरीका यह हो सकता है कि नए एवं इच्छुक साझेदारों की तलाश की जाए और अल्पावधि में ही इन साझेदारों के साथ विश्वास एवं आपसी समझ का एक मजबूत रिश्ता बनाने की दिशा में समर्पित ढंग से काम किया जाए। इस दिशा में ओमान और संयुक्त राज्य अमेरिका उपयुक्त हो सकते हैं।

चुनौतियाँ

उपर्युक्त तरीकों में से किसी के भी कारगर साबित होने के मार्ग में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- पहली एवं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपने यहाँ तेल आयात में जितनी वृद्धि को आवश्यक मानता है वह किसी भी दृष्टि से मामूली नहीं है, इसलिए इन एशियाई देशों और किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाना जरूरी है जो अपने निर्यात में अच्छी-खासी बढ़ोतरी करना चाहते हैं।
- एक और बाधा नए साझेदारों के साथ ढुलाई संबंधी रियायतों और विस्तारित ऋण अदायगी अवधि के लिए सौदेबाजी करने के दौरान उत्पन्न हो सकती है। दरअसल, इस तरह की दोनों ही गारंटी ईरान ने भारत को दे रखी है। चूँकि आयात करने वाले देश के लिए अपने साझेदार से ऐसी शर्तों को मनवाना मुश्किल है, इसलिए ऐसे में ईरान के तेल को प्रतिस्थापित करने वाले स्रोत से भारत में होने वाला आयात महंगा हो सकता है।
- अमेरिका से शेल एवं किसी और देश से भारी क्रूड की खरीद का अनुपात तय करने का जो अन्य विकल्प है उससे भी जटिलताएँ बढ़ सकती हैं क्योंकि वैसी स्थिति में कई पार्टियों के साथ सौदेबाजी करनी होगी।
- एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती यह भी है कि भारत में सार्वजनिक तेल रिफाइनरियों की अपनी तकनीकी सीमाएं हैं। वैसे तो 'नेल्सन जटिलता सूचकांक' में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) जैसी रिफाइनिंग कंपनियों को काफी ऊंची रेटिंग मिलती है, लेकिन सार्वजनिक रिफाइनरियों की अनुकूलन क्षमता अकसर कम होती है।
- इन विशिष्ट चुनौतियों के अलावा यह भी एक बड़ा सवाल है कि भारत कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हालिया तेज उतार-चढ़ाव से निपटते हुए संबंधित वार्ताओं

और सौदेबाजी के बीच संतुलन कैसे स्थापित करेगा।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कच्चे तेल के बाजार में उथल-पुथल को रोका जाना समय की मांग हो गई है। इस दिशा में सभी देशों को पहल करने की जरूरत है विदित हो कि इस मुश्किल वक्त और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले रोकने का एलान किया है। अमेरिका ने इसका स्वागत भी किया है और वो सऊदी अरब को यमन के बागियों के साथ होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए राजी कर सकता है। इस शांति वार्ता को सऊदी अरब पर ड्रोन हमला होने से पहले ही अमेरिका ने शुरू किया था। भले ही ये मुश्किल है, लेकिन इस वार्ता के शुरू होने से ईरान के साथ तनाव कम करने में काफी राहत मिलेगी। अन्यथा इस बढ़ते तनाव का असर तबाही वाला होगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता के अलावा वैश्विक तेल बाजार पर भी असर डाल सकता है। अगर तनाव बढ़ा तो तमाम देश बिजली से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा हुआ तो आने वाले समय में ओपेक देशों की उपयोगिता और प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. 'मेक इन इंडिया' : एक मूल्यांकन

चर्चा का कारण

भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम को पाँच वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों के माध्यम से भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। इस लेख के माध्यम से हम 'मेक इन इंडिया' के सफर का विश्लेषण करेंगे।

परिचय

विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्द्धन के लिए सरकार ने 25 सितम्बर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरूआत की, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं विनिर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके।

'मेक इन इंडिया' मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नये क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। गौरतलब है कि 'मेक इन इंडिया' पहल के संबंध में देश एवं विदेशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। जापान, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने विभिन्न औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में भारत में निवेश करने हेतु अपना समर्थन दिखाया है।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य

- मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में प्रति वर्ष 12-14% वृद्धि करना।
- 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में 16% से 25% की वृद्धि करना।
- विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना।
- समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल का निर्माण करना।
- घरेलू मूल्य संवर्द्धन और निर्माण में तकनीकी गहराई में वृद्धि करना।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना।
- विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना।
- मेक इन इंडिया अभियान के लिए सरकार ने प्राथमिकता वाले 25 क्षेत्र चिह्नित किए हैं, जिन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कुछ प्रमुख क्षेत्र

- फूड प्रोसेसिंग, अक्षय ऊर्जा, आईटी और बीपीएम, सड़क और राजमार्ग, एविएशन (विमानन), चमड़ा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी,
- मीडिया और मनोरंजन, कपड़ा और वस्त्र, रसायन, खनन, थर्मल पावर, निर्माण, तेल और गैस, पर्यटन और हॉस्पिटेलिटी, रक्षा विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, कल्याण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बंदरगाह, रेलवे।

वर्तमान स्थिति

गौरतलब है कि भारत की 'मेक-इन इंडिया' को शुरू हुए पांच साल बीतने के बावजूद विनिर्माता कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मिसाल के तौर पर चीन से पलायन कर रही कंपनियां भारत में अपने पैर पसारने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जितनी दिलचस्पी वे वियतनाम जैसे छोटे से देश में ले रही हैं। विदित हो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2013-14 में 16 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 36 बिलियन डॉलर हो गया है, लेकिन इस उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद एफडीआई भारत के औद्योगिकीकरण में योगदान नहीं दे रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वास्तव में कम है। विदित हो कि 2017-18 में, यह 7 बिलियन डॉलर था जबकि 2014-15 में यह 9.6 बिलियन डॉलर था। इसके दूसरे तरफ सेवा क्षेत्रों में एफडीआई 23.5 बिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र के तीन गुना से अधिक है। मेक इन इंडिया औद्योगिक धरातल पर सफल अपेक्षाकृत नहीं हो पाया इसको लेकर निम्न तर्क दिए जा रहे है।

पहला, भारती में एफडीआई का एक बड़ा हिस्सा मॉरीशस स्थित शेल कंपनियों से आता है, जिसपर विशेषज्ञों और भारतीय कर अधिकारियों को संदेह है कि कैसे मॉरीशस जैसे देश विकसित राष्ट्र की तुलना में भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। इनमें से अधिकांश निवेश भारत का काला धन ही होता है जो 'राउंड ट्रिपिंग' के माध्यम से पुन: भारत में आ जाता है।

- दूसरा, भारतीय कारखानों की उत्पादकता कम है। मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार, "भारत के विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिक थाईलैंड और चीन के अपने समकक्षों की तुलना में औसतन लगभग चार और पाँच गुना कम उत्पादक हैं।" यह सिर्फ अपर्याप्त कौशल

के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि आधुनिक उपकरणों में निवेश करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों का आकार बहुत छोटा है। इन असफलताओं के बावजूद भी 'मेक इन इंडिया' भारत के लिए महत्व रखता है।

मेक इन इंडिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- बहुत ही थोड़े समय में सरकार ने पुराने ढांचे को नवीनतम ढांचे में बदल दिया है ताकि नवाचार और कौशल विकास को बढ़ाया जा सके। भारत ने अपनी 'व्यापार करने में आसानी' (Ease of doing business) की रैंकिंग को वर्तमान के 130 से सुधारने के लिए विश्व बैंक के साथ बैठकों का आयोजन करके विकास का सही ढांचा विकसित करने की दिशा में कई कदम उठाये हैं।
- 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि यहाँ के बने उत्पादों को विश्व के किसी भी कोने में बेचा जा सके।
- 'मेक इन इंडिया' अभियान में बढ़ोतरी से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि हो सकता है निर्यात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 16% का योगदान देता है और सरकार का लक्ष्य इसे 2020 तक 25% करना है।
- भारत के इस अभियान में उन युवा प्रतिभाओं की मदद करने की बात भी कही गयी है जो कि नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण हैं। ऐसे लोगों को सरकार मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता दे रही है जिससे कि देश में नयी स्टार्टअप कंपनियों का विकास हो सके जो कि आगे चलकर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।
- इस प्रोजेक्ट में कुल 25 क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा जिससे लगभग दस मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यदि इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में कई और क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी जो कि कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था को समृद्धि के मार्ग पर चलाकर चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देगा।
- वर्तमान समय में 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के चलते विदेशी रक्षा कंपनियां अपने कारखानों को भारत में स्थापित करने पर विचार कर रही हैं। इसी क्रम में हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मेड इन इंडिया एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें (Anti-Tank Missiles) शामिल हैं, जो दुश्मन के टैंकों को नेस्तनाबूत करने में सक्षम हैं।वही इससे पूर्व अगस्त 2015 में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमान के 332 पार्ट्स की तकनीक को भारत को स्थानांतरित करने के लिए रूस के इरकुट कॉर्प (Irkut Corp) कम्पनी से वार्ता शुरू की। भारत में रक्षा मंत्रालय फाइटिंग इन्फैंट्री कॉम्बोट वाहन (एफआईसीवी) के डिजाइन और निर्माण के लिए 600 अरब डॉलर (यूएस 9.3 बिलियन) अनुबंध की नीलामी कर रहा है।

मेक इन इंडिया की सफलता की सम्भावना

'मेक इन इंडिया' को शुरू हुए लगभग पाँच साल से ज्यादा समय हो गया है। यह अभियान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हालाँकि हाल में इसकी खामियाँ सामने आयी है, बावजूद इसके अभियान का अगर सही रूप से क्रियान्वयन किया जाए तो इसके सफल होने की काफी गुंजाइश है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई देशी-विदेशी कंपनियों ने 'मेक इन इंडिया' में दिलचस्पी दिखाई है। इससे देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तो इजाफा हुआ ही है, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

- जॉब प्लेसमेंट फर्मों का अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इनसे जुड़े सेक्टर्स में इनवेस्टमेंट बढ़ने से 2022 तक करीब 10 करोड़ नई नौकरियाँ बढ़ेगी।
- मेक इन इंडिया अभियान में स्किल डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना से भी नौकरियों की संख्या बढ़ने का अनुमान है।
- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है और उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2020 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन जाएगा।
- वहीं अनुमानतः अगले दो तीन दशकों तक यहां की जनसंख्या वृद्धि उद्योगों के अनुकूल हो जायेगी।
- भारत में अन्य देशों के मुकाबले जनशक्ति पर कम लागत भी इसकी सफलता को सुनिश्चित करती है।
- इसके अलावा भारत के व्यावसायिक घराने उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से, भरोसेमंद तरीकों से और व्यावसायिक रूप से काम कर रहे हैं।
- भारत के घरेलू बाजार में उपभोक्तावाद प्रवृत्ति की हवा चल रही है जो विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
- भारत में तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताएँ मौजूद हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों का हाथ है।
- विदेशी निवेशकों के लिए भारत का बाजार खुला हुआ है और यह काफी अच्छी तरह से विनियमित भी है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत नए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में 1500 से 2000 तक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का कार्यक्रम चल रहा है।
- इस परियोजना पर 2000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। सरकार ने हर साल लगभग तीन लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा।

चुनौतियाँ

'मेक इन इंडिया' अभियान अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है लेकिन इसके मार्ग में कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिस कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। इन चुनौतियों का जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- 'मेक इन इंडिया' का सबसे प्रमुख उद्देश्य निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना है। लेकिन दोनों मसलों पर ये कार्यक्रम उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा।
- 'मेक इन इंडिया' की सफलता के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन योजना का असर उस स्तर पर नहीं हुआ जितना सरकार ने दावा किया था।
- विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग

और जीडीपी में वृद्धि दर से रोजगार पैदा करने में मदद नहीं मिलेगी। भारत सबसे तेज गति वाले अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन रोजगार सृजन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी रोजगार सृजन के तरीके खोजने होंगे और रोजगार बढ़ाने के दूसरे उपाय भी ढूंढने होंगे।

- मेक इन इंडिया के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भारत में रेल-सड़क यातायात और अपर्याप्त बंदरगाह भी है। अगर भारत में निर्माण इकाइयां स्थापित की जाती हैं, तो उत्पाद को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए जरूरी ट्रांसपोर्ट सुविधा का बंदोबस्त करना जरूरी हो जाता है।
- वहीं भारत का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
- सभी राज्य निवेश चाहते हैं। लेकिन निवेश के रास्ते में एक बड़ी समस्या राज्यों और केंद्र की नीतियों की जटिलता है।
- सरकारों का नौकरशाही नजरिया और बड़े पैमाने पर फैला भ्रष्टाचार भी एक समस्या है।
- भ्रष्टाचार के अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या लाल फीताशाही है। दरअसल 'मेक इन इंडिया' निवेशक जटिल प्रक्रियाओं के जाल में फंसकर अपना समय गँवाना पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा सरकार को ऐसी आसान व्यवस्थाएँ बनानी होंगी और 'सिंगल विंडो सिस्टम्स' पर जोर देना होगा।
- भारत में पिछले कई वर्षो से टैक्स व्यवस्था में सुधार की मांग की जा रही है। अब तक टेलीकॉम से लेकर कई अन्य क्षेत्र की कंपनियां टैक्स संबंधी मामलों के सिलसिले में भारतीय अदालतों के चक्कर काट चुकी हैं। ऐसे में आसान और पारदर्शी टैक्स व्यवस्था की जरूरत है।
- देश का श्रम कानून 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए सहायक साबित नहीं हो पा रहा है। विदित हो कि अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970 के तहत कर्मचारी के नौकरी विवरण या कर्तव्यों में सरल बदलाव के लिए सरकार और कर्मचारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- आसान व्यापार करने के सूचकांक' में भारत का स्थान नीचे होना एक अन्य चुनौती बनी हुई है।।
- चीन के 'मेक इन चाईना' अभियान से भारत की प्रतिस्पर्द्धा चल रही है लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में अभी भी चीन का वर्चस्व बना हुआ है।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 'मेक इन इंडिया' एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरूआत की है। इस पहल ने भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नयी डी-लाइसेंसिंग और ढील के उपायों से जटिलता को कम करने और समग्र प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता काफी बढ़ी हैं।

अब जब व्यापार करने की बात आती है तो भारत काफी कुछ प्रदान करता है। अब यह ऐसे सभी निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करता है जो स्थिर अर्थव्यवस्था और आकर्षक व्यवसाय के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद जो चुनौतियाँ बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित किया जाना भी जरूरी है। इसके लिए न सिर्फ सरकारी प्रयास काफी है बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयासों की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 और भारतः एक विश्लेषण

प्र. 'वैश्विक भूख सूचकांक' में भारत की रैंकिंग में सुधार न हो पाने के कारणों की चर्चा करें तथा इस संदर्भ में देश के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को भी रेखांकित करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति अनुसंधान संस्था (IFPRI) ने 14वां 'वैश्विक भूख सूचकांक' जारी किया है। भारत 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर है।

'वैश्विक भूख सूचकांक' रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- वैश्विक स्तर पर भूख सूचकांक में प्रथम तीन स्थान प्राप्तकर्ता देश बेलारुस, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का बाल निर्बलता अनुपात 20.8% है जो कि किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है।

भारत रैंक में क्यों सुधार नहीं कर पा रहा है?

- वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार न होने का एक कारण जलवायु में लगातार परिवर्तन भी है। इसका जिक्र इस सूचकांक में भी किया गया है। चरम मौसम की स्थिति आने से बीमारी में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा पर संकट, हिंसक संघर्ष में वृद्धि देखी जा रही है। इन परिस्थितियों के लिये सर्वाधिक सुभेद्य वर्ग बच्चे ही हैं जिन पर तीव्रता से, अधिक घातक प्रभाव पड़ता है।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

- सरकार द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक में भारतीय रैंक को सुधारने के लिये कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे मिड-डे मिल योजना, जिसके तहत प्रत्येक बच्चे को उसके विद्यालय में पर्याप्त पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को 1975 से चलाया जा रहा है। जिसमें बच्चों में पोषण, उसकी देखभाल, मृत्युदर को कम करना, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना तथा अन्य बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है। यह भारत का बच्चों के विकास को बनाये रखने के लिये सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- जननी सुरक्षा योजना जो न केवल गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव देने की सुविधा प्रदान करती है बल्कि इसके तहत निःशुल्क अस्पताल की सुविधा, न्यूनतम धन राशि एवं बच्चे के जन्म के बाद उसकी चिकित्सीय जाँच की सुविधा भी देती है ताकि महिला एवं बच्चे दोनों को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखा जा सके।

आगे की राह

- सरकार द्वारा सुभेद्य लोगों के लिये लगातार कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद भारत पिछले पाँच दशकों में लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर भारत जो कि वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। यू.एन की रिपोर्ट के मुताबिक 0-14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की कुल संख्या 26.16% है। ■

2. भारत में एचआईवी का संकट और इसका समाधान

प्र. पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम, जो अपनी खुबसूरती के लिए जाना जाता है कुछ वर्षों से एड्स के फैलाव में अव्वल होता जा रहा है। इसके कारणों को बताते हुए सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए किये गये प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में मिजोरम स्टेट 'एड्स नियंत्रण सोसायटी' (एमएसएसीएस) के अनुसार भारत में मिजोरम में सबसे ज्यादा एचआईवी एड्स (HIV AIDS) से पीड़ित मरीज पाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- मिजोरम स्टेट 'एडस नियंत्रण सोसाइटी' ने इंडियन एचआईवी एस्टिमेशन्स 2017 टेक्निकल रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मिजोरम एचआईवी संक्रमण के मामले में देश में पहले स्थान पर है। यहां जिन लोगों के खून के नमूनों की जांच की गई उनमें से 2.04 प्रतिशत लोग इससे पीड़ित थे।

मिजोरम में एड्स के मरीजों में वृद्धि का कारण

- राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आँकड़ों के मुताबिक मिजोरम में असुरक्षित यौन संबंध इसकी सबसे बड़ी वजह है। चूँकि मिजोरम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसकी सीमाएँ पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। परिणामस्वरूप इन देशों से कई तरह के अवैध व्यापार होते हैं जिससे कि मिजोरम में एड्स की समस्या बढ़ती जा रही है।

सरकारी प्रयास

- बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से सटे इस राज्य में एचआईवी का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं जो महीने में 25 दिन खुले रहते हैं। इन केंद्रों पर रोजाना एचआईवी/एड्स

के नौ नए मामले पहुंच रहे हैं। मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा. लालथेंगलियानी बताती हैं, "पूरे राज्य में 44 ऐसे केंद्र हैं जहाँ इस बीमारी की जांच और पुष्टि की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्य में एचआईवी का पहला मामला 1990 में सामने आया था।"

आगे की राह

- एड्स भारत के लिए सिर्फ मिजोरम या उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे भारत की समस्या है। यह बीमारी उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूरब से लेकर पश्चिम सभी जगह बढ़ रही है, इस बीमारी की वजह जो कुछ भी हो, ऐसे लाइलाज बीमारियों के खात्मे के लिए देश के स्तर पर प्रयास तो करना ही चाहिए। ■

3. भारत में खाद्य अपमिश्रण एवं संदूषण

प्र. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बताते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के लिए एक एडवायजरी जारी की जिसमे कहा गया कि अगर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो साल 2025 तक देश की करीब 87 फीसदी आबादी कैंसर की चपेट में होगी।

मिलावट का प्रभाव

- वर्तमान समय में मिलावट का सबसे अधिक कुप्रभाव हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। अनेक स्वार्थी उत्पादक एवं व्यापारी कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य सामाग्री में अनेक सस्ते अवयवों की मिलावट कर रहे हैं, स्मरणीय हो कि शरीर के पोषण के लिए हमें खाद्य पदार्थों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन् 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (पीएफए एक्ट 1954) लागू किया गया। उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है।
- विदित हो कि आजकल दूध में हो रही मिलावट को देखते हुए इसे रोकने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India) ने 1 जनवरी 2020 से एक नया नियम बनाने जा रही है जिसके अनुसार अब संगठित क्षेत्र के दूध कंपनियां जैसे मदर डेरी (Mother Dairy), अमूल (AMUL), पारस (Paras) को भी अपने दूध के सैंपल (Milk Sample) की जाँच FSSAI की लैब में कराना होगा।

चुनौतियाँ

- मिलावट रोकने के लिए कानून केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन पालन राज्य की एजेंसियों को करवाना होता है। राज्य का खाद्य विभाग, नगर निगम, पुलिस, एफएसएसएआई का जो राज्य कार्यालय है, उनके जिम्मे कानून का अनुपालन करवाना होता है। लेकिन, इन महकमों में इतना भ्रष्टाचार है कि अधिकारी कानून का डर दिखाकर वसूली करते हैं। वे सैंपल इकट्ठा कर उनकी जांच नहीं करवाते।

सुझाव

- आम लोगों से हर साल खाद्य सुरक्षा मानकों और उपलब्ध सामग्रियों पर रायशुमारी की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए।
- एफएसएसएआई के कामकाज पर भी ऐसा ही सर्वे हर साल किया जाना चाहिए। इसमें सरकार को कोई विशेष खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे यह तय हो जाएगा कि एफएसएसएआई आखिर क्यों ठीक काम नहीं कर पा रही है? एफएसएसएआई के इंस्पेक्टरों और लेबोरेटरियों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय की जाए।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि खाद्य पदार्थों मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और इसका रोकथाम के लिए न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हमारी भावी पीढ़ी स्वच्छ और मिलावट रहित खाद्य पदार्थों का सेवन कर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। ■

4. तुर्की–सीरिया संकटः एक अवलोकन

प्र. हाल ही में तुर्की द्वारा कुर्दों पर किये गये हमले ने किस प्रकार की चुनौतियों को उत्पन्न किया है? इस संघर्ष की समाप्ति हेतु विश्व बिरादरी (भारत सहित) की क्या भूमिका हो सकती है? चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सीरिया के उत्तर-पूर्व क्षेत्र और तुर्की के सीमाई क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात तुर्की ने इन क्षेत्रों में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की है, जिसे उसने 'ऑपरेशन पीस स्प्रिंग' (Operation Peace Spring) नाम दिया है।

परिचय

- सीरिया से आतंकवाद को खत्म करने व आइएस को हराने के लिए यूएसए के प्रयासों से सन् 2015 में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (SDF) का गठन हुआ। एसडीएफ कई समूहों का एक गठबंधन है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी 'पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट' (इसे YPG के नाम से भी जाना जाता है) की है।

कुर्द एवं तुर्की संघर्ष

- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि के दौरान कुर्द लोगों ने एक नये कुर्दिस्तान के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा था। इसमें कहा गया था कि आधुनिक तुर्की, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों को शामिल करके

कुर्दों के लिए एक कुर्दिस्तान नामक देश का गठन किया जाये। इसके पश्चात् 1920 की सेव्रेस की संधि (Treaty of Serveres) में पश्चिमी देशों ने कुछ हद तक कुर्दों की माँग पर विचार किया और पश्चिम एशिया में कुछ क्षेत्र को कुर्दिस्तान हेतु निर्धारित किया, लेकिन बाद में कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिक तुर्की का गठन हुआ और तुर्की ने किसी भी तरह के कुर्दिस्तान की माँग को सिरे से खारिज कर दिया।

वैश्विक प्रतिक्रिया

- अमेरिका सहित विश्व के अन्य लोग इस संघर्ष के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि अमेरिकी सरकार ने सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से अचानक सेना वापस बुला ली, जिससे तुर्की को सैन्य कार्रवाई का मौका मिल गया। अमेरिका को चाहिए था कि इस क्षेत्र से धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से सेना की वापसी सुनिश्चित की जाती ताकि वहाँ शांति और स्थायित्व के लिए समय मिल पाता।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने तुर्की की तरफ से सीरिया के पूर्वोत्तर हिस्से में की जा रही अकारण सैन्य कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत का कहना है कि तुर्की की इस कार्रवाई से न सिर्फ सीरिया के उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शांति व स्थिरता में बाधा आयेगी बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई भी कमजोर पड़ेगी। तुर्की की सैन्य कार्रवाई सीरिया की संप्रभुता पर चोट है, अत: किसी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर कार्रवाई से बचना चाहिए।

आगे की राह

- अमेरिका सहित पूरी विश्व बिरादरी को तुर्की पर दबाव बनाने की आवश्यकता है ताकि कुर्दों के मानव अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। अमेरिका को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक स्थायी संघर्ष विराम समझौता कराना होगा और सीरिया के उत्तर-पूर्व में वहाँ के मूल निवासियों की पुनर्वापसी सुनिश्चित करानी होगी। ■

5. भारतीय डाक सेवा: अब तक की यात्रा

प्र. भारत में डाक ने संचार प्रणाली में अहम योगदान दिया है, किंतु तकनीक के इस युग में यह पिछड़ता जा रहा है। चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस (World Post Day) 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को डाक विभाग के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

क्यों मनाया जाता है विश्व डाक दिवस

- विश्व डाक दिवस उन संदेश वाहकों को याद करने का दिन है जो मोबाइल और वीडियो कॉल से पहले के जमाने से हमारे संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाते थे। इस दिवस का मकसद रोजमर्रा की जिंदगी और समाज के बीच रिश्ते मजबूत करने में डाक विभाग की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

भारतीय डाक प्रणाली का विस्तार

- 200 वर्षों से ज्यादा पुरानी भारतीय डाक दुनिया की डाक प्रणालियों में अव्वल है। पूरी दुनिया में या तो डाकघर बंद हो रहे हैं या संचार क्रांति के कारण सिमट रहे हैं, लेकिन भारतीय डाक का लगातार विस्तार हो रहा है। आज भी ये पूरे देश की संचार व्यवस्था की धड़कन बनी हुई है।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भले ही संचार क्रांति के बाद देश में व्यक्तिगत चिट्ठियाँ कम हुई हों, लेकिन अभी भी सालाना करीब 635 करोड़ डाक सामग्रियाँ आ रही हैं जिनमें 568 करोड़ सामान्य चिट्ठियाँ हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जिसका इस संस्थान से कोई वास्ता न पड़ा हो, चाहे वह डाक, बैंकिंग सेवा, जीवन बीमा, मनी ऑर्डर, हो या फिर पोस्टल ऑर्डर, रिटेल सेवाएँ, स्पीड पोस्ट, मनरेगा की मजदूरी, पीपीएफ (Public Provident fund) और एनएससी (National Saving Certificate) हो। भारतीय डाक की सेवा सभी ने कभी न कभी जरूर ली है।

डाक सुधारों की दिशा में उठाये गए कदम

- तेज डाक वितरण के जरिए 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर (Postal Index Number) यानी पिन कोड की शुरूआत की गई। संचार की बढ़ती अहमियत की वजह से 1985 में डाक और दूरसंचार विभाग को अलग-अलग कर दिया गया। इसके ठीक एक वर्ष बाद 1986 में स्पीड पोस्ट (Speed Post) सेवा की शुरूआत की गई।
- हाल ही में केन्द्र सरकार ने डाक विभाग को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इनमें आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सेवा में सुधार के लिए प्रोजेक्ट ऐरो (Project Arrow) और नेटवर्क सुधार के लिए डाक नेटवर्क का सर्वाधिक उपयोग योजना (एमएनओपी) और चिट्ठियों की तेज छटनी के लिए स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र अहम हैं।

चुनौतियाँ

- भारतीय डाक ने 1997-98 में 15 अरब 74 करोड़ चिट्ठियाँ बाँटी, 2006-07 में यह आंकड़ा घटकर 6 अरब 39 करोड़ रह गया। वर्ष 2012-13 में 6 अरब 5 करोड़ और 2013-14 में 6 अरब 8 करोड़ चिट्ठियां भारतीय डाक ने देशभर में पहुँचायीं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय डाक विभाग का राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है। साल 2016 में यह 150 फीसदी बढ़कर 6 हजार 7 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। वहीं 2019 में यह घाटा बढ़कर 15 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

आगे की राह

- संचार और आइटी (Information Technology) क्रांति ने बेशक पत्रों या चिट्ठियों पर असर डाला है, मगर इसकी उपयोगिता समाप्त नहीं हुई है। पत्र जैसा संतोष न फोन दे सकता है और न ही कोई दूसरा साधन। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केन्द्रित है, अर्थात मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका रही है। ■

6. कच्चे तेल में उछाल और भारत पर उसका प्रभाव

प्र. हाल ही में तेल बाजार में आयी उथल-पुथल के कारणों को बताते हुए इस संदर्भ में संभावित विकल्पों पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- वर्तमान समय में तेल के बाजार में उथल-पुथल की वजह से ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि कच्चे तेल की कीमत जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल पार कर जाएगी। हालाँकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खाड़ी देशों में हालात कैसे बनते हैं। चूँकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था और खराब होगी।

कच्चे तेल में उछाल के अन्य कारण एवं प्रभाव

- जिस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हुए ड्रोन हमले ने तेल के बाजार को और जबरदस्त झटका दिया।
- इसका नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमतों में तीस साल का सबसे बड़ा उछाल देखा गया। जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 20 प्रतिशत तक बढ़ कर 72 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं।

भारत की स्थिति

- भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल आयात पर काफी हद तक निर्भर है। भारत में लगभग 80 फीसदी कच्चा तेल विदेश से आता है। ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है और वर्ष 2016-17 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 13 फीसदी का स्रोत ईरान ही था।

अमेरिका की नीति

- वहीं दूसरी तरफ इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने तेल के रणनीतिक भंडारों को खोला है। विदित हो कि यह अस्थाई विकल्प भी तब ही बाजार में उपलब्ध होगा जब अमेरिकी सरकार ये तय कर लेगी कि वो इन भंडारों से कितना तेल बाजार में जारी करेगी।

चुनौतियाँ

- पहली एवं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपने यहाँ तेल आयात में जितनी वृद्धि को आवश्यक मानता है वह किसी भी दृष्टि से मामूली नहीं है, इसलिए इन एशियाई देशों और किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाना जरूरी है जो अपने निर्यात में अच्छी-खासी बढ़ोतरी करना चाहते हैं।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कच्चे तेल के बाजार में उथल-पुथल को रोका जाना समय की मांग हो गई है। इस दिशा में सभी देशों को पहल करने की जरूरत है विदित हो कि इस मुश्किल वक्त और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले रोकने का एलान किया है। ■

7. 'मेक इन इंडिया' : एक मूल्यांकन

प्र. 'मेक इन इंडिया' अभियान से आप क्या समझते हैं? इसकी सफलताओं की संभावना को बताते हुए इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम को पाँच वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों के माध्यम से भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है।

परिचय

- 'मेक इन इंडिया' मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नये क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य

- 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में 16% से 25% की वृद्धि करना।
- विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना।

मेक इन इंडिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- बहुत ही थोड़े समय में सरकार ने पुराने ढांचे को नवीनतम ढांचे में बदल दिया है ताकि नवाचार और कौशल विकास को बढ़ाया जा सके। भारत ने अपनी 'व्यापार करने में आसानी' (Ease of doing business) की रैंकिंग को वर्तमान के 130 से सुधारने के लिए विश्व बैंक के साथ बैठकों का आयोजन करके विकास का सही ढांचा विकसित करने की दिशा में कई कदम उठाये हैं।

चुनौतियाँ

- 'मेक इन इंडिया' अभियान अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है लेकिन इसके मार्ग में कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिस कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। इन चुनौतियों का जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-
  - 'मेक इन इंडिया' का सबसे प्रमुख उद्देश्य निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना है। लेकिन दोनों मसलों पर ये कार्यक्रम उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 'मेक इन इंडिया' एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरूआत की है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

गोल (GOAL) कार्यक्रम

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय महिलाओं हेतु 'गोल' (जीओएएल-गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) के दूसरे चरण की घोषणा की।

गोल कार्यक्रम क्या है

2.1 गोल (GOAL) कार्यक्रम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का है, इसका उद्देश्य देशभर की जनजातीय युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

3.1 कार्यक्रम 'गोल' के जरिए वंचित युवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार, फैशन और कला क्षेत्रों के वरिष्ठ विशेषज्ञों से जोड़ा जाता है, जिससे कि वे डिजिटल और जीवन कौशल सीख सकें।

3.2 कार्यक्रम के दूसरे चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक भारत के जनजातीय बहुल जिलों में करीब पाँच हजार युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

3.3 'गोल' कार्यक्रम के इस साझेदारी के जरिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सीमांत युवा महिलाओं का प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में मार्गदर्शन किया जायेगा।

3.4 इस कार्यक्रम में 125 से अधिक युवा महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत मार्च 2019 में हुई थी।

3.5 इनमें से अधिकतर महिलाएं अपने समुदायों की समस्याओं को उजागर करने हेतु इंटरनेट का उपयोग करती हैं तथा इन सभी महिलाओं ने अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने की इच्छा भी व्यक्त की।

महत्त्व

4.1 फेसबुक महिलाओं की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाकर डिजिटल लैंगिक अंतराल को कम करने हेतु प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम इसलिए अहम है, क्योंकि इसके माध्यम से युवा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का काम किया जाता है।

4.2 उन सभी महिलाओं को जो अपने कौशल को उन्नत करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपनी आजीविका उत्थान करने की इच्छा रखते हैं, इस पहल का लाभ उठा सकती हैं।

4.3 इस कार्यक्रम से जनजातीय क्षेत्रों की युवा महिलाओं को अपना कौशल विकास करने में सहायता मिलेगी। नीति आयोग इन प्रतिभाशाली महिलाओं को अपने प्रयासों में सफल बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

4.4 यह कार्यक्रम सक्रिय रूप से नेतृत्व क्षमता का निर्माण करने हेतु इन युवा आदिवासी महिलाओं का समर्थन करता है और उन्हें चैंपियन बनने और दूसरों के साथ अपनी सीख साझा करने में मदद करता है।

नीति आयोग के प्रयास

5.1 नीति आयोग ने कहा कि इस घोषणा से जनजातीय क्षेत्रों की युवा महिलाओं को अपना कौशल विकास करने में मदद मिलेगी। साथ ही नीति आयोग इन प्रतिभाशाली महिलाओं को अपने प्रयासों में सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.2 इसके अलावा नीति आयोग महिलाओं की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाकर डिजिटल लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.3 भारत सरकार का प्रयास है कि समाज के सभी वर्ग देश की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में हिस्सेदारी करें। भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों को, पिछले छह दशकों में कार्यान्वित विकास परियोजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला है इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हैं।

भारत में जनजातीय जनसंख्या

6.1 2011 की जनगणना के आँकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 104 मिलियन आदिवासी लोग रह रहे हैं।

6.2 अधिकांश आदिवासी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में रह रहे हैं।

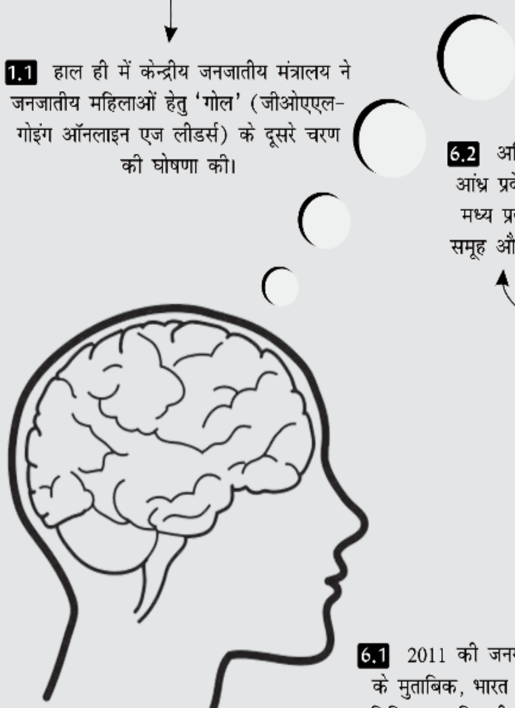

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में नीति आयोग ने वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज (नवप्रवर्तन के आधार पर) पर राज्यों की रैंकिंग जारी की है जिसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है।

नवाचार सूचकांक का आधार

2.1 नवप्रवर्तन के मामले में रैंकिंग तीन श्रेणियों जैसे बड़े राज्य, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों/और छोटे राज्य के अंतर्गत की गयी है।

2.2 इस सूचकांक के निर्माण के लिए पाँच सक्षम बनाने वाले पैमानों और दो प्रदर्शन के पैमानों पर राज्यों को परखा गया। सक्षम बनाने वाले पैमानों में मानव संसाधन, निवेश, कारोबार का माहौल, सुरक्षा और कानूनी वातावरण को रखा गया था। वहीं, ज्ञान के उत्पादन और ज्ञान के प्रसार को प्रदर्शन के पैमानों में रखा गया था।

नवाचार सूचकांक की जरूरत क्यों

3.1 देश के सभी राज्यों की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति भिन्न हैं। जब केन्द्र सरकार कोई योजना बनाती है तो कई बार किसी राज्य के लिए वह उतना फायदेमंद नहीं हो पाता जितनी उम्मीद होती है।

3.2 नवाचार सूचकांक के जरिए राज्यों का मजबूत और कमजोर पक्ष सामने आएगा। इससे जरूरत के मुताबिक नीति बनाने में मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

4.1 नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक (35.65 अंक) पहले नंबर पर आया है। इसमें दूसरे स्थान पर तमिलनाडु (32.98 अंक) जबकि महाराष्ट्र (29.93 अंक) तीसरे स्थान पर काबिज है।

4.2 22.06 अंक के साथ तेलंगाना चौथे स्थान पर है जबकि 20.55 अंक के साथ हरियाणा पांचवे स्थान पर है। केरल 0.58 अंक पाकर छठे स्थान पर है जबकि उत्तर प्रदेश 10.08 अंक के साथ सातवें स्थान पर है।

4.3 वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार इंडिया इनोवेशन में सबसे नीचे झारखंड (6.20 अंक) है। केंद्र शासित और छोटे प्रदेशों की सूची में पहला स्थान दिल्ली (42.98 अंक) को मिला है।

4.4 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर सिक्किम, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा है।

4.5 इस सूची में केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान का चंडीगढ़ है, जिसे 27.97 अंक मिला है। गोवा 22.49 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है जबकि 13.94 अंक के साथ पुद्दुचेरी चौथे स्थान पर।

क्या है नवाचार के मायने

5.1 इसका मतलब है नई पहल। इसके तहत यह देखा जाता है कि कौन राज्य किस क्षेत्र में और क्यों बेहतर कर रहा है। वहाँ राज्य के संसाधन, तकनीक और मानव संसाधन के बीच कैसा तालमेल है।

5.2 इसके लिए उसने किस तरह की मदद ली और उनमें किस तरह की चुनौतियाँ सामने आईं और उसे कहां तक हल करने में सफल रहा।

5.3 साथ ही इसका वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ा। नवाचार में निवेशक, शोधकर्ता और आविष्कारक सभी को एक मंच मिलता है।

सुझाव

6.1 एक देश के लिये प्रभावी रूप से नीति तैयार करने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर नवप्रवर्तन की स्थिति को समझने की जरूरत है। केवल राष्ट्रीय स्तर पर नीति पर्याप्त नहीं है।

6.2 प्रत्येक राज्य को अपने अनूठे संसाधनों और विशेषताओं के आधार पर जरूरतों के अनुसार अपनी नीति तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही नवप्रवर्तन हमेशा बदलाव और प्रगति का अगुवा रहा है क्योंकि इससे पुरानी और कुंद पड़ चुकी गतिविधियाँ खत्म होती हैं।

6.3 नीति आयोग ने देश में राज्य स्तर पर नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिये यह पहल की है। यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे राज्यों की तुलना में अपने प्रदर्शन को मानकीकृत बनाने में उपयोगी साबित होगा। इसके आधार पर वे अलग-अलग प्रदर्शन के कारणों को समझ पाएंगे और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिये बेहतर रणनीति तैयार कर सकेंगे

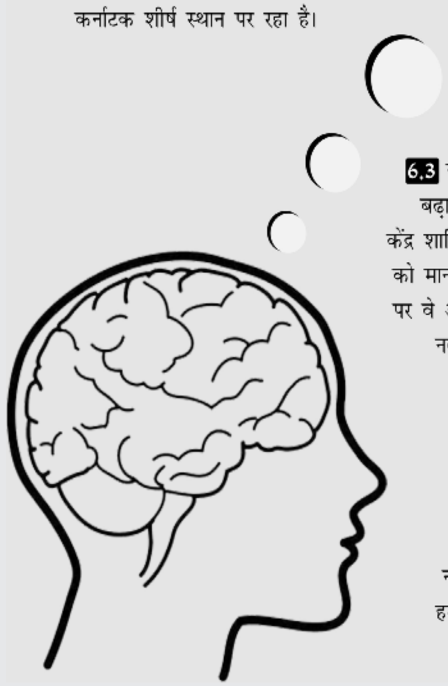

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, 2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने चालू वर्ष के दौरान भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। उसने भारत की विकास दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है जबकि अप्रैल में 7.3 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया था।

1.2 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार इस साल चीन के मुकाबले भारत की आर्थिक विकास दर में ज्यादा गिरावट आने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु

2.1 आइएमएफ ने अपने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि पिछले साल 2018 में भारत की विकास दर 6.8 फीसदी रही थी।

2.2 हालांकि अगले साल यानी 2020 में विकास दर सुधर कर 7 फीसदी होने का अनुमान है। आइएमएफ ने कहा कि अप्रैल 2019 के अनुमान के मुकाबले भारत की विकास दर इस साल 1.2 फीसदी और अगले साल 0.5 फीसदी धीमी रह सकती है। इससे घरेलू माँग उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर होने का पता चलता है।

2.3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट चौंकानी वाली है। इस रिपोर्ट में दुनियाभर में आर्थिक मंदी की आशंका जाहिर की गई है।

2.4 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का कहना है कि तरह-तरह के ट्रेड बैरियर और भू-राजनीतिक चिंताओं के चलते ग्लोबल इकोनॉमी एक 'सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाउन' के चक्र में फंसी है।

2.5 2017 के 3.8 फीसद की तुलना में ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर तीन फीसद पर पहुंचना चिंताजनक है।

2.6 यूरो क्षेत्र की विकास दर इस साल 1.2 फीसद और अगले साल 1.4 फीसद रहने का अनुमान है। जर्मन इकोनॉमी की विकास दर मात्र आधा फीसद रहेगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस साल 2.1 फीसद और अगले साल 2.4 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान है।

भारत के लिए सुझाव

3.1 वैश्विक परिस्थिति में भारत कम विकास दर के साथ भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि चीन की विकास दर 5.8 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है।

3.2 आइएमएफ के अनुसार भारत कॉर्पोरेट और पर्यावरण नियमन की अनिश्चितता के अलावा एनबीएफसी सेक्टर की अनिश्चितता से इस साल विकास दर सुस्त पड़ी।

3.3 भारत को चक्रीय कमजोरी दूर करने और भरोसा मजबूत करने के लिए मौद्रिक नीति और बड़े आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.4 मध्यम अवधि के दौरान बढ़ते सार्वजनिक कर्ज को नियंत्रित करने के लिए मजबूत वित्तीय अनुशासन की जरूरत है।

चीन और अमेरिका से उम्मीद

4.1 अगर अमेरिका और चीन 2018 की शुरूआत में एक-दूसरे पर लगाए गए शुल्क हटा दें, तो ग्लोबल इकोनॉमी में 2020 तक 0.8 फीसद की वृद्धि हो सकती है।

4.2 दरअसल, ऊंचे शुल्क और व्यापार नीतियों पर लंबे समय से अनिश्चितता के माहौल ने निवेश को नुकसान पहुँचाया है। कैपिटल गुड्स की मांग पर भी इससे असर पड़ा है।

4.3 आइएमएफ ने चेताया है कि ब्रेक्जिट के कारण उपजे संकट और कई तरह के ट्रेड प्रतिबंध से सप्लाई चेन और कारोबारियों के भरोसे पर बुरा असर पड़ा है।

4.4 आइएमएफ ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे भी अब दिखने लगे हैं। अगर समय रहते नहीं निपटा गया, तो भविष्य में इनका भी व्यापक असर देखने को मिल सकता है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

5.1 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक सर्वेक्षण है जिसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।

5.2 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

मणिपुर और त्रिपुरा का विलय

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के छोटे से राज्य मणिपुर में भारत से अलग होने की मांग उठ रही है। 70 साल पहले इस राज्य का विलय भारत में हुआ था, लेकिन यहाँ पर बगावती सुर अब तेज हो रहे हैं।

1.2 गौरतलब है कि मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वी.पी.मेनन ने विलय के समझौते पर 21 सितंबर, 1949 को हस्ताक्षर किए थे।

विवाद क्या

2.1 जब भारत आजाद हुआ था तब कथित रूप से मणिपुर के विलय के विरोध में उग्रवादी संगठनों ने मणिपुर के अलावा त्रिपुरा में भी 15 अक्टूबर को 12 घंटे का बंद रखा था। हालांकि त्रिपुरा में इसका खास असर नहीं पड़ा, लेकिन मणिपुर में आम जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा था।

2.2 मणिपुर के द कोऑर्डिनेशन कमिटी और द अलायंस ऑफ सोशलिस्ट यूनिटी उग्रवादी संगठनों के साथ त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) ने 15 अक्टूबर, 1949 को भारत में इन दोनों राज्यों के कथित रूप से जबरन विलय के विरोध में बंद का आव्हान किया था।

2.3 इन सभी संगठनों ने अपने संयुक्त बयान में भारत में इन दोनों राज्यों के विलय को इतिहास का अंधेरा दौर बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि विलय के चलते इन दोनों राज्यों के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं। साथ ही राजनीतिक व आर्थिक रूप से ये दोनों राज्य पूरी तरह हाशिए पर हैं।

भारत में त्रिपुरा का विलय

3.1 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। 1947 में त्रिपुरा के अंतिम महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य के निधन के बाद राजकाज संभालने वाली महारानी कंचनप्रभा देवी ने त्रिपुरा के भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

कमिश्नरी से लेकर राज्य तक मणिपुर का सफर

4.1 मणिपुर का भारत में विलय होने के बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर का शासन चलाने के लिए एक चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की थी।

4.2 वर्ष 1954 में रिशांग किशिंग ने केंद्रीय शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और राज्य की अपनी विधानसभा गठित करने की मांग उठाई। लेकिन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने दलील दी कि मणिपुर और त्रिपुरा की स्थिति संवेदनशील है और वहां प्रशासन अभी कमजोर स्थिति में है।

4.3 उसके बाद वर्ष 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत 30 चयनित और तीन मनोनीत सदस्यों की एक विधान सभा स्थापित की गई। 19 दिसंबर, 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल का कर दिया गया।

4.4 21 जनवरी, 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधान सभा का गठन कर दिया गया।

उग्रवादी संगठनों का आरोप

5.1 उग्रवादी संगठनों ने एक बयान में आरोप लगाया गया कि दो स्वतंत्र राज्यों मणिपुर और त्रिपुरा को एक संधि के तहत बगैर कोई विशेष दर्जा दिए भारत में विलय कर दिया गया।

5.2 इसके साथ ही विलय से पूर्व सार्वभौम राजनीतिक स्थिति की उपेक्षा करते हुए इन दोनों राज्यों को सबसे निचले वर्ग (C) के राज्य का दर्जा दिया गया।

5.3 मणिपुर की संप्रभुता की वकालत करने वाले लोगों की दलील है कि दबाव या मजबूरी में कोई भी समझौता गैर-कानूनी होता है। ऐसे में कैद की स्थिति में जबरन हस्ताक्षर कराने की वजह से मणिपुर के विलय का समझौता भी गैर-कानूनी है।

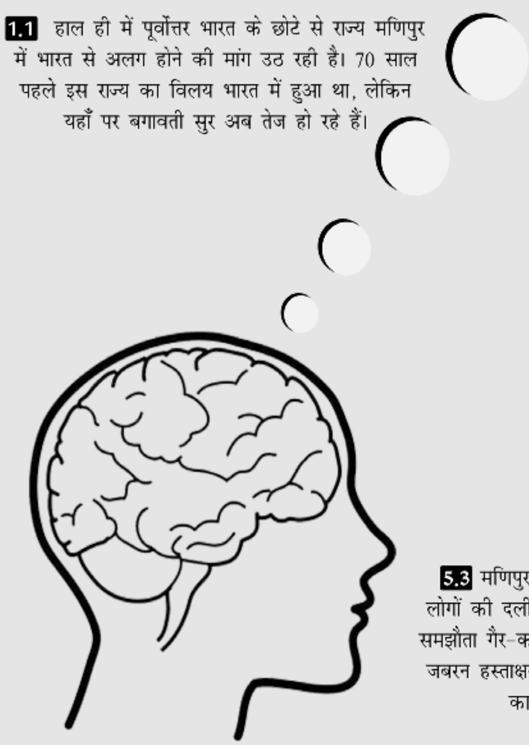

आरसीईपी और भारत

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में 16 सदस्य देशों वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समूह के व्यापार मंत्रियों ने सहमति जताई कि वे नवंबर में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर असहमति के अपने सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे।

आरसीईपी क्या है

2.1 इसकी औपचारिक शुरूआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी। आरसीईपी 16 देशों के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता है, जिससे इन देशों के बीच होने वाले व्यापार को आसान बनाया जा सके।

2.2 इन 16 देशों में 10 आसियान समूह के और छह देश वो हैं जिनके साथ आसियान देशों का मुक्त व्यापार समझौता है।

2.3 इस समझौते में उत्पाद और सेवाओं, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, विवादों के निपटारे, ई कॉमर्स, बौद्धिक संपदा और छोटे-बड़े उद्योग शामिल होंगे।

2.4 इन 16 देशों में दुनिया की लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। दुनिया के निर्यात का एक चौथाई इन देशों से होता है। दुनिया की जीडीपी का 30 प्रतिशत हिस्सा इन देशों से ही आता है।

2.5 इन आंकड़ों के चलते यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता होगा। इस समझौते में 25 हिस्से होंगे। इनमें से 21 हिस्सों पर सहमति बन गई है। अब निवेश, ई कॉमर्स, उत्पादों के बनने की जगह और व्यावसायिक उपचारों पर सहमति होनी है।

आरसीईपी और भारत

3.1 आरसीईपी में शामिल क्षेत्रों में काम कर रही भारत की कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिल सकेगा। इस समझौते के होने के बाद घरेलू बाजार में मौजूद बड़ी कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को भी निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार मिल सकेगा।

3.2 साथ ही भारत में इन देशों से आने वाले उत्पादों पर टैक्स कम होगा और ग्राहकों को कम कीमत पर ये सामान उपलब्ध हो सकेंगे।

3.3 विश्लेषकों के मुताबिक इस करार से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि दर्ज की जा सकती है, खासकर एक्सपोर्ट से जुड़े एफडीआई में। इसके अलावा इस करार से देश के एमएसएमई क्षेत्र को भी खासा फायदा मिलने की उम्मीद है।

चिंताएँ

4.1 भारत के सामने सबसे बड़ी परेशानी है भारत का व्यापार घाटा। इन 16 देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारत 11 देशों के साथ व्यापार घाटे की स्थिति में है। इनमें सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ है।

4.2 2014-15 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2600 अरब रुपये था जो 2018-19 में बढ़कर 3700 अरब रुपये हो गया है। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी चिंता आर्थिक मंदी भी है।

4.3 जानकारों के मुताबिक भारत की निर्यात विकास दर 2019 के पहले आठ महीनों में 11.8 प्रतिशत से घटकर 1.4 प्रतिशत पर आ गई है। अगर ये गिरावट जारी रही तो भारत का व्यापार घाटा और बढ़ेगा क्योंकि भारत दूसरे देशों को निर्यात करने से ज्यादा खुद आयात करेगा।

4.4 जिस तरह भारत की कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिलेगा वैसे ही दूसरे देशों की कंपनियों को भी भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा। ऐसे में चीन समेत सभी दूसरे देश सस्ती कीमतों पर अपना सामान भारतीय बाजार में बेचना शुरू करेंगे। इससे भारतीय बाजार के उत्पादकों को परेशानी हो सकती है।

4.5 इसका उदाहरण बांग्लादेश से लिया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता है। इसके चलते बांग्लादेश में बनने वाला कपड़ा सस्ती दरों पर भारत में उपलब्ध होता है। इसके चलते भारतीय कपड़ा उद्योग को बहुत नुकसान हुआ है।

4.6 खेती के बाद दूसरे नंबर पर रोजगार प्रदान करने वाले कपड़ा उद्योग में करीब 10 लाख लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है।।

4.7 आरसीईपी से इस तरह का असर सबसे ज्यादा डेयरी और स्टील उद्योग पर पड़ने के आसार हैं। विदेशों से सस्ते डेयरी उत्पाद और स्टील आने से भारतीय बाजार को नुकसान हो सकता है।

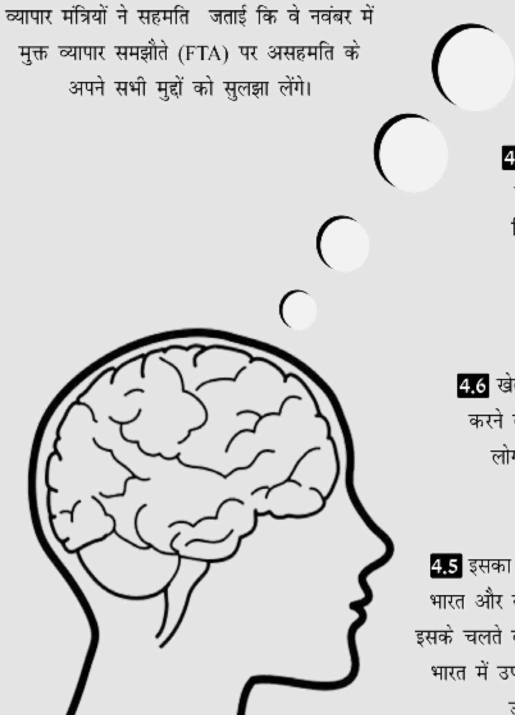

एफ्लाटॉक्सिन एम 1

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देशभर में सर्वे के आधार पर यह खुलासा किया है कि देश में मिलने वाले कच्चे दूध से दोगुना जहरीला पैकेज्ड दूध होता है।

1.2 इसके अलावा कई प्रमुख ब्रांड के पैकेज्ड दूध (प्रोसेस्ड मिल्क) और कच्चे दूध के नमूने निर्धारित गुणवत्ता और तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।

सर्वे के प्रमुख बिंदु

2.1 प्रोसेस्ड मिल्क के 10.4 फीसदी नमूने सुरक्षा मानकों पर फेल रहे, जो कच्चे दूध (4.8 फीसदी) की तुलना में काफी अधिक हैं। इनमें एफ्लाटॉक्सिन- एम 1, एंटीबायोटिक व कीटनाशक जैसे जहरीले पदार्थ मिले हैं।

2.2 तामिलनाडु, दिल्ली, केरल, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए सैंपल में एफ्लाटॉक्सिन मिला है। मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, यूपी, आंध्रप्रदेश और गुजरात के सैंपलों में एंटीबायोटिक अधिक मिले हैं।

2.3 कई प्रमुख ब्रांड के पैकेज्ड दूध (प्रोसेस्ड मिल्क) और कच्चे दूध के नमूने निर्धारित गुणवत्ता और तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।

2.4 वहीं, कच्चे दूध के 3,825 नमूनों में से 47 फीसदी मानकों के मुताबिक नहीं थे। सुरक्षा मानकों की बात करें तो प्रोसेस्ड दूध के 10.4 फीसदी नमूने फेल रहे, जो कच्चे दूध (4.8 फीसदी) की तुलना में काफी अधिक है।

सात फीसदी दूध पीने लायक नहीं

3.1 एफएसएसएआई ने मई से अक्टूबर 2018 के बीच 1,103 शहरों से 6,432 नमूने लिए थे। इनमें 3825 (59.5 फीसदी) कच्चे दूध और 2607 (40.5 फीसदी) प्रोसेस्ड दूध के हैं।

3.2 जांच में 5976 नमूने (93 फीसदी) सुरक्षित मिले, जबकि 456 (7.1 फीसदी) नमूनों में कई तरह की मिलावट मिली।

3.3 इनमें से 368 नमूने (5.7 फीसदी) एफ्लाटॉक्सिन एम-1 नामक रसायन मिला। दो में यूरिया, तीन में डिटर्जेंट पाउडर, छह में हाइड्रोजन ऑक्साइड और एक में न्यूट्रलाइजर के तत्व मिले हैं।

एफ्लाटॉक्सिन एम 1 क्या होता है

4.1 एफ्लाटॉक्सिन का पशु आहार में इस्तेमाल होता रहा है। डेयरी फार्मिंग में अकसर एफ्लाटॉक्सिन बी-1, बी-2 और एम-1 व एम-2 की चर्चा होती रहती है। पशु एफ्लाटॉक्सिन बी-1 युक्त आहार खा लें तो यह सामान्य उपचय द्वारा एफ्लाटॉक्सिन एम 1 के रूप में उनके दूध तथा पेशाब में निकलने लगता है।

4.2 एफ्लाटॉक्सिन ऐसे माइकोटॉक्सिन हैं, जो एस्पर्जिलस फ्लेवस तथा एस्पर्जिलस पैरासाइटिक्स नामक फफूंद से उत्पन्न होते हैं।

4.3 इसे फंफूद से पैदा होने वाला जहर भी कहते हैं। यह मनुष्य और पशु दोनों के लिए खतरनाक होता है। पशुपालन विभाग के अनुसार, कई बार एफ्लाटॉक्सिन नमी और कीटों के द्वारा फसलों की क्षति होने पर भी पैदा हो सकता है।

4.4 एफ्लाटॉक्सिन एम1 रसायन पर अब तक हुए अध्ययनों के अनुसार, इसके सेवन से लोगों में लिवर कैंसर तक का खतरा हो सकता है।

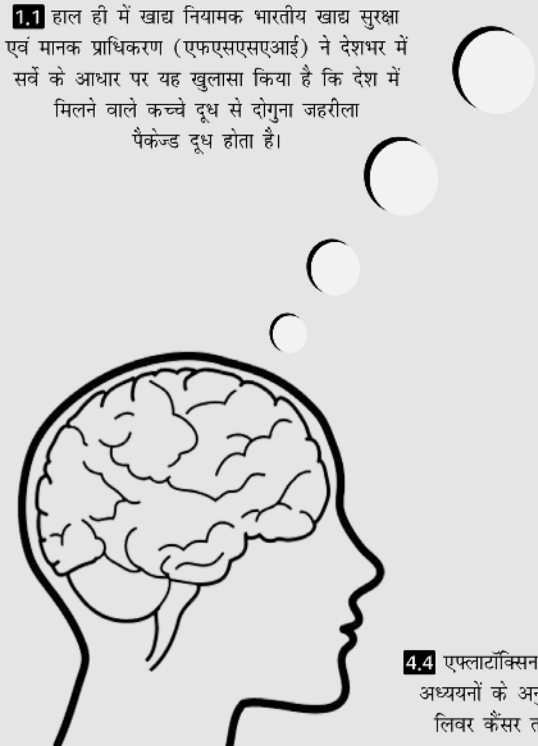

पोबीटोरा वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में पशु चिकित्सकों ने पुष्टि की है कि मध्य असम के पोबीटोरा वन्यजीव अभयारण्य में दो एशियाई जल भैंसों की मौत का कारण एंथ्रेक्स है।

1.2 पोबीटोरा वन्यजीव अभयारण्य जिसमें दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की उच्चतम एकाग्रता है, को 'मिनी काजीरंगा' कहा जाता है।

एंथ्रेक्स क्या है

2.1 एंथ्रेक्स एक कम पाई जाने वाली लेकिन गंभीर बीमारी है जो बैसिलस एंथ्रेसीस (Bacillus anthracis: एक तरह का बैक्टीरिया) के कारण होती है।

2.2 एंथ्रेक्स एक संक्रामक पशुजन्य/जूनोटिक रोग है (इसका संक्रमण संक्रमित पशु से मनुष्य में हो सकता है)। यह मुख्यत: वनस्पति भोजी जंतुओं, विशेषकर भेड़, बकरी, घोड़ा और खच्चर में होने वाला रोग है।

2.3 यह रोग स्वाभाविक रूप से वनस्पति भोजी जानवरों के बीच दूषित मिट्टी और चारा दूषित मांस, हड्डियों से बने खाद्य या अन्य पशु खाद्यों के माध्यम से सर्वाहारी और मांसाहारी जानवरों तथा एंथ्रेक्स संक्रमित मृत शरीर खाने द्वारा जंगली जानवरों में फैलता है।

2.4 एंथ्रेक्स संक्रमित जानवरों की मृत्यु के समय अंतिम रक्तस्राव या गिराए गए रक्त से हो सकता है। एन्थ्रेक्स जीवाणु मिट्टी में कई वर्षों तक जीवित रह सकता है।

2.5 एंथ्रेक्स विश्व के कई हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें एशिया, दक्षिणी यूरोप, उप- सहारा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। प्राणघातक फुंसी (मलिग्नेंट पुस्टुले), प्राणघातक सूजन (मलिग्नेंट एडिमा), ऊन का काम करने वालों का रोग (ऊल सार्टर्स डिजीज) या रैगपिकर्स (कचरा उठाने वालों का रोग) रोग भी कहा जाता है।

2.6 एन्थ्रेक्स दक्षिणी भारत में (जानवरों के क्षेत्र में सामान्यत: होता है) पशुस्थानिक है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में इस रोग का प्रकोप स्थानिक है। पिछले वर्षों में आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक में एंथ्रेक्स के मामले सामने पाए गये हैं।

पशु पर प्रभाव

3.1 एंथ्रेक्स बीमारी फैलने का कोई नियत समय या मौसम नहीं होता है। यह बीमारी साल के किसी भी महीने में फैल सकती है। इससे पीड़ित पशु सुस्त हो जाता है और पागुर करना बंद कर देता है।

3.2 बीमार पशु को तेज बुखार हो जाता है। प्लीहा काफी बढ़ जाता है। पेट काफी फूल जाता है। नाक, पेशाब के रास्ते और मल द्वार से खून बहने लगता है। कभी-कभी एकाएक बिना लक्षण दिखाए भी पशु की मौत हो जाती है।

पोबीटोरा वन्य जीव अभयारण्य

4.1 पोबीटोरा वन्य जीव अभयारण्य गुवाहाटी से 50 किमी दूर मारीगांव जिले में स्थित है। यह अभयारण्य मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है।

4.2 30.8 वर्ग किमी में फैले इस अभ्यारण्य में 16 वर्ग किमी में गैंडे रहते हैं।

4.3 गैंडें के अलावा इस वन्य जीव अभयारण्य की दूसरी विशेषता यहाँ हर साल आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। यहां हर साल करीब 2000 प्रवासी पक्षियाँ आते हैं।

4.4 अभयारण्य में एशियाई भैंस, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और जंगली भालू सहित कई अन्य जीव भी देखे जा सकते हैं।

एंथ्रेक्स रोकने के उपाय

5.1 इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी के अलावा आम जागरूक लोग व जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी इस बीमारी को समाप्त किया जा सकता है।

5.2 साथ ही उन पशुओं को निश्चित स्थानों में दफन कर उस पर चुना, नमक आदि डालने से इस बीमारी से जिवाणु को फैलने से रोकने के सभी उपाय करने की आवश्यकता है।

5.3 पशुपालक को पशुओं में रोग फैलने से पहले रोग निरोधक टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। टीका लगा देने पर पशु इस रोग से एक वर्ष तक सुरक्षित रहता है। अगर एंथ्रेक्स फैल जाए तो पशुपालक आसपास के गाँव में पशुओं का आवागमन बंद कर दें।

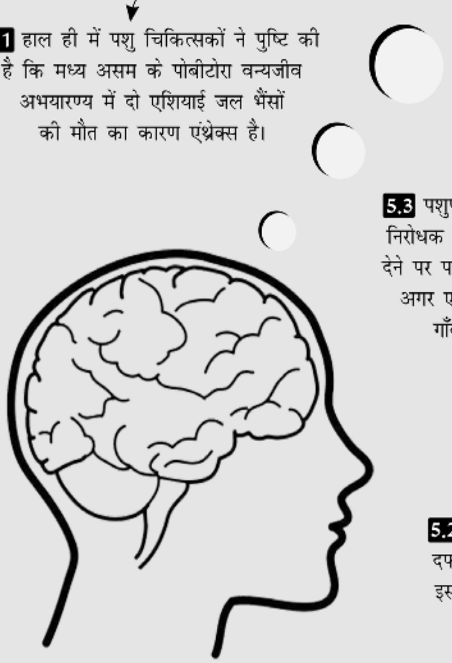

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. गोल (GOAL) कार्यक्रम

प्र. गोल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह कार्यक्रम गूगल एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग द्वारा चलाया जा रहा है।
2. इसका उद्देश्य युवा पुरुषों को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और शिक्षित करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय महिलाओं हेतु 'गोल' (जीओएएल-गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) के दूसरे चरण की घोषणा की। गोल कार्यक्रम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का है, इसका उद्देश्य देशभर की जनजातीय युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम 'गोल' के जरिए वंचित युवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार, फैशन और कला क्षेत्रों के वरिष्ठ विशेषज्ञों से जोड़ा जाता है, जिससे कि वे डिजिटल और जीवन कौशल सीख सकें। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

2. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स

प्र. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में राज्य स्तर पर नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है।
2. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में सबसे निचला स्थान झारखण्ड का है।
3. नवाचार सूचकांक के जरिए राज्यों का मजबूत और कमजोर पक्ष सामने आएगा।
4. इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है।

उत्तरः (1)

व्याख्याः हाल ही में नीति आयोग ने वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज (नवप्रवर्तन के आधार पर) पर राज्यों की रैंकिंग जारी की है जिसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। नवाचार सूचकांक के जरिए राज्यों का मजबूत और कमजोर पक्ष सामने आएगा। इससे जरूरत के मुताबिक नीति बनाने में मदद मिलेगी। नीति आयोग ने देश में राज्य स्तर पर नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिये यह पहल की है। यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे राज्यों की तुलना में अपने प्रदर्शन को मानकीकृत बनाने में उपयोगी साबित होगा। इसके आधार पर वे अलग-अलग प्रदर्शन के कारणों को समझ पाएंगे और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिये बेहतर रणनीति तैयार कर सकेंगे इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

3. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, 2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ल्ड आउटलुक का प्रकाशन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है।
2. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन एक वर्ष में दो बार होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक सर्वेक्षण है जिसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

4. मणिपुर और त्रिपुरा का विलय

प्र. मणिपुर और त्रिपुरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय संघ में विलय होने के पहले त्रिपुरा एक स्वतंत्र रियासत थी।
2. 15 नवंबर 1949 को त्रिपुरा को भारतीय संघ में मिला लिया गया।
3. 1975 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
4. मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 3 व 4 (d) केवल 1, 3 व 4

उत्तरः (c)

व्याख्याः 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। 1947 में त्रिपुरा के अंतिम महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य के निधन के बाद राजकाज संभालने वाली महारानी कंचनप्रभा देवी

ने त्रिपुरा के भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 21 जनवरी, 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधान सभा का गठन कर दिया गया। इस प्रकार कथन 1 व 2 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

5. आरसीईपी और भारत

प्र. आरसीईपी और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आरसीईपी 10 देशों का समूह है।
2. आरसीईपी में वे देश भी शामिल हैं जिनके साथ मुक्त व्यापार समझौता है।
3. भारत आरसीईपी का संस्थापक सदस्य है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 व 2
(c) केवल 1 व 3
(d) केवल 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में 16 सदस्य देशों वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समूह के व्यापार मंत्रियों ने सहमति जताई कि वे नवंबर में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर असहमति के अपने सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे। इसकी औपचारिक शुरूआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी। आरसीईपी 16 देशों के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता है, जिससे इन देशों के बीच होने वाले व्यापार को आसान बनाया जा सके। इन 16 देशों में 10 आसियान समूह के और छह देश वो हैं जिनके साथ आसियान देशों का मुक्त व्यापार समझौता है। भारत वर्तमान में आरसीईपी का सदस्य नहीं है। इस प्रकार कथन 2 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

6. एफ्लाटॉक्सिन एम 1

प्र. एफ्लाटॉक्सिन एम 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एफ्लाटॉक्सिन का मानव भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है।
2. एफ्लॉटाक्सिन से लिवर कैंसर का खतरा हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: एफ्लाटॉक्सिन का पशु आहार में इस्तेमाल होता रहा है। डेयरी फार्मिंग में अकसर एफ्लाटॉक्सिन बी-1, बी-2 और एम-1 व एम-2 की चर्चा होती रहती है। पशु एफ्लाटॉक्सिन बी-1 युक्त आहार खा लें तो यह सामान्य उपचय द्वारा एफ्लाटॉक्सिन एम 1 के रूप में उनके दूध तथा पेशाब में निकलने लगता है। एफ्लाटॉक्सिन ऐसे माइकोटॉक्सिन हैं, जो एस्पर्जिलस फ्लेवस तथा एस्पर्जिलस पैरासाइटिक्स नामक फफूंद से उत्पन्न होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन एम1 रसायन पर अब तक हुए अध्ययनों के अनुसार, इसके सेवन से लोगों में लिवर कैंसर तक का खतरा हो सकता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

7. पोबीटोरा वन्यजीव अभयारण्य

प्र. पोबीटोरा वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह अभयारण्य मणिपुर में स्थित है।
2. यह अभयारण्य मुख्य रूप से जल भैसों के लिए जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: पोबीटोरा वन्य जीव अभयारण्य गुवाहाटी से 50 किमी दूर मारीगांव जिले में स्थित है। यह अभयारण्य मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। 30.8 वर्ग किमी में फैले इस अभयारण्य में 16 वर्ग किमी में गैंडे के अलावा एशियाई भैंस, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और भालू सहित अन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में सुर्खियों में रहा तुलागी द्वीप किस देश का हिस्सा है?

- सोलोमन आइलैंड्स

2. हाल ही में कँवर सेन जॉली का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे?

- पत्रकारिता

3. हाल ही में सुर्खियों में रहा 'बलियात्रा' किस राज्य का व्यापारिक मेला है?

- ओडिशा

4. हाल ही में संपन्न परमाणु उर्जा कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया?

- नई दिल्ली

5. हाल ही में शिरुई लिली उत्सव चर्चा में रहा, यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है?

- मणिपुर

6. हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज-वी युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया गया?

- ओमान

7. हाल ही में सुर्खियों में रहा चेनानी नाशरी सुरंग किस राज्य में स्थित है?

- जम्मू-कश्मीर

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारत और नेपाल के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव के कारणों का विश्लेषण करें, साथ ही बताएँ कि नेपाल में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप से भारत किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है?

2. साइबर अपराध क्या है? भारत में साइबर अपराध सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

3. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'इंटरनेट ने भारतीय कला एवं संस्कृति पर आघात किया है'? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

4. सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए आने वाले चुनौतियों को रेखांकित करें।

5. पॉलिथीन पर प्रतिबंध को अमल में लाया जा रहा है, इस संदर्भ में क्या सरकार ने पॉलिथीन निर्माता कंपनियों के ऊपर निगरानी हेतु कोई प्रभावी योजना लागू की है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

6. भारत में आरक्षण नीति के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें, साथ ही बताएँ कि इस नीति के सम्मुख कौन-कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

7. किसी भी देश की आबादी में महिलाओं के कार्यबल को तरजीह दिए बगैर एकीकृत विकास संभव नहीं है। विश्लेषण कीजिए।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट

- हाल ही में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड (यूनिसेफ) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनियाभर में पाँच साल से कम उम्र के तीन बच्चों में एक बच्चा कुपोषित है और उसका विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है। यूनिसेफ ने चिल्ड्रेन, फूड एंड न्यूट्रिशन की रिपोर्ट में चेताया, "बड़ी संख्या में खतरनाक ढंग से बच्चे खराब आहार व खाद्य प्रणाली का परिणाम भुगत रहे हैं।"
- 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2019: चिल्ड्रेन, फूड एंड न्यूट्रिशन' में कहा गया है कि पाँच साल से कम उम्र के 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे या तो कुपोषित हैं या मोटापाग्रस्त हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह स्थिति तीन में से एक है और छह महीने से दो साल की आयु के करीब दो-तिहाई बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिससे उनका उचित विकास हो।
- पर्याप्त पोषण की कमी से बच्चों में स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कमजोर दिमाग, सीखने की कमी, कमजोर प्रतिरक्षा और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और कई मामलों में समय पूर्व मौत भी हो जाती है।
- स्वास्थ्य और पोषण को लेकर तकनीकी उन्नति के बावजूद दुनिया सबसे मूल तथ्य को भूल गई है कि अगर बच्चे खराब तरह से खाते हैं तो खराब तरह से जीएंगे। लाखों बच्चे पोषक आहार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है।
- महत्वपूर्ण रिपोट कुपोषण के 'ट्रिपल बर्डन' को बताती है। इसके तहत कुपोषण, मोटापा और जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। पाँच साल से कम उम्र के 14.9 करोड़ बच्चे अपनी उम्र से काफी छोटे हैं। पाँच करोड़ बच्चे अपनी लंबाई के मुकाबले काफी पतले हैं, जो कुपोषण का आम संकेत है।
- यूनिसेफ ने 'हिडेन हंगर' में कहा कि इसी आयु समूह वाले अन्य चार करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हैं। इसके साथ ही दुनियाभर के आधे बच्चे जरूरी विटामिन व पोषक पदार्थ नहीं पा रहे हैं। ■

2. खाद्य सुरक्षा मित्र योजना

- हाल ही में विश्व खाद्य दिवस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना शुरू की। सही नीति और कार्यान्वयन की दिशा में ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया अभियान सफल साबित होगें। इस दिवस की थीम है 'शून्ये भूखमरी वाली दुनिया के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन।'
- सरकार ने विशेष बल देते हुए कहा कि लोगों में बहुप्रतीक्षित सामाजिक एवं स्वभाव संबंधी बदलाव लाने के लिए 'ईट राइट इंडिया' अभियान अंतिम जरूरी है। यदि सही रणनीति अपनायी जाए और समाज के हर तबके तक पहुँचने के लिए ठोस प्रयास किये जाएं, तो 'फिट इंडिया' अभियान के साथ-साथ इस अभियान को भी उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। लोगों को महात्मा गाँधी के संदेशों को अपनाना चाहिए जिनमें उन्होंने कम भोजन करने, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन करने, अतिरिक्त भोजन को साझा करने की आदत डालने और खाद्य पदार्थो की बर्बादी में कमी लाने को कहा है। 'खाद्य सुरक्षा मित्र' योजना छोटे एवं मझोले खाद्य व्यवसायियों के लिए खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करने और लाइसेंस एवं पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग तथा प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने में मददगार साबित होगी। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा यह योजना विशेषकर खाद्य एवं पोषण से जुड़ी पृष्ठखभूमि वाले युवाओं के लिए नये रोजगार अवसर भी सृजित करेगी। ■

3. ग्लोबल टीबी रिपोर्ट

हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'ग्लोबल टीबी रिपोर्ट' बताती है कि वर्ष 2018 में टीबी संक्रमण के एक करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए और 30 लाख से ज्यादा ऐसे पीड़ित हैं जिनकी आवश्यकतानुसार देखरेख नहीं हो रही है। इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाईजीरिया, पाकिस्तान, फिलिपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार टीबी बीमारी के भारी बोझ से पीड़ित ब्राजील, चीन, रूस और जिम्बाब्वे में वर्ष 2018 तक उपचार का स्तर 80 फीसदी तक पहुंच गया है। वर्ष 2018 में टीबी का

प्रकोप 2017 में तुलना में थोड़ा कम था लेकिन गरीब और वंचित जनसमूहों में टीबी संक्रमण अब भी बहुत अधिक है- विशेषकर एचआईवी से पीड़ित लोगों में। वर्ष 2018 में टीबी से पीड़ित 70 लाख लोगों का इलाज किया गया जबकि 2017 में यह संख्या 64 लाख थी।

इस स्थिति के पीछे मुख्य वजह टीबी के इलाज का खर्च बताया गया है। आँकड़े दर्शाते हैं कि टीबी से बुरी तरह प्रभावित देशों 80 फीसदी से ज्यादा मरीज अपनी कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा उपचार पर खर्च करते हैं। इलाज में दवाई का असर ना कर पाना एक नई चुनौती है और वर्ष 2019 में टीबी के पाँच लाख से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए जिनमें इलाज के दौरान दवाई ने काम नहीं किया।

इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019

2018 में टीबी संक्रमित लोगों की संख्या में 16 प्रतिशत बढ़ गई है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 के अनुसार, कुल 25 प्रतिशत यानी 5.4 लाख मामले निजी अस्पतालों से सामने आए हैं। यह संकेत देता है कि लोग निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहे हैं। रिवाइज्ड नेशनल टुब्रोकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (आरएनटीसीपी) को सूचित किया गया है कि 2018 में टीबी के 21.5 लाख मामले सामने आए, जबकि 2017 में यह 18 लाख था यानी एक साल के भीतर 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ■

4. राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन

- हाल ही में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 07 मई 2018 को सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने और विशेष रूप से सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने वाले सदस्य के स्वत: निलंबन का प्रावधान करने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है। उच्च सदन का कामकाज बेहतर ढंग से चलाने के उद्देश्य से नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने का फैसला किया गया है। यह समिति सांसदों एवं विशेषज्ञों से बात करके तथा विभिन्न देशों के सदनों के नियमों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी।

समिति का स्वरूप

- समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे। समिति की सिफारिशें सदन की नियम संबंधी समिति के पास भेजी जाएगी जो राजनीतिक दलों एवं सांसदों से विचार विमर्श के बाद सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

नियमों में बदलाव की आवश्यकता क्यों

- बजट सत्र के दूसरे में चरण में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो पाया था। इसी के मद्देनजर नियमों में बदलाव करने हंगामा करने वालों के खिलाफ स्वत: निलंबन का प्रावधान किया जा रहा है। लोकसभा की तरह, सदन में सभापति के आसन के पास आकर बार-बार हंगामा करने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन का प्रावधान फिलहाल राज्यसभा में नहीं है। ■

5. भारत के सबसे ऊँचे पुल का उद्घाटन

- हाल ही में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम कर्नल चेवांग रिनचेन के नाम पर रखा गया है, कर्नल रिनचेन लद्दाख से भारतीय सेना के अफसर थे। उन्हें 1952 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु

- इस पुल का निर्माण लद्दाख क्षेत्र में 14,650 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। इस पुल का निर्माण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दुरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क पर किया गया है। यह चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कण्ट्रोल से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस पुल की चौड़ाई 4.5 मीटर है, यह पुल 70 टन श्रेणी के वाहनों का भार उठाने में सक्षम है। इससे श्योक नदी के दूसरी ओर के क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी तथा यात्रा के समय में भी कमी आएगी। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा किया गया है। इस पुल का निर्माण 15 महीने में किया गया, इसमें 6900 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तथा 1984 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया।

कर्नल चेवांग रिनचेन

- कर्नल चेवांग रिनचेन को 'लद्दाख का शेर' भी कहा जाता है, उन्हें दो बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
- 1971 में लद्दाख के प्रतापपुर सेक्टर में दुश्मन के नौ ठिकानों को मुक्त करने के लिए उन्हें पुन: महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ■

6. बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को एक द्वीप पर भेजेगा

- म्यांमार हिंसा के बाद जान बचाकर बांग्लादेश पहुँचे करीब दस लाख रोहिंग्या मुस्लिमों में से एक लाख लोगों को बांग्लादेश सरकार अब जबरन स्थानांतरित करने की योजना बना रही है सरकार की योजना एक लाख रोहिंग्याओं को दूर 'भाशन चार द्वीप' भेजने की तैयारी है। बंगाल की खाड़ी में स्थित इस द्वीप को निर्जन द्वीप भी कहा जाता है। डीडब्ल्यू की खबर के मुताबिक इस द्वीप पर सैकड़ों घर बनाए गए हैं। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं और खुद रोहिंग्या शरणार्थियों ने सरकार की इस योजना पर

सवाल उठाए हैं दरअसल 'भाशन चार' एक छोटा और दलदल से बना द्वीप है, जिस पर बाढ़ और तूफान आने का खतरा हमेशा बना रहता है।

- रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने करीब एक साला पहले इस द्वीप पर सड़के, शिविर और बाढ़ से बचाने वाली दिवारे बनवानी शुरू की। बता दें कि करीब बीस साल पहले बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप बनना शुरू हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह द्वीप ऐसी जगह पर जहाँ मानसून में हमेशा बाढ़ का खतरा होगा।
- गौरतलब है कि म्यांमार सीमा से सेटे बांग्लादेश के कोक्स बाजार में स्थित शरणार्थी शिविरों में इस समय करीब दस लाख शरणार्थी हैं। ■

7. संयुक्त राष्ट्र ने भारत में 'फीड अवर फ्यूचर' अभियान की शुरूआत की

- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने भारत में भूख और कुपोषण के विरुद्ध जागरुकता लाने तथा कदम उठाने के उद्देश्य से सिनेमा के लिए विज्ञापन अभियान 'फीड अवर फ्यूचर' की शुरूआत की है। इस समारोह का आयोजन फेसबुक के साथ साझेदारी में हुआ।
- विज्ञापन अभियान 'फीड अवर फ्यूचर' ने यूएफओ मूवीज के साथ मिलकर लॉन्च किया है, जो भारत में सिनेमा के सबसे बड़े विज्ञापन प्लेटफॉर्म में से एक है। डब्ल्यूएफपी का मानना है कि इस विज्ञापन अभियान से उन्हें भारतीयों में शून्य भूख के संदेश को फैलाने में सहायता मिलेगी।
- यह विज्ञापन वास्तविकता को दिखाता है जो विश्वभर में लाखों लोग सामना कर रहे हैं। यह यूएफओ मूवीज और डब्ल्यूएफपी के सहयोग से पिछले अभियान की सफलता पर आधारित है। यह भारत में भूख और कुपोषण के अहम मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने के योग्य है तथा दर्शकों के साथ इसका समर्थन करेगा।
- विज्ञापन से पता चलता है कि जब बच्चों की आवाजें भूख के कारण खामोश हो जाती हैं तो विश्व को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मार्मिक वृतांत सीरियन शरणार्थी बच्चों के समूह को देखता है जो स्थानीय समुदाय से चुने गए मलबे में खेलते हैं तथा स्पष्ट युद्ध क्षेत्र में बमबारी वाली इमारतों से बाहर निकलते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम

- यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता शाखा है। यह भूखमरी को समाप्त करने हेतु तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है और इसकी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना साल 1961 में की गयी थी। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने जापान के ओकायामा शहर में जापान की प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित जी-20 ओकायामा स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- जी-20 के स्वास्थ्य मंत्रियों के विचार-विमर्श में चार प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनके नाम हैं (i) सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की उपलब्धि (ii) बुजर्ग हो रही जनसंख्या पर प्रतिक्रिया (iii) एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) एवं इसका नियंत्रण (IV) स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन।
- भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) पर अपनी युक्ति प्रस्तुत करते हुए समावेशी स्वास्थ्य के लिए सब का साथ; सब का विकास; सब का विश्वास के विजन को आयुष्मान भारत, फिट इंडिया आंदोलन और सही खाओ (इट राईट) अभियान को रेखांगित किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत यूएचसी के रास्ते पर है और वैश्विक स्तर पर यूएचसी को बनाए रखने में प्रभावी योगदान देगा।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बुजर्ग हो रही जनसंख्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, 2050 तक अपनी अनुमानित 20% बुजुर्ग आबादी के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया।
- उन्होंने जी-20 देशों को बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बढ़ती उम्र के लोगों के लिए सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने से संबंधित अब तक किए गए प्रयासों से अवगत कराया।
- उन्होंने जड़बुद्धिता से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने अपने बुजुर्गों की देखभाल के साथ गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य जोखिम और स्वास्थ्य सुरक्षा पर विचार करते हुए, एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) पर विचार प्रस्तुरत किया, जिसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर उभरते खतरे के रूप में देखा गया।
- उन्होंने जी 20 स्वास्थ्य मंत्रियों को अवगत कराया कि कुछ ही समय में भारत ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करके, एक राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी प्रणाली की स्थापना करके और वैश्विक एएमआर विकास अनुसंधान प्रयासों में योगदान देने के अपने निर्णय के जरिए सराहनीय प्रगति की है।

2. भारत-फिलीपींस व्यापार सम्मेलन

- हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मनीला में भारत-फिलीपींस व्यांपारिक सम्मेलन और चौथे आसियान-भारत व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
- राष्ट्रपति ने कहा कि फिलीपींस और भारत के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश कई परस्पर पूरकताएँ साझा करते हैं, जिनका उपयोग व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत बनाने में किया जा सकता है।
- भारत का 'मेक इन इंडिया' और अगली पीढ़ी के अवसंरचना संबंधी कार्यक्रम तथा फिलीपींस की 'बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड अवसंरचना संबंधी पहल दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- जहाँ एक ओर द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है, वहीं आईटी-बीपीओ खंड में हमारा सहयोग वास्तविक मायनों में लाभप्रद रहा है। ऐसे में जबकि हम डिजिटल युग में दाखिल हो रहे हैं, हमारे पास ई-कॉमर्स के विस्तार, फिन-टेक सेवाओं के सृजन, काल्पनिक मनोरंजन मंचों तथा हरित एवं स्वच्छ समाधानों के विकास की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं।

- हाल के वर्षों में भारत-फिलीपींस, अवसंरचना और ऊर्जा क्षेत्रों में दो तरफा निवेश में विकास के साक्षी रहे हैं। हवाई अड्डा टर्मिनलों से लेकर एलएनजी पाइपलाइन और अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों तक जैसे अनेक क्षेत्रों में मौजूद संभावनाएं ठोस परियोजनाओं में परिवर्तित किये जाने की प्रतीक्षा में हैं।
- भारतीय औषधि निर्माण एवं स्वास्थ सेवा क्षेत्र फिलीपींस के लिए अत्यंत महत्व रखते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवाएँ, कृषि, अभियांत्रिकी से लेकर नई प्रौद्योगिकियों तक कई अन्य क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की संभावनाएँ मौजूद हैं।

3. चौथा आसियान-भारत व्यापार सम्मेलन

- राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मनीला में चौथे आसियान-भारत व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
- राष्ट्रपति ने कहा कि आसियान आज विश्व में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा गतिशील क्षेत्रों में से एक है।
- भारत के आसियान के प्रत्येक सदस्य देश के साथ राजनीतिक एवं जनता के बीच गहरे पारस्परिक संबंध हैं। हम अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को समान स्तर पर लाने के इच्छुक हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में आसियान-भारत के व्यापार में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि हालाँकि वर्ष 2022 तक 200 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। खासतौर पर आसियान-भारत व्यापार परिषद् जैसे मौजूदा तंत्रों का कारगर उपयोग करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी मदद मिल सकती है।
- उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भारतीय कंपनियों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह उन्हें यकीन है कि आसियान व्यापारिक समुदाय भी भारत में व्यापार की अपार संभावनाओं की पहचान कर सकता है।
- राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आसियान की विकास गाथा में भागीदार बनने का इच्छुक है और वह आसियान के सभी सदस्य देशों को अपनी विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।
- राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि फिलीपींस के साथ भारत के संबंधों के बढ़ते दायरे में जन कल्याण और जीवन प्रदान करने वाली परियोजनाएँ शामिल की गई हैं।
- उन्होंने कहा कि मानव जीवन से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है और माता-पिता के लिए उनके बच्चों की सेहत और तंदुरुस्त से बढ़कर कुछ नहीं है।

4. 11वाँ परमाणु ऊर्जा सम्मेलन

- हाल ही में नई दिल्ली में 11वाँ परमाणु ऊर्जा सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का विषय था: परमाणु ऊर्जा का अर्थशास्त्र सुरक्षित और किफायती प्रौद्योगिकियों की दिशा में नवाचार।
- प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन,परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि होमी जहागीर भाभा कहा करते थे कि भारत की परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण कार्यो के लिए है।
- सरकार विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोगों में विविधता लेकर आई है।
- सरकार ने देश में और विशेषकर परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं।
- पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल दक्षिण भारत तक सीमित थे, लेकिन अब सरकार ने ऐसे संयंत्र देश के अन्य हिस्सो में भी लगाने शुरू कर दिये हैं। ऐसा ही एक परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में लगाया जा रहा है।
- परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग दोनों का मुख्यालय दिल्ली से बाहर है।
- ऐसे में छात्रों और आम जनता को परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में 'हॉल ऑफ न्यूक्लिर एनर्जी' खोला गया था। अंतरिक्ष विभाग के लिए भी ऐसा ही एक हॉल खोले जाने की योजना है।
- उन्होंने बीमारियों और विशेषकर कैंसर के इलाज में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस संदर्भ में गुवाहाटी के डॉक्टर बी.बरूआ, कैंसर इंस्टीट्यूट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे मुम्बई के टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर के साथ जोड़ा गया है।
- उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग कई प्रमुख सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।
- उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों के मन मे पैदा भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक बड़ा स्रोत है।
- जलवायु परिवर्तन गंभीर रूप ले रहा है। मानवता के लिए ये बड़ा खतरा है। यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, तो आगे स्थितियाँ बिगड़ जाएगी। बढ़ते वैश्विक तापमान को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे बेहतर विकल्प है।

- परमाणु ऊर्जा के लिए भारत द्वारा बड़े पैमाने पर यूरेनियम आयात करना सही नहीं होगा। ऐसा करने से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए हमें कम संसाधनों के साथ ही इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।
- सौर ऊर्जा इसके लिए बेहतर विकल्प है। भारत इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा का निर्यात कर सकता है।

5. एक्स ईस्टर्न ब्रिज- V

- हाल ही में भारतीय वायु सेना, रॉयल एयरफोर्स ओमान (आरएएफओ) के साथ एक्स ईस्टर्न ब्रिज-V नामक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास एयरफोर्स बेस मसीरा में 17 से 26 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित किया गया। पिछला अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज-IV जामनगर में 2017 में आयोजित किया गया था।
- पहली बार मिग-29 लड़ाकू विमान ने भारत से बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है।
- इसके अलावा भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल मिग-29 और सी-17 विमान, मिग-29 रॉयल एयरफोर्स ओमान के यूरोफाइटर टाइफून, एफ-16 और हॉक के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। इस अभ्यास से दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी परिचालन के दौरान अंतरसंक्रियता में बढ़ोत्तरी हुई है और इससे एक-दूसरे की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को जानने का अवसर उपलब्ध हुआ है।
- इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की भागीदारी से व्यावसायिक बातचीत, अनुभव आदान-प्रदान और परिचालन जानकारी को भी बढ़ावा मिले। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा इससे वायुसैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय माहौल में परिचालन करने का एक अच्छा अवसर भी उपलब्ध हुआ है।

6. 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी कर दी है। यह गणना न केवल नीति निर्माताओं, बल्कि कृषि विशेषज्ञों, व्याापारियों, उद्यमियों, डेयरी उद्योग और आम जनता के लिए भी लाभप्रद साबित होगी।
- देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है जो पशुधन गणना- 2012 की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक है।
- कुल गोजातीय आबादी (मवेशी, भैंस, मिथुन एवं याक) वर्ष 2019 में 302.79 मिलियन आंकी गई जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत अधिक है।
- देश में मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में 192.49 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में 0.8 प्रतिशत ज्यादा है।
- मादा मवेशी (गायों की कुल संख्या) 145.12 मिलियन आंकी गई है जो पिछली गणना (2012) की तुलना में 18.0 प्रतिशत अधिक है।
- विदेशी/संकर नस्ल और स्वदेशी/अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या देश में क्रमश: 50.42 मिलियन और 142.11 मिलियन है।
- स्वदेशी/अवर्गीय मादा मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में पिछली गणना की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ गई है।
- विदेशी/संकर नस्ल वाली मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में पिछली गणना की तुलना में 26.9 प्रतिशत बढ़ गई है।
- स्वदेशी/अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या पिछली गणना की तुलना में 6 प्रतिशत कम हो गई है। हालांकि, 2012-2019 के दौरान स्वदेशी/अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या में कमी की गति 2007-12 के लगभग 9 प्रतिशत की तुलना में अपेक्षाकृत काफी कम है।
- देश में भैंसों की कुल संख्या 1109.85 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 1.0 प्रतिशत अधिक है।
- गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 9125.34 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में 6.0 प्रतिशत अधिक है।
- देश में भेड़ की कुल संख्या वर्ष 2019 में 74.26 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में 14.1 प्रतिशत ज्यादा है।
- देश में बकरी की कुल संख्या वर्ष 2019 में 148.88 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में 10.1 प्रतिशत अधिक है।
- वर्तमान गणना में देश में सुअर की कुल संख्या 9.06 मिलियन आंकी गई है जो पिछली गणना की तुलना में 12.03 प्रतिशत कम है।
- मिथुन, याक, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट सहित अन्य पशुधन आपस में मिलकर कुल पशुधन में लगभग 0.23 प्रतिशत का योगदान करते हैं और उनकी कुल संख्या 1.24 मिलियन है।
- देश में कुल पोल्ट्री संख्या वर्ष 2019 में 851.81 मिलियन आंकी गई है जो 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- देश में घरों के आंगन में पोल्ट्री की कुल संख्या 1317.07 मिलियन आंकी गई है जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत ज्यादा है।

- देश में वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या 534.74 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में 4.5 प्रतिशत अधिक है।

7. भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय मूल्यों के अनुरूप इतिहास का ज्ञान होना जरूरी

- उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय मूल्यों के साथ इतिहास लिखे जाने का आह्वान करते हुए कहा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 को स्वतंत्रता का पहला संघर्ष के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया।
- इसे हमेशा सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का शोषण करने के लिए अंग्रेजों के अपने निहित स्वार्थ थे। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतिहास को मात्र एक उपकरण बनाया।
- हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- भारत में 19,500 से अधिक भाषाएँ तथा बोलियाँ मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। भाषा की इस समृद्ध विरासत को संजोने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। हमें भाषा की इस विरासत में गर्व होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में मिलनी चाहिए।
- इससे बच्चों में शिक्षा प्राप्ति का परिणाम बेहतर होगा और इससे हमारी भाषाओं का संरक्षण भी होगा।
- उपराष्ट्रपति ने छात्रों को भविष्य का नेता बताते हुए कहा कि उन्हें केवल अपनी पढ़ाई में ही बेहतर नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के समक्ष मौजूद ज्वलंत मुद्दों के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए।
- उन्होंने छात्रों से कक्षाओं तक सीमित न रहते हुए प्रकृति की गोद में भी कुछ समय बिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा 'प्रकृति व्यक्ति एक ऐसा इंसान बनने में मदद करती है जो छोटे से छोटे जीवों के प्रति भी संवेदनशील होता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे विकास का रास्ता चुना जाना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधनों पर विपरित न डाले।
- उन्होंने कहा कि गैर-संचारी रोगों में बढ़ोतरी युवा पीढ़ी की बदलती जीवन शैली की वजह से हो रही है।
- युवाओं को पारंपरिक भारतीय खान-पान और योग के फायदे के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये फिट इंडिया अभियान का संदेश सब तक पहुँचाने का अनुरोध किया।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय था जब भारत विश्व गुरु माना जाता था। हमे दुबारा भारत की ऐसी छवि बनानी है और देश को नवाचार और ज्ञान का केन्द्र बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करने होंगे, ताकि छात्र 21 सदी की चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे भविष्य के अपने सभी प्रयासों में इंडिया फर्स्ट की सोच को पहले रखे।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. 'मानव पूँजी' के मानक पर उच्चतम व निम्नतम प्रदर्शन करने वाले राज्य

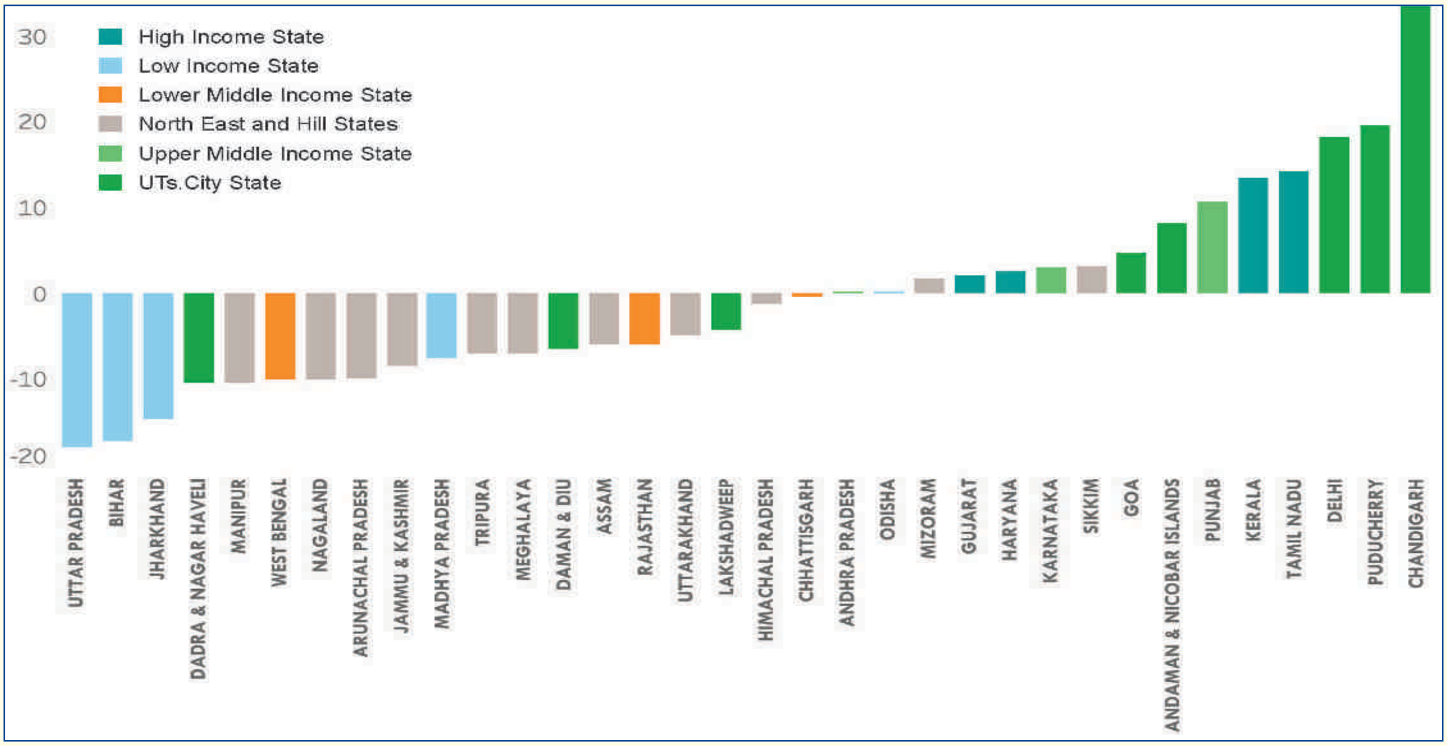

महत्वपूर्ण तथ्य

- 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स' के माध्यम से नीति आयोग यह परखने की कोशिश कर रहा है कि राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार और समाज द्वारा क्या नई पहलकदमियां की जा रही हैं।
- इसके अलावा नीति आयोग यह भी देखने की कोशिश कर रहा है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, तकनीक और मानव संसाधन के बीच कैसा तालमेल है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 के औसत स्कोर की गणना दो आयामों-एनेब्लर्स (Enablers) और परफॉर्मेंस (Performance) के आधार पर की गई है। एनेब्लर्स वाले पैमाने में मानव संसाधन, निवेश, कारोबार का माहौल, सुरक्षा और कानूनी वातावरण को रखा गया है जबकि ज्ञान के उत्पादन और ज्ञान के प्रसार को परफॉर्मेंस का पैमाना माना गया है। गौरतलब है कि एनेब्लर्स वे कारक हैं जो अभिनव क्षमताओं को रेखांकित करते हैं।
- नवाचार के संबंध में भारत का औसत स्कोर सूचकांक 15.6 है। यह स्कोर बताता है कि देश में नवाचार के संबंध में विकास और सुधार की बहुत संभावनाएँ हैं। इनेब्लर्स (Enablers) का औसत स्कोर 18.3 है, जबकि परफॉर्मेंस मानक का औसत स्कोर 12.8 है। चूँकि एनेब्लर्स का प्रदर्शन बेहतर है, इसलिए यह स्पष्ट है कि देश अपनी क्षमता के अनुरूप नवाचार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है।
- एनेब्लर्स और परफॉर्मेंस के बीच मानव पूँजी 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स' में औसतन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्तम्भ है। हालांकि यह एनेब्लर्स और परफॉर्मेंस करने वाले मानकों में राज्यों के बीच असमानता भी प्रस्तुत कर रहा है जहाँ न्यूनतम स्कोर 8.98 तो अधिकतम स्कोर 74.96 है।
- मानव पूँजी में दक्षिण के कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है।
- बिहार, झारखण्ड और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों को विशेष रूप से नवाचार के लिए उच्च संस्थागत निवेश की आवश्यकता है।
- केन्द्रशासित प्रदेशों की बात करें तो मानव पूँजी में चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली इन दोनों राज्यों से थोड़ा सा आगे है। ये तीनों केन्द्रशासित प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं और शोधकर्त्ता की उच्च उपलब्धता के कारण सभी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

2. 'निवेश' के मानक पर उच्चतम व निम्नतम प्रदर्शन करने वाले राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

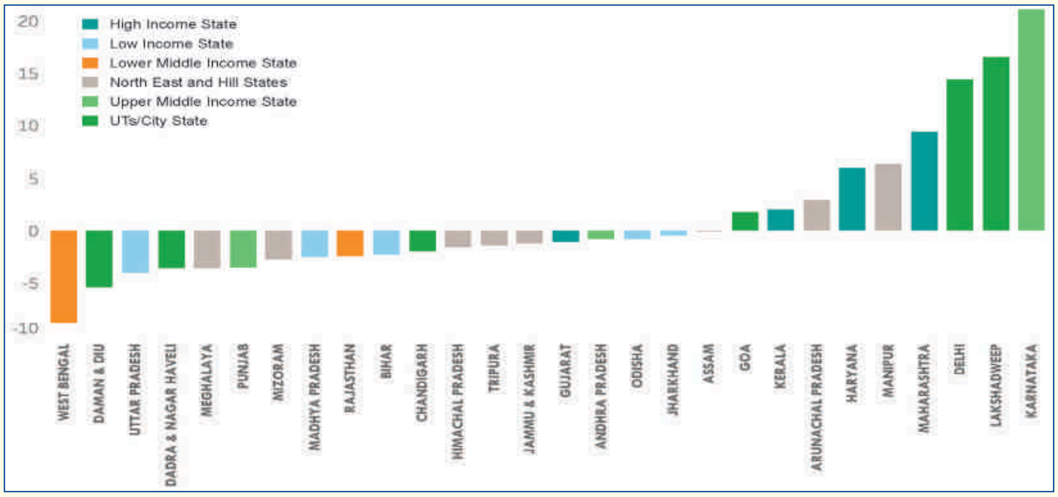

- यदि बड़े राज्यों पर नजर डालें तो निवेश के मामले में कर्नाटक अव्वल है।
- इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और हरियाणा का स्थान आता है।
- इसका एक बड़ा कारण यह है कि इन राज्यों के बड़े शहरों जैसे-बंगलुरु, मंबई और गुरुग्राम ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct Investment) को आकर्षित किया है।
- भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य जैसे बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा द्वारा प्राप्त किए गए अंक से पता चलता है कि इन राज्यों को नवाचार की दिशा में उच्च निवेश की विशेष आवश्यकता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों की बात करें तो आश्चर्यजनक रूप से मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य निवेश की दृष्टि से अनुकूल हैं, जबकि केन्द्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ने निवेश के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही दिल्ली ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण अच्छा प्रदर्शन किया है।
- गौरतलब है कि कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि आश्चर्य इस बात का है कि लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर निवेश के संबंध में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्षद्वीप और उत्तर-पूर्व के इन राज्यों ने उच्च शिक्षा पर महत्वपूर्ण राशि खर्च की है। साथ ही ये राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

3. 'कुशल श्रमिक' के मानक पर उच्चतम व निम्नतम प्रदर्शन करने वाले राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

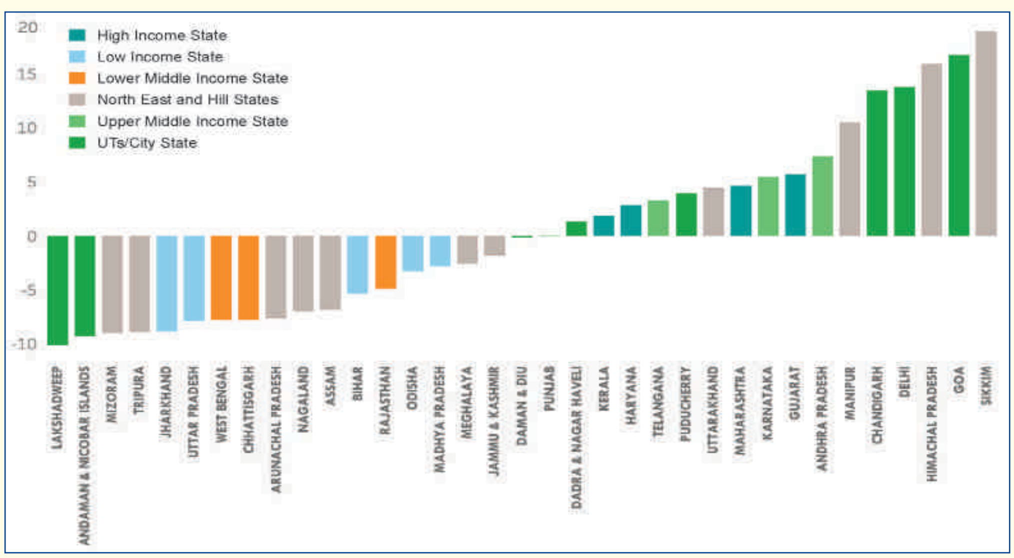

- इस स्तंभ में एक राज्य द्वारा प्राप्त उच्चतम स्कोर 35.24 है। जब हम मानव पूँजी के उच्च स्कोर (74.96) की तुलना कुशल श्रमिक (Knowledge workers Piller) से करते हैं तो पाते हैं कि भारत पर्याप्त मात्रा में स्नातक तो पैदा कर रहा है, मगर उन स्नातकों को ज्ञान-गहन गतिविधियों में नियोजित करने में विफल रहा है।
- इसका मतलब यह हो सकता है कि ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं या फिर स्नातक रोजगार योग्य नहीं हैं।
- औसतन भारत में प्रति 10 लाख आबादी में अनुसंधान एवं विकास (Research and development) करने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। इसके अलावा आर एण्ड डी (R & D) निजी संस्थानों द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशालाओं से आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि निजी प्रयोगशालाओं के अनुपात में सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशालाएँ काफी कम मात्रा में हैं। इसलिए देश के राज्यों को इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
- राज्यवार प्रदर्शन पर गौर करें तो पाएंगे कि छोटे राज्य आर एण्ड डी (R&D) के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- यह भी आश्चर्य की बात है कि सिक्किम, गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य अनुसंधान एवं विकास में बेहतर कार्य कर रहे हैं।

4. 'व्यावसायिक वातावरण' के मानक पर उच्चतम व निम्नतम प्रदर्शन करने वाले राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- व्यावसायिक वातावरण के मामले में शीर्ष तीन राज्य-गोवा, दिल्ली और तमिलनाडु हैं। इन राज्यों का स्कोर क्रमशः 52, 42 और 37 है। इन राज्यों में व्यवसायिक वातावरण नवाचार के लिए अनुकूल है।
- गोवा ने व्यावसायिक वातावरण का माहौल बेहतर ढंग से बना रखा है, जिसमें इंटरनेट की उपलब्धता, औद्योगिक समूह इनक्यूबेटर्स (Incubators) की उपस्थिति आदि शामिल हैं।

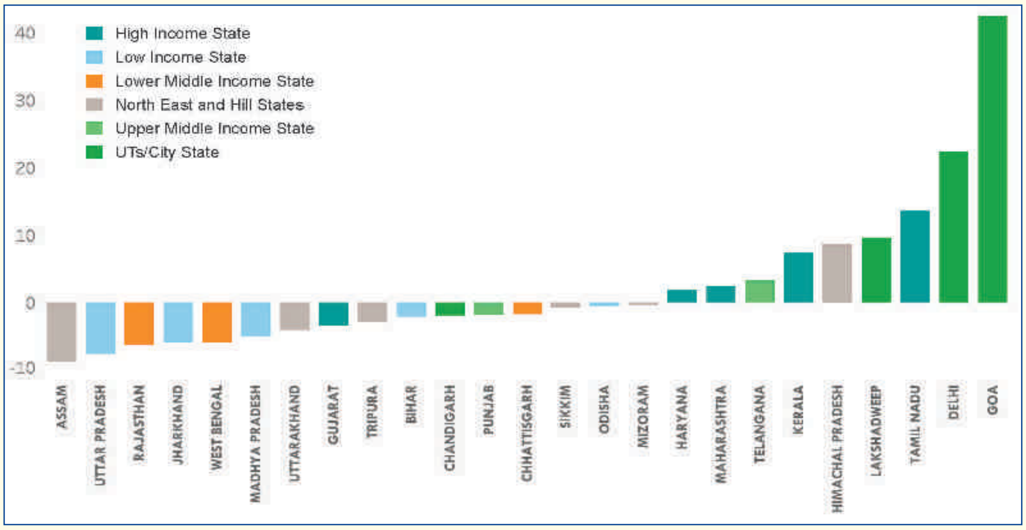

- दिल्ली ने व्यावसायिक वातावरण का माहौल सुचारू रूप से बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ सर्वाधिक इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराए हैं।
- तमिलनाडु का प्रदर्शन नवाचार सूचकांक के सभी पैमानों पर बेहतर रहा है। तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्य कच्चे माल को उत्पादों (Inputs Into Output) में बदलने के मामले में शीर्ष राज्य हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो ये तीन राज्य न केवल उच्च स्कोर प्राप्त किए हुए हैं बल्कि तीन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ये शीर्ष पर हैं।
- अन्य सभी क्षेत्रों के पूर्ण स्कोर 30 से नीचे हैं, हालांकि यह बहुत उत्साहजनक है कि कम स्कोर वाले क्षेत्रों में व्यवसाय कार्यान्वयन स्कोर करने में आसानी होती है।
- इससे यह प्रतिबिंबित होता है कि व्यवसाय के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सुझाई गई नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।
- व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराने में लक्षद्वीप, केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य अग्रणी भूमिका तो निभा ही रहे हैं, साथ ही ये अन्य राज्यों को उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं।

5. 'सुरक्षा और वैधनिक व्यवस्था' के मानक पर उच्चतम व निम्नतम प्रदर्शन करने वाले राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- सुरक्षा और वैधानिक व्यवस्था के मामले में तीन राज्यों- सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चण्डीगढ़ ने पचास से अधिक स्कोर किया है।
- गौरतलब है कि कई प्रमुख राज्यों ने 40 से अधिक स्कोर नहीं किया है। इन सभी राज्यों के स्कोर दर्शाते हैं कि एक सुरक्षित और वैधानिक व्यवस्था परिदृश्य इन राज्यों के लिए चुनौती बना हुआ है।

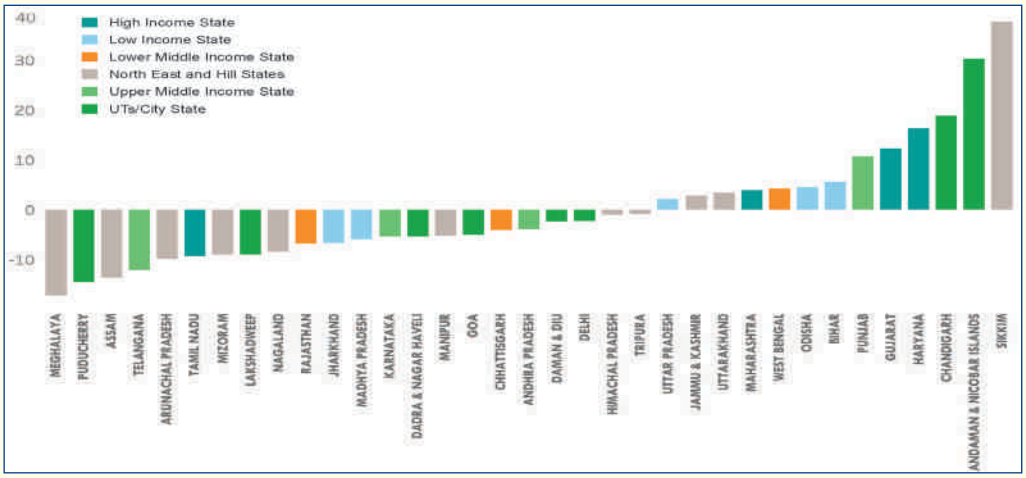

- साथ ही भारतीय समाज देश के कानून व्यवस्था को समझने और उसके क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियों का सामना करता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, जो कारोबारी माहौल के लिए शीर्ष तीन राज्य हैं। वे सुरक्षा और वैधानिक व्यवस्था के क्षेत्र में प्रमुख राज्यों में सबसे खराब स्थिति पर हैं।
- इस प्रकार कहा जा सकता है कि विकसित या अमीर राज्य अपने प्रदर्शन पर खरा नहीं उतर रहे हैं, हालांकि सापेक्ष परिणाम बताते हैं कि तीन उच्च आय वाले राज्य-हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर-पूर्वी राज्यों से अन्य राज्य सबक ले सकते हैं, जहाँ केवल तीन प्रतिशत अदालती मामले लंबित हैं, जबकि देश में यह औसत 28 प्रतिशत है।

6. 'नॉलेज आउटपुट' के मानक पर उच्चतम व निम्नतम प्रदर्शन करने वाले राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- ज्ञान उत्पादन (Knowledge output) में 0.08 से 72.2 तक पैमाने की भिन्नता पहली नजर में राज्यों के प्रदर्शन के बीच बड़े अंतर को दर्शाती है। लेकिन मानक विचलन बताता है कि राज्यों के बीच वास्तव में इतनी बड़ी भिन्नता नहीं है।
- उदाहरण के लिए दिल्ली ने नॉलेज आउटपुट (Knowledge output) के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

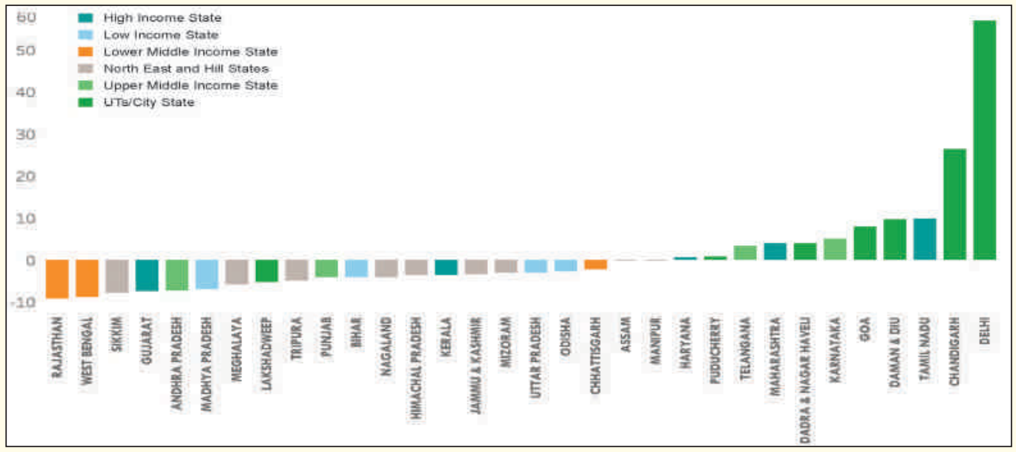

- जिसमें इसका स्कोर 72.2 है, जबकि चंडीगढ़ जिसने द्वितीय स्थान हासिल किया हैं, स्कोर 36.42 है, जो बहुत बड़े अंतर को नहीं दर्शाता।
- अग्रणी राज्य जैसे तमिलनाडु ने भी 30.22 अंक अर्जित किए हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो तमिलनाडु जो एक अग्रणी राज्य है, का स्कोर 30.22 है। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क जैसी चीजों पर अधिकांश आवेदन फॉर्म दिल्ली से भरे गए होंगे, जिससे इन दोनों राज्यों के स्कोर में अंतर दिखाई देता है। नॉलेज आउटपुट के मामले में भारत के दक्षिणी राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- बड़े राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना शीर्ष चार स्थानों (नवाचार सूचकांक के) पर काबिज हैं। केरल में सबसे अधिक मौलिक नवाचार (कुल संख्या के मामले में) हुए हैं, जबकि मणिपुर प्रति व्यक्ति मौलिक नवाचार (Per Capita Grassroot Innovations) के मामले में शीर्ष पर है। दिल्ली और भारत के दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन यह बताता है कि यहाँ पर उच्च मात्रा में शोधकर्त्ता और अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाओं की पर्याप्त संख्या है। तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की बात करें तो ये दोनों राज्य नॉलेज आउटपुट के प्रदर्शन के मानकों के विपरीत हैं, जहाँ आंध्र प्रदेश ने नवाचार के सभी मोर्चे पर निराश किया है, वहीं तेलंगाना ने इन सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

7. 'ज्ञान प्रसार' के मानक पर उच्चतम व निम्नतम प्रदर्शन करने वाले राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में राज्यों के बीच जिस तरह की भिन्नता देखी गई हैं, उसे दो प्रकार के आंकडों से समझा जा सकता है। पहले प्रकार के आँकड़े की बात करें तो 36 राज्यों में से 27 राज्यों का स्कोर 15 से नीचे है, जबकि दूसरा आंकड़ा बताता है कि शीर्ष 9 राज्यों का स्कोर 16 से 67 के बीच है। 27 राज्यों द्वारा प्राप्त कम स्कोर को आईसीटी (Information and Communication Technology Service export) के निर्यात के माध्यम से समझाया गया है, अर्थात इन राज्यों का आईसीटी के क्षेत्र में योगदान कम है।

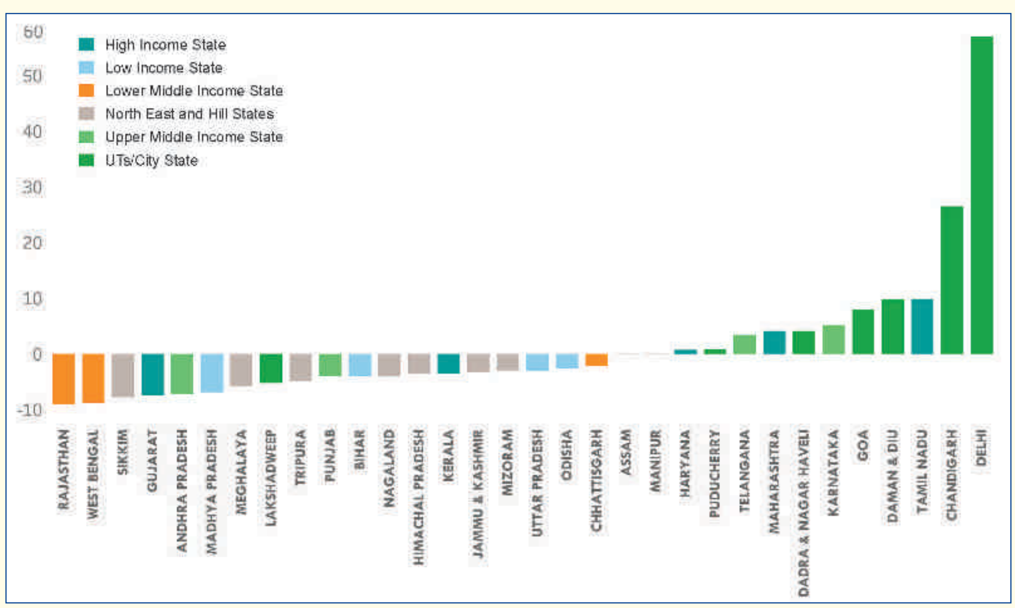

- देश के केवल 9 राज्य ऐसे हैं, जो 97 प्रतिशत आईसीटी का निर्यात कर रहे हैं। इन राज्यों में शामिल हैं- कर्नाटक (40%), महाराष्ट्र (19%), तेलंगाना (13%), तमिलनाडु (9%), हरियाणा (5%), उत्तर प्रदेश (4%), पश्चिम बंगाल (2%) और केरल (1%)। इस प्रकार आईसीटी का क्षेत्र इन राज्यों को अग्रणी बनाता है। इसके अलावा नॉलेज आउटपुट और ज्ञान प्रसार (Knowledge Diffusion) के क्षेत्र में सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ से काफी उम्मीद है। हालांकि इन क्षेत्रों में से अधिकांश या तो एक से छोटे से अंतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।
- यह आश्चर्य की बात है कि दो भिन्न आय वाले राज्य-उत्तरप्रदेश और ओडिशा इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राज्य उन राज्यों के लिए रोल-मॉडल हो सकते हैं कि कैसे संसाधनों का अधिकतम कुशलता से उपयोग किया जा सकता है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है

परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

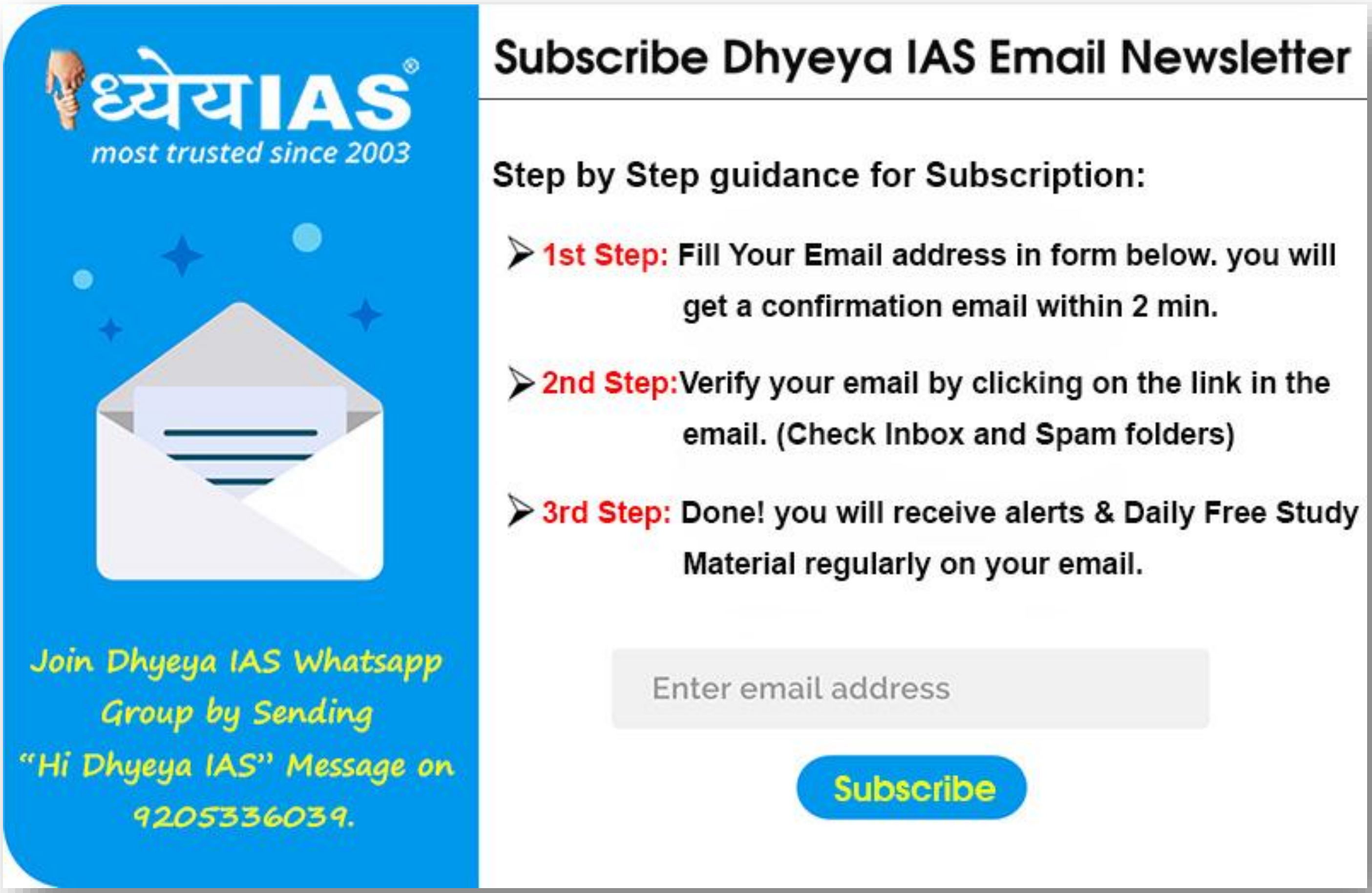

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400